

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj)**

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

चुनाव पद्धतियाँ

और
जन-सत्ता

भूमिका लेखक—
आचार्य नरेन्द्र देव, ऐम० एल० ए०

लेखक
विजयसिंह "पथिक"

Herbert College Library,

KOTAH.

Class No ¹³⁵ *H 324~~1~~2*

Book No *N 9544*

Accession No *9544* ...

2000-10-40

चुनाव पद्धतियां

और

जन-सत्ता

भूमिका लेखक

आचार्य नरेन्द्रदेव एम० एल० ए०

सभापति अखिल भारतीय किसान सभा

और कांग्रेस समाजवादी वल यू० पी०



लेखक—

विजयसिंह "पथिक" सम्पादक "नवसन्देश"



प्रथमवार
२०००

सन १९३६ ई०

मूल्य
१। ५०

प्रकाशक—
'नवसन्देश' ग्रन्थ रत्नमाला
लोहामण्टी, आगरा ।



मुद्रक—
राधारमन अग्रवाल
दी मॉडर्न प्रेस, आगरा ।

भूमिका

श्रीविजयासिंहजी पथिक एक बहुत पुराने राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं। इन्होंने राजस्थान के देशी राज्या की प्रजा की बहुत बड़ी सेवा की है और राष्ट्रीय हलचला में निरन्तर भाग लेते हैं। यह एक सफल पत्रकार हैं। इस समय 'नवसन्देश' नामक हिन्दी साप्ताहिक पत्र का कुरालता के साथ सम्पादन कर रहे हैं। इनकी लेखन-शैली बड़ी रोचक और सुगम है। यह दूरूह विषयों का भी विवेचन बड़ी सुलभ रीति से करते हैं।

प्रस्तुत पुस्तक में प्रचलित निर्वाचन पद्धतियाँ का विशद वर्णन और उनके गुण-दोषों का विस्तार से विवेचन किया गया है। वर्तमान युग का लोकतन्त्र-शासन असफल सिद्ध हुआ है। सच्चा लोकतन्त्र क्या है और किस प्रकार जनता का वास्तविक अधिकार शासन-यन्त्र पर स्थापित हो सकता है, इन गभीर प्रश्नों को लेकर विद्वानों में विवाद चल रहा है। प्रचलित लोकतन्त्र की असफलता देख कर बहुतों का लोकतन्त्र पर से विश्वास भी उठता जाता है। ऐसी अवस्था में समाज का कल्याण चाहने वाले चिन्ताशील कमियों का कर्तव्य है कि वे इन सारगर्भित प्रश्नों पर उचित विचार करें। जो लोग लोकतन्त्र के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं उनके सामने भी यह

(व)

जटिल प्रश्न है कि किस प्रकार की निर्वाचन पद्धति को प्रचलित कर जनमत्ता की साम्यविक प्रतिष्ठा हो सकती है ।

इन विविध विषयों पर प्रस्तुत पुस्तक में प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है । लेखक के विचारों से कोई पूर्णतया सहमत हों या न हों, इनमें मन्देह नहीं कि पुस्तक बहुत अच्छे ढंग में लिखी गई है और मनम्या के प्रत्येक पहलू पर भली प्रकार विचार किया गया है । पुस्तक सामयिक है और मुझे पूरी आशा है कि हिन्दी पाठक-समाज पधिकारी की पुस्तक में लाभ उठावेगा ।

विनीत—

ता० १६-५-३६ ई०

नरेन्द्रदेव (आचार्य)

प्राक्कथन

आजकल हमारे देश में चुनावों का महत्व काफी बढ़ गया है। कांग्रेस के हाथ में सत्ता आने के बाद से तो यह हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक मुख्य भाग बन गया है। देश व्यापी दल मन्दिषा ने जहाँ देश के सार्वजनिक जीवन को बहुत नुक्सान पहुँचाया है, वहाँ इस रुचि को बढ़ाने में काफी मदद भी दी है।

कांग्रेस संगठन में पैदा हुई इस उथल-पुथल का प्रभाव दूसरे संगठनों पर भी पड़ा है। हिन्दू महासभा, मुस्लिम लीग, अहमद दल आदि अनेक संस्थाएँ जिनका ध्येय राजनैतिक है, अपने संगठन और विधानों को कांग्रेस की समानता पर लाने की कोशिशें कर रही हैं। प्रत्येक की चेष्टा है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आए हुए समूह और व्यक्ति उसकी श्रुतियों के कारण, उस में अलग न हो जायें।

यही हालत भिन्न-भिन्न वर्गों के संगठनों की है। पूँजीपति वर्ग, श्रमींदार वर्ग, राजाओं का वर्ग आदि सभी के संगठन इस धूल के शिखर हो गए हैं। सब को अपने अपने संगठनों को मजबूत और मुख्यवस्था बनाने की धुन सवार हो गई है।

कारण स्पष्ट हैं—

अब तक देश की मार्बजनिक संस्थाओं, मुख्यतः कांग्रेस के मामले अंग्रेजी साम्राज्यवाद में लड़ने का कार्यक्रम था। स्वभावतः उनका पुरस्कार दमन और कठिनाइयाँ थीं। उनमें केवल उन ही लोगों के लिये आकर्षण था, जो या तो ममन्दार होने के साथ माहमी और दूरदर्शी भी थे, या अपनी धुन के पगल और भावुक। उनके कान का दावरा भी बहुत मंजुचित— प्रायः शहरों की नीमा तक ही था।

परन्तु आज स्थिति सर्वथा दूसरी है। आज एक ओर कांग्रेस के हाथ में शामन मत्ता का काफी भाग है। व्यवस्था-पिकाओं के हाथों में कानून बनाने की शक्ति है। स्यूनिर्मिपलिटिडियों विन्ट्रिक्ट बोर्डों आदि के हाथों में स्थानीय शामन प्रबन्ध के काफी अधिकार हैं। दूसरी ओर उनमें हर प्रकार के—जानीय, घार्मिक, वर्गीय—नंगटनों को अपने प्रतिनिधि भेजने का प्रवकाश है।

उनके अतिरिक्त पहले देश में राजनैतिक ज्ञान के छेददार बुद्ध गिने चुने आदमी थे। माघारण जनता के मनान ही मध्यम वर्ग भी राजनैतिक ज्ञान में कोरा था। नवागिदार काफी मंजुचित था ही। साथ ही कांग्रेस ने भी जनता को और युवकों को इन संस्थाओं के सम्पर्क में दूर रक्खा। स्वभावतः कांग्रेस के दम रस्त्र ने राष्ट्रीय भारत के लिये बड़ी क्लान किया, जो किसी भी समूह में व्यक्तियों की चरित्र रत्ता के लिये समान के नैतिक बन्धन करते हैं। उन में से कमशोर लोग भी इन बन्धनों के कारण अपनी कमशोरियों पर अंकुश रखने को विवश हुए और इस प्रकार, कम से कम ऊपर में, हमारी मेना अनुशामन-

युक्त बनी रही। इस सम्बन्ध में 'विहार प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी' ने जो गत वर्ष, 'कांग्रेस में आधुनिक गन्दगियों' की जाँच करने को एक कमेटी नियुक्त की थी, उसके निष्पक्ष ध्यान देने योग्य हैं।
 एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है—

“हम लोगों ने कांग्रेस और गवर्नर्स की जाँच की और उन त्रुटियों के कुछ स्थानों को जाँच देना जो हमारे माध्यम सहयोग करने को तैयार थे। और तब हमने अपने निर्णय लिखे, जिन्हें हम नीचे दे रहे हैं।

अचानक विस्फोट—

लोगों की निम्नतम दुर्भावनाओं के एक ही बार कूट निरालने का क्या कारण है? कांग्रेस चुनाव में हमारे पहले इतने व्यापक रूप में ऐसी उठनाइयाँ नहीं उठी थीं। यह कैसे हुआ कि लोगों में अनायास यह झुंझा पैदा हुई कि किसी भी हालत में कांग्रेस की समस्याओं पर हत्या किया जाय? कांग्रेस बहुत दूर नहीं है। जब तक कांग्रेस एक युद्ध करने वाली संस्था थी, वह नैतिकता की ऊँची मंजर पर काम कर रही थी। गांधी जी के शब्दों में—यह एक लड़ाई पर जाने वाली फौज की तरह थी, जो बड़े नैतिक अनुशासन का अनुसरण करती है। जब वह एक सामान्य दुश्मन से नहीं लड़ रही थी, उस समय भी वह मेरा ही भावना में उद्भूत थी और इसलिए वह चुपचाप कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रमों को ढोए जा रही थी। एक आदर्श, सत्य और अहिंसा में विश्वास द्वारा प्रेरणा पाने की और यद्यपि हम उच्च आदर्शों को बहुतना उठाने या, फिर भी उनको जहाँ तक सम्भव था, ईमानदारी से कार्यान्वित करने की कोशिश की जाती थी। कमसे-कम उन आदर्शों में लोग बहुत दूर नहीं हट जाते थे। ऐसा हम लिखें, क्योंकि हम

समझते हैं, तब उनके सामने कोई भौतिक प्रलोभन नहीं थे और केवल वे ही लोग चुनाव में खड़े होते थे जो स्वार्थानता के कार्य में लगे थे और कॉंग्रेस के मिद्धान्तों को मानते थे। और इनमें सिर्फ इतने ही लाभ की वे कल्पना कर सकते थे कि इससे उनका आत्म-संतोष होता तथा अपने मायियों को नजर में उँचे उठते।

कांग्रेस ने जब मे मन्त्रित्व ग्रहण किया, तब मे लोगों के रास्ते में बड़े-बड़े प्रलोभन आ खड़े हुए। जो लोग इसकी हिमायत करते थे. उन लोगों ने यह मोच रखा था कि इसके द्वारा सेवा और त्याग के बहुत से द्वार खुल जाते हैं। हम अपनी प्राप्ति की हुई न्यति को हट कर लेंगे और साथ ही न्वरान्य की लड़ाई को उपरत बनायेंगे। हममें मन्देह नहीं कि हमने कुछ महूलियनों गरीबों को दीं। लेकिन हमने अवसरवादियों और राजनीतिक समय-मेयियों के लिए बड़े आकर्षण का काम किया। हमने कुछ पुराने कार्यकर्ताओं को भी पतित कर दिया, जो मोचने लगे कि यह उनकी अनीत की मेराओं के पुरस्कार का समय है। वे भी प्राप्ति की हुई लूट में अपना हिस्सा खोजने लगे और हम धान के लिए ध्वेनी दिग्गई जाने लगी कि कहीं कोई बिना अपने हिस्से के ही न रह जाय। स्वादी, जो ब्रिटिश-साम्राज्यशाही के विरुद्ध अहिंसात्मक विद्रोह की प्रतीक थी, मेरा रा बंज और मन्व-अहिंसा की प्रतिनिधि थी, अब हमके पहिग्नेवालों के लिए नाकरी की मिस्कारिण का काम करने लगी। विभिन्न कॉंग्रेस कमेटियों न्वार्थानता के अङ्ग बनने के रजाय मन्त्रियों के पास दरम्पान्तें भेजने की माघन बन गईं। हर तरह के लोगों में कांग्रेस-मन्था पर ग्दडा करने के व्यापक खयाल पैदा हुए। नाकि म्वार्थ और लाभ की जगहें अपने और अपने दोन्नों और

नातेदारों के लिए प्राप्त की जा सकें और स्थानीय बोर्ड आदि को हाथों में किया जा सके ।”

जनता में सन्देह—

इस प्रकार जहाँ देश के पुराने संस्कारों में जनता का श्रीगणेश हुआ है, वहाँ दूसरी ओर इतने दिन के अनुभवों के कारण जनता भी पहले की तरह सरल-विरासिनी नहीं रही है। हर दफा हर सत्ता में, उसकी भलाई करने के नाम पर चुने जाने वालों ने, अपने आचरणों से उसमें यह भावना पैदा कर दी है कि वर्तमान समय में प्रत्येक वर्ग अपना प्रतिनिधित्व स्वयं ही कर सकता है।

दूसरी ओर जिन लोगों के हाथों में अब तक ये अधिकार रहे हैं या अब आ गए हैं, उनमें उपरोक्त परिस्थितियों के कारण अपने स्थानों से मोह पैदा हो गया है, और इसलिये वे प्रत्येक उपाय में अन्य लोगों और अपने पुराने साथियों तक को आगे आने देने से रोकने में कुछ उठा नहीं रखते। यहाँ तक कि अब हम बीमारी ने कितने ही बड़े २ नेताओं को भी दूधोच लिया है।

संक्षेपतः इस स्थिति को बनाने वाले दलों को नीचे लिखे भागों में बाँटा जा सकता है —

- १—वे लोग जो हमेशा सत्ता के साथ रह कर उस से लाभ उठाते रहे हैं और इस कला में दक्ष हैं।
- २—वे वर्ग, विशेषतः पूँजीपति व जमींदार आदि—जिन्हें इंग्लैंड आदि की तरह यहाँ पूँजीवादी शासन स्थापित करने की धुन है और जो यहाँ के तरीकों में परिचित हैं।

३—वे काप्रेम कार्यकर्ता, जो अपनी सेवाओं के बदले, हम समय लाभ उठाना अपना हक समझते हैं।

४—मध्यम श्रेणी के अपसरकारी, आदर्शहीन और माधन रहित लोग, जिनसे सब दलों में काफी मग्या है।

म्यभारत इस स्थिति में देश के उदुत में विचारशील

मस्तिष्क घबरा उठे हैं। "हैं देश का भविष्य मरुत मय दिग्गड्डे देने लगा है। वे देख रहे हैं कि देश को सुमगठित कर लेने का स्वर्ण अवसर न्यर्य खोया जा रहा है। राष्ट्र-निर्माणकारी शक्तियाँ अपने ही विगठन में लग रही हैं और शत्रु हमारी इस दशा पर प्रसन्न हो रहा है। वे इस स्थिति का अन्त कर देने को "सुर" हैं, परन्तु जिन शक्तिमान दैत्यों को "न्होंने अपनी महा प्रता के लिये जाग्रत और मगठित किया था, वे "त्रात "न्होंने के सामने मुँह फाड़े रखे हैं। मात्र ही चूँकि "नके अपने ही मगठन के कील-मुर्ख काफी मग्या में खराब हो गए हैं और "नके आसुरी प्रभाव में हैं, अतः वे इस प्रवाद को खोलने का भी गेडे कारगर "पात्र नहीं निकाल पा रहे हैं।

सुख्य कारण—

परन्तु विचार नष्टि में देखा जाय तो हममें अन्त्याभावितता कुछ भी नहीं है। न ही विशेष घबहाने की जरूरत है। हमारे राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं और अन्य वर्गों के चरित्र में जो दुर्बलता इस समय दिग्गड्डे दे रही है, वह सोई नई या आन पैदा हुई वस्तु नहीं है। हजारों वर्षों की पराधीनता ने हमें हमारी नम नम में पहले ही में भर रमगा था। केवल परिस्थितियों के कारण "मरे मुलने खेलने के मार्ग धन्ड थे। इस समय अमात्रयानता इतनी ही हुई कि इस स्थिति के ग्यत्र होने का अन्दाजा करने

पहले से उसके कुछ न्याय नहीं मोचे गए। शायद रिस्वकी, और देशकी बदलती हुई परिस्थितिया भी इस गलती के लिये कारी जिम्मेदार हैं। शायद इसी सतरे का अनुमान करके बहुत से लोगों ने पद ग्रहण का विरोध किया था। वैसे भी तब कभी समाज या शासन की व्यवस्था में कोई नया और व्यापक परिवर्तन होता है तब कुछ समय तब अव्यवस्था और गड़बड़ी अनिवार्य रूप से होती ही है। प्रत्येक मानि के नाद अच्छे में अच्छे सिद्धान्तों का कुछ समय तक दुरुपयोग होता है। किन्तु यदि परिस्थितिया की मांग के अनुसार जनता को विचार और ज्ञान दिया जाय, तो कुछ ही समय में स्थिति बदल जाती है। गड़बड़ी पैदा करने वाली शक्तियाँ के मीड़ा मांग रुद्ध हो जाते हैं। कुछ अनुभवों में और कुछ जनता के मनग हो जाने से, फिर ठीक रास्ते पर आने को मजबूर होता पड़ता है।

रूस की लाल मान्ति के बाद 'समाजवादी सिद्धान्तों, तब का दुरुपयोग हो गया था। स्त्रियाँ के समानाधिकार और स्वातंत्र्य का रूप 'व्यवस्थित अनेकन चीजन' का सा बना डालने की कोशिश की गई थी। कुछ समय तब यह गड़बड़ी महामना लैंगिन के विरोध करने पर भी चलती रही। परन्तु तब जनता में कभी जाति के सम्यन्ध में आवश्यक विचार पटुप गए, तब सब गड़बड़ी शान्त हो गई जब उसका स्थान साम्यिक और सत्य सत्यता ने ले लिया। यही यहाँ भी हो सक्ता है, वर्राँ कि हम अपना की और अपनी जुनियाँ और चुराईया की भी सुली आलोचना, और जरूरत हो, तो तब विरोध करने को भी तैयार हों।

क्योंकि आखिर इन सब गड़बड़ा का मूल कारण तो जनता का राजनीतिक अज्ञान ही है। यदि वह मनग हो, उसमें अपने

हितादिन और गानन व्यवस्था के मुख्य प्रकारों के गुण दोषों का ज्ञान हो तो फिर अवसरवादियों और स्वार्थियों को सचेष्ट गति का दुष्प्रयोग करने का साहस ही न हो। साहस करें तो भी उन्हें सफलता न हो।

एक और कारण—

एक और बात ध्यान में रखने योग्य है। इस समय देश का ज्ञान और सन्दर्भ वर्ग भी इन चुनारों में काफी विलम्बों से रहा है। उन मनुष्यों के मुख्यतः हमने स्वर ही राजनीति की ओर आकर्षित भी किया है और बाल्य में इन ही का नाम रेंग है।

इनमें गुरु नहीं कि आज के समुद्र पटले में अधिक समझदार हैं। पहले वे भीतर जातों में आकर और नमस्कृत्यवादी के खदान में पड़ रही लालच आदि के फँस में पड़ कर अपने मत, अपने नालिक के ज्ञान बाने से ही डे डालने थे। अब उनमें से अधिकांश में इतना विवेक और साहस आ गया है कि वे कम से कम नालिक वर्ग के चक्कर में नहीं आते। किन्तु ट्राविटी-प्राप्त नाम द्वारा और दूसरे वर्गों ने अब भी वे योना न्या मज्जे हैं और उन्हें बद दिग जता है।

इसके मुख्य कारण तो ही हैं। प्रथम तो यह कि वे अपने मत का पूरा मूल्य नहीं जानते। दूसरे वे प्रचलित चुनार पट विगों और एक सदुपयोग-दुष्प्रयोग में सर्वथा अशक्ति हैं। तब इस अज्ञान का लान जा कर ही प्रायः उनके विगों में उन्हें अमल करने पड़े हैं।

किन्तु बात यही मनाय नहीं होती। जगत् वर्गों के विगों से पहले उन्हें अमल नाने हैं और तब वे स अमलना से

पैदा हुई निराशा से प्रभावित होते हैं, अथवा उनका चुनाव हुआ प्रतिनिधि उनके हितों के विपरीत कुछ कहता या करता है, तब वे उन्हें यह समझाने की चेष्टा करते हैं कि "जनसत्ता या प्रजा सत्ता अव्यावहारिक वस्तुएँ हैं। इनसे शरीर कोई लाभ नहीं उठा सकते। शासन की कला उनके लिये रची ही नहीं गई है। इसमें तो एक के बजाय अनेक मालिक बन जाते हैं—किस किस को गुला करके काम बना सकते हो?" आदि आदि।

इस प्रकार उनका प्रयत्न यह होता है कि वे जनता के मन में जनतन्त्रात्मक शासन पद्धति और प्रतिनिधि सस्थाओं के प्रति घृणा और अविश्वास पैदा कर दें। स्वभावतः असफलता से निराशा और विपत्तियों की कूट धालों से चिढ़े हुए हृदयों पर ऐसे प्रचार का असर होने लगता है। साधारण मनुष्यों की तो बात दूर, हमने अनेक कार्यकर्ताओं पर ऐसी स्थितियों और बातों का प्रभाव होते देखा है।

और यह तो स्पष्ट ही है कि ऐसी धीझ को निर्माण पढ़ने देना न केवल देश के साथ प्रत्युत जनतन्त्र के सिद्धान्त के प्रति भी अभिद्रोह करना है। यदि हम शासन में जनतन्त्रवादी हैं और अपने देश को उसके लिये तैयार करना चाहते हैं, तो ऐसी बातों का तत्काल प्रतिकार करना हमारा कर्तव्य है। भोली और भावुक जनता न तो जनतन्त्र चला सकती है, न जनतन्त्रात्मक व्यवस्थाओं से लाभ उठा सकती है। यह हमेशा किसी न किसी व्यक्ति या वर्ग से ठगी जाती रहेगी। अतः जनतन्त्र का मार्ग परिष्कृत करने का इसके सिवाय कोई 'राज मार्ग' नहीं है कि साधारण जनता को राजनीति के व्यावहारिक नियमों की शिक्षा दी जाय। और यह सब तक नहीं हो सकता, जब तक कि चुनाव पद्धतियों के उद्देश्य, उनके सफल

होने के कारण और साधन तथा उनके अमफल होने के रहस्य सर्व-साधारण को न उठाए जाय। एक ओर साहित्य द्वारा ऐसे ज्ञान का प्रचार न किया जाय और दूसरी ओर राष्ट्रीय समस्याओं को उनके स्कूल न उनाया जाय।

किंतु दुर्भाग्य से हमारे देश के प्रभासक ऐसी पुस्तकों को छूते ही नहीं। अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में उन विषयों पर काफी साहित्य है। परन्तु वह इतना महंगा है कि साधारण व्यक्ति उससे लाभ नहीं उठा सकता। प्रस्तुत पुस्तक के लिये जरूरी मामूली एकत्र करने की ही हमें 300 रुपये से ऊपर के मूल्य का साहित्य देखना पड़ा। उस में शायद ही कोई ग्रंथ 20 शिलिंग से कम मूल्य का था।

यही अवस्था हमारी समस्याओं की है। हमारी राष्ट्रीय महासभा ने भी चुनाव पद्धति में एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति और अप्रत्यक्ष चुनाव को पसन्द किया है, जो काफी पेचीदा तो है ही, जनसाधारण के लिये अधिक उपयोगी भी नहीं है। आज कल कांग्रेस-संगठनों में प्रायः सदस्य बनाने और चुनाव लड़ने के अतिरिक्त कोई काम नहीं होता। ऐसे समय में यदि Proportional Representation अनुपातिक मतधिकार अथवा कोई दूसरी उपयोगी पद्धति के साथ रिफॉरेण्डम, रिकाल और इनीशियेटिव की पद्धतियों को स्वीकार कर व्यवहार में लाया जाता तो लोकमत क्षिती आसानी से जनतंत्र के लिये शिक्षित एवं तैयार हो जाता? इस समय चुनावों में पैदा हुई जन साधारण और भिन्न-२ वर्गों की अभिरुचि का, जिसे हम समय पर अनाच्छेदनीय आत्म समझा जा रहा है, किना अच्छा उपयोग होना? शायद हम इस साप में आशीर्वाद में परिवर्तित कर सकते। अस्तु,

उन तथा ऐसे ही विचारों से प्रेरित हो कर हमने इस पुस्तक को लिखने का साहस किया है और यदि यह इस उद्देश्य की पूर्ति में कुछ भी सहायक सिद्ध हो, तो हम अपना श्रम सफल समझेंगे ।

अन्त में हम उन लेखकों और मित्रों का सादर आभार मानते हैं, जिनके लिखे ग्रन्थों, सत्परामर्श और प्रोत्साहन से इस पुस्तक को लिखने में हमें मदद मिली है । इति—

नोट — इस पुस्तक में जर्मनी की चुनाव पद्धतियों का जहाँ जहाँ उल्लेख है, वहाँ वह 'नाज़ीवाद' स्थापित होने के पूर्व के 'जर्मन विधान' के आधार पर है ।

आगरा
१ जून १९३६ ई०

विजयसिंह पथिक



विषय-सूची



I

प्रजावाद की पुकार

विषय प्रवेश—राजमत्तावादियों के दौरे पेच—लोफ़तंत्र
कैसे असफल बनाया जाता है ?—एक प्रधान चालवासी—आज
के प्रजातन्त्र—क्या वे जनतंत्र हैं ? १—१२

II

आधुनिक मताधिकार

इंग्लैंड में जनता के प्रतिनिधित्व के लिए आन्दोलन—
दूसरा आन्दोलन—१८६६ की शान्ति—मजदूरों में जाग्रति—
दो व्यवस्थापिका सभाएँ—और चालवासीयों तथा परिणाम

१३—२७

III

चुनाव पद्धतियाँ

सुधार की आवश्यकता—एक मत पद्धति—द्वैध मत पद्धति
या मैजस्ट्रेट वेलट—एवासी हस्तान्तरित मत पद्धति—हस्तान्तरित
मत पद्धति—नियंत्रित मत पद्धति—संगत्यानुपातिक मतदान
पद्धति—इन सब पद्धतियों के विमर्श या इतिहास—इनके भिन्न
रूप—व्यावहारिक पद्धति, और आलोचना २६—४०

जनना की मत्ता

जनमत्ता और प्रतिनिधि मत्ता—अममानताओं का संघर्ष—
रिफ़ैरेंस अथवा अन्तिमस्वीकृतिपद्धति—रिफ़ैरेंस के
विनाश का इतिहास और आलोचना ... ४१-६६

सफलता की कुर्ज़ी

रिफ़ैरेंस के विरुद्ध आयुधियाँ और उनके उत्तर—इंग्लिश
शासन की न्याय्यता—धार्मिक और ज़ार्तीय मेद्मास—रिफ़ैरेंस
के मेद्मास—सरकारी कानूनों का संग्रहण एवं परिवर्तन—जनता के
साधारण संग्रहण—स्विट्ज़रलैंड में रिफ़ैरेंस पद्धति प्रचलित
होने पर कुछ परिणाम—अमेरिका की मनकंता ... ६९-८९

विधान-निर्माणधिकार (दो इनीशियेटिव)

व्यावहारिक रूप—फ़ारसुलेटेट इनीशियेटिव—जनरल इनी-
शियेटिव—दिले का इनीशियेटिव—नव लेने का समय—मक-
लता के मुख्य माधन—इनीशियेटिव की दरम्यान्—
आत्म निर्णय या ऑर्गेनिस्माट—व्यावहारिक पद्धति—न्युनि
का अन्तर—धार्मिक रूप—राज्य विस्तार का माधन—... ११३

पुनरावर्तन (रिकाल)

आवरणकता—शॉर्ट वेल्ड सिन्टन—व्यावहारिक रूप—रुम
की विशेषता—पुनरावर्तन के विरुद्ध इनीशियेटिव—न्यायाधीशों का
पुनरावर्तन—“निर्णय”—अन्यावर्तन—या मार्गजनिष्ठ अर्थ
... ११४-१२३

भारत में प्रचलित

चुनाव नियमावली

आवश्यकता—वर्तमान संकट—वास्तव में बुरा है क्या ?

निर्वाचन और निर्वाचक—साधारण मतदाता—परोक्ष निर्वाचन—प्रत्यक्ष निर्वाचन—निर्याचकसभ—धार्मिक निर्वाचकसभ—जातीय निर्वाचकसभ—व्यावसायिक निर्वाचकसभ—सम्मिलित निर्वाचकसभ—मरुतिन स्थान—वर्तमान निर्वाचकसभ ।

चुनाव नियमावली मतदाताओं की फहरिस्त—सरोधित निर्वाचक सूची—नामजदगी का पर्चा—कुछ याद रखने योग्य बातें—म्यूनिसिपल चुनावों में—जिला बोर्डों में—नामजदगी नामजदगी की जाँच—निबिरोध चुनाव—वापिसी—विशेष स्थिति में वापिसी ।

चुनाव—अनियमित रच कराना—अनमरों की अनियमितताएँ—नाजायन रार्न—हिमात्र की नियमितता—चुनाव केन्द्र (पोलिंग स्टेशन) के कुछ नियम—मतदान-पद्धति—दूसरी तथा तीसरी—पद्धति—कुछ अन्य अनियमितताएँ—घोषणापत्र—चुनाव संघी कार्य—कुछ आवश्यक सूचनाएँ ।

१२४—१२६

VII

भारत में प्रचलित एकरी हस्तान्तरित मत-पद्धति—रान्दों के अर्थ—रझा हुआ उम्मीदवार—अमित-मत-पत्र—गौण मत पत्र—मुख्य मत वा पहली वमन्दगी—मत गिनने की विधि—उदाहरण ।

१२७—१६८

ए-७८७७

प्रजावाद की पुकार

बालकृष्ण

विषय-प्रवेश



जकल दुनिया भर में प्रजावाद की लहर फैल रही है। जिधर देसो, जिस देस में जाओ, जहाँ के समाचारपत्र पढ़ो, सर्वत्र प्रजा का शासन स्थापित करने की उत्सुकता और इस सम्वन्ध में होने वाले प्रयत्नों की गैँज सुनाई देती है। प्रत्येक पढ़ा लिखा और पढ़े-

लिखा के ससर्ग में रहने वाला व्यक्ति प्रजावाद का मतवाला दिखाई देता है।

इतिहास के जानकारों के लिये इस सारी हल-चल में कोई नवीनता नहीं है। वे जानते हैं कि इस प्रहार की प्रगतियाँ प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप में चलती रही हैं। जब से प्रजा के हाथ से शासनाधिकार वगैँ और व्यक्तियों के हाथों में गये हैं, तब ही से इन प्रयत्नों का इतिहास भी बरामद मिलता है। इसमें सन्देह नहीं कि राज्यशक्तियों और सत्तालोलुपों ने प्रजा के हृदय में उन स्वर्ण-दिवसों की स्मृति को धो खानने का भरसक प्रयत्न किया है। वे उसमें सफल भी हुए हैं। हजारों वर्षों तक वे ईश्वर के प्रतिनिधि भी बने रह चुके हैं। परन्तु फिर भी यह है,

भावना और ये प्रगतियाँ किसी भी युग में मर्यादा नहीं हुईं। वे बराबर भिन्न-भिन्न रूपों में उद्भूत होती रही हैं।

कारण

इसके कारण स्पष्ट हैं। जिनमें शान्त और शान्ति दोनों ही मनुष्य हैं। सबकी शरीर-रचना और प्राकृतिक शक्तियाँ भी प्रायः समान ही होती हैं। आज भी हम देखते हैं कि अचमर और माघन मिलने पर शरीर में शरीर और पिढ़ड़े में पिढ़ड़े मनुष्यों के व्यक्ति अनेक अद्वितीय गिने जानेवाले, मूर्धन्य और ईश्वर-पुत्रों से अधिक योग्य एवं विचक्षण हो निकलने हैं। यही क्यों, संसार के अधिकांश महापुरुष ऐसे ही व्यक्तियों में से निकले हैं। क्या प्राचीन काल के कृष्ण, व्यास, वाल्मीकि, क्राइस्ट और मुहम्मद आदि और क्या आधुनिक युग के कार्ल मार्क्स, लेनिन, हिटलर, सुमोलीनी आदि सब ऐसे ही वर्गों के व्यक्ति थे और हैं।

इन सब बातों ने यही प्रमाणित होता है कि मनुष्य-मात्र में स्वतन्त्रता और शान्त की शक्ति स्वाभाविक है। मानसिक विश्राम न होने से अथवा किसी के द्वारा इसके मार्ग रोक दिये जाने पर वह इस तथ्य और सिद्धान्त को मूल भले ही जाय। उसे यह भले ही विस्तृत याद न रहे कि किसी युग में उसके पूर्वज स्वयं ही शान्त-शक्ति बलाते थे और किसी के शान्त में रहना पशुता का चिह्न माना जाता था। उनका ही नहीं, भले ही वह व्यक्ति और ममूह हृदय में यह विश्राम करने लगा हो कि मेरा अधिकार, शान्त करना, शान्त के बारे में सोचना या उसमें हस्तक्षेप करना नहीं है। फिर भी आगे-पीछे वह शान्त के बारे में सोचने, उसमें हस्तक्षेप करने और फिर उसे धियान के प्रयत्न करना ही है। यह हमें याद है कि कभी

वह उसे धर्मरक्षा के नाम पर करता है, कभी जातिरक्षा के नाम पर, कभी देश-रक्षा के नाम पर और कभी केवल स्वायत्तता के नाम पर ।

और वास्तव में ये भिन्न-भिन्न रूप तो उस विस्मृति के आवरण के ही फल हैं । जोर तो मनुष्य की स्वाभाविक, शासन-यन्त्र को अपनी इच्छानुसार चलाने की, भावना ही भारती है । यही उसमें विद्रोहाग्नि प्रदीप्त करती है । परंतु चूंकि राज्यराज्या की कुशिक्षा के फल से वह उसका असली रूप को पहचानने में असमर्थ हो जाता है अथवा दूसरे स्वार्थी लोग उसे उसका दूसरा नाम रूप देते हैं, अब यह उसे वैसा ही मानने लगता है । अन्यथा धर्म के नाम पर या किसी सामाजिक प्रश्न के नाम पर कान्ति कराने या शासन विधान बदलवाने में और केवल स्वयं के लिये ऐसा करने में अन्तर ही क्या होता है ? मूल में दानों का अपनी इच्छानुसार शासन-यन्त्र को चलाना, है न ?

तात्पर्य यह कि यह मनुष्य का प्राकृतिक गुण और उनकी मनसे अधिक स्वाभाविक भावना है । यही कारण है कि मनुष्य के स्वयं उसे भूल जाने पर भी कृष्ण के वचन —

“ प्रकृतिस्त्वा नियोजयति ।”

के अनुसार प्रकृति स्वयं ही उन्हें शासन यन्त्र का स्वेच्छा-नुसार चलाने के लिये प्रेरित करती है एवं इसीलिये अपनी इच्छा के विरुद्ध होने वाले शासन से उसे स्वतः लाभ होता है ।

राजसत्तावादियों के दांव पेच

प्रश्न होता है कि यदि यही बात है, तो आज तो मुझे तौर पर ये प्रगतियों आसानी और स्वशासन के नाम पर चल रही हैं,

फिर क्या कारण है कि आज भी भिन्न-भिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रश्नों को लेकर लोगों को लड़ाया जाता है ? क्यों नहीं इन सबको एक ही लक्ष्य पर लाया जाता ? इस प्रश्न का उत्तर समझनेवाले के लिए बहुत मरन है । यह तो स्पष्ट ही है कि प्रत्येक देश की जनता की उस समय की और आज की स्थिति में आकाश पानाल का अन्तर है, जब कि वह जातियाँ Tribes की शक्ल में अपना शासन स्वयं करती थी । उस समय तक न तो लोगों में आजकी सी आर्थिक असमानता थी, न किसी वर्ग या दल विशेष को शासन करने का और दूसरों को लूट कर बड़े बनने का चस्का लगा था । न जनता अपने स्वशासन के अधिकार को भूलती थी, न आज की तरह हजारों वर्ष शासन-कार्य में अलग रख उसे अयोग्य बनाया गया था । आजकल की तरह पढ़ाई की परीक्षाएँ पास न करने पर भी व्यावहारिक शासन-शिक्षा की बदौलत उसका प्रत्येक व्यक्ति काफ़ी राजनीति-विद और समझदार होता था, और इस लिये किसी को उसके अधिकारों पर हाथ डालने वा उसे भ्रम में डाल अपना उल्लू मीधा करने का प्रयत्न करने का माहम ही न होता था ।

परन्तु आज की स्थिति मर्यादा दूमेरी है । आज उई वर्ग ऐसे हैं जो किसी समय शासन कर चुके हैं या कर रहे हैं, और इस लिये उन्हें शासन यंत्र को अपने हाथों में रखने का चस्का लगा हुआ है । इसी प्रकार कुछ पूंजीपति और मध्यम दर्जे के वर्ग ऐसे भी हैं, जो यद्यपि शासन नहीं कर चुके हैं, परन्तु या तो शासन वर्गों के साथी और महायुक्त रह चुके हैं, अथवा कोई उत्पादक कार्य न करके केवल बुद्धि के महारे उत्पादक ममूहों ही को भिन्न-भिन्न प्रकार ठगकर अपनी स्थिति ऊँची बनाए रखते हैं । और चूँकि शिक्षा आदि का लाभ भी आज ये ही वर्ग पा

रहे हैं, अतः इन ही में राजनैतिक बुद्धि है। यही कारण है कि ये दल प्रायः साधारण जनता के विरुद्ध आपस में मिल जाते हैं और उसके असन्तोष का उपयोग करने के लिये छोटे मोटे प्रश्नों को प्रधानता देकर उसे मार्ग ले लेते हैं। वे शिक्षा और बुद्धि का उपयोग आज लोगों का अज्ञानान्धकार से निकाल, प्रकाश में लाने के लिये नहीं, उनका अज्ञानान्धकार का और मचन बनाने के लिये करते हैं। वे यदि स्वायत्तता या स्वशासन के लिये भी उसका उपयोग लेते हैं और इस लिये यदि उन्हें जनता का स्पर्धीनता समझ के लिये आर्पित करना पड़ता है, तो वे उसका चित्र इतना पेशीदा बनाकर उसके सामने रखते हैं कि वह उसे कुछ समझ ही नहीं सकते। उसे दिखाया तो यह जाता है कि सब कुछ उसी के लिये किया जा रहा है, परन्तु शासन पद्धति ऐसी मांगी, स्वीकार की और बनाई जाती है कि व्यवहार में प्रचारी साधारण जनता का उसका कोई स्थान ही नहीं रहता। जनता के स्थान पर और उसके नाम पर ये लोग स्वयं ही उसके प्रशासन घन बैठते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक देश में भारी स्वराज्य आदि शक्तों की सर्वसाधारण की समझ में आने योग्य व्याख्या अन्त तक टाली जाती है।

एक प्रधान चालबाज़ी

जनता का उल्लू बनाने की ऐसी चालों में सबसे अधिक घातक चाल सब था जोट डेने की पद्धति की होती है। शासन में आधुनिक युग में इसी पर सब कुछ निर्भर भी है। यही कारण है कि घड़े-बड़े राजनैतिक मस्तिष्क इस पद्धति पर ही अपनी सबसे अधिक शक्ति लगाते आए हैं एवं यही कारण है कि इस पद्धति के इतिहास की अब तक बिजनी ही पुनरावृत्तियाँ हो चुकी हैं।

उदाहरण के लिये प्राचीन-काल के ऐसे असंख्य प्रमाण हैं कि तत्कालीन प्रजातंत्रों में प्रत्येक वालिग पुरुष, स्त्री को मताधिकार होता था और चुनाव प्रायः सदा प्रत्यक्ष होता था। परन्तु जब राज्य मत्ता की बुनियाद डालनेवाले मनु आदि ने शासन विधान बनाए तो उन्होंने चुने जाने वाले और चुननेवाले अर्थान् मतदाताओं की योग्यताएँ इस प्रकार स्थिर कीं कि उनके अनुसार सरीय या सरीयों के प्रतिनिधि शासन यंत्र के मंचालकों में प्रवेश ही न पा सकते थे। इस प्रकार उन्होंने एक वर्ग के प्रभुत्व की नींव डाल दी। मंचेप में यही प्राचीन प्रजावाद और राज्यवाद के मध्यकालीन संघर्ष के इतिहास का सार है। और फिर तो धीरे-धीरे ये वर्ग भी टुकड़े दे दे कर अलग कर दिये गए और “कण्टकेनैव कण्टकम्” की नीति पर एक वर्ग के विरुद्ध दूसरे का उपयोग कर क्रमशः सबको अधिकार विहीन कर स्वैच्छाचारी शासन के पैर जमा दिये गए। इस पर फिर जब कभी अमन्तोष अद्रम्य हो गया, तो उसी क्रम में थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व जनता को दे दिया गया और अग्रसर मिलते ही फिर उसे स्वार्थी राज्यवादियों एवं उनके बनाए हुए महात्माओं तथा धर्माचार्यों द्वारा छीन लिया गया।

आज के प्रजातंत्र

आज के प्रजावाद का इतिहास भी यही अथवा उन्ही पुराने इतिहास की पुनरावृत्ति है। उदाहरण के लिए प्रजावाद की व्याख्या में कहा जाता है कि :—

It is a Government of the people, by the people and for the people.

अर्थान् प्रजावाद या प्रजानंत्रीय शासन वही है, जिस पर

सारी प्रजा का अधिकार हो और जो प्रजा द्वारा प्रजा के लिये ही चलाया जाता हो ।

किन्तु व्यवहार में स्विटजरलैंड और रूस को छोड़कर शायद ही किसी देश के प्रजातंत्र में वास्तव में प्रजा का शासन कहा जा सकता है । इन देशों में वास्तविक प्रजा सत्ता न स्थापित करने के कारण भी वे ही बनाये जाते हैं, जो पहले के राज्यराजी बनाने आए हैं । आम तौर पर इस सम्बन्ध में दो दलीलें दी जाती हैं :—

१—यह कि इस प्रकार का शासन छोटे क्षेत्र में ही सम्भव है । किसी बड़े देश में यह रूप व्यावहारिक नहीं हो सकता ।

२—यह कि साधारण प्रजा का सीधा प्रतिनिधित्व होने में शासन और व्यवस्थापित सभाओं में योग्य आदमी नहीं पहुँचते और इस लिये शासन नीति कमजोर एवं दोष-युक्त बन जाती है ।

ये दलीलें अधिक बल के साथ और बहुत काल से दी जाती रही हैं और इसीलिये जो लोग बहुधा दूसरों ही के विचारों को लेकर युद्धिमान बनने के आदी हैं वे प्रायः इन्हे मान लेते हैं । परन्तु इतिहास और राजनीति के जानकार लोग जानते हैं कि ये सर्वथा थोथी बातें हैं और लोगों को गलत रास्ते पर डालने के लिये गढ़ी गई हैं । वास्तव में 'विस्काउण्ट ग्राइम' के शब्दों में पढ़ें तो—“व्यावहारिक रूप से अपने क्षेत्र में शासन करने का अवसर दिया जाना ही, जनता के लिये प्रजातंत्र शासन चलाने की शिक्षा का प्रधान साधन है ।”

मि० ग्राइम ही इस संरन्ध में आगे कहते हैं: “पिछड़े हुए समूहों में शिक्षा का प्रचार एक वाञ्छनीय कार्य है । परन्तु वह

उन्हें प्रजातंत्र चलाने के लिये अधिक योग्य बना दे. यह कोई आवश्यक बात नहीं है। उही स्यों, वह उन्हें और अधिक अयोग्य भी बना दे सकती है।" (मीटर्न टिमीकेमीड पहला भाग पृ० २६) मार यह कि राज्यवादियों से ऊपर उल्लिखित दलील सर्वथा मार्गपूर्ण और धोयी है। यूनाइज्ड किंगडम के सिस्टर पर या उन दिनों वहा प्रत्येक पुरुष-स्त्री को न केवल मताधिकार था प्रत्युत वहाँ की महासभा में अधिपेशन में प्रत्येक को जरूर बोलने और वदम करने का भी अधिकार था। आज जो कहा जाता है कि जितने कम आदमी हों, जितना ही काम अच्छा और विचारपूर्ण होता है, हमारे विपरीत वहा गंभीर से गंभीर मंथिपत्र तक मान २ हजार की महासभा में बहम करके स्थिर किये जाते थे। फिर भी उसी भाषा और उनकी धारणें इनकी ही निनिजतामय और विचारपूर्ण होती थीं, जितनी कि आज के अच्छे से अच्छे नीतिज्ञों से। और समय तो इन मामों में आज से भी कम लगता था। अतः प्रश्न यह है कि यदि हम जमाने की कम गिजित पर अशिन्ति जनता ऐसा कर सकती थी, तो अवसर और व्यावहारिक शिक्षा मिलने पर, शिक्षा और प्रचार के वैज्ञानिक मायनों में सम्यक्, आधुनिक नैत्यों की जनता वैसा क्यों नहीं कर सकती ?

यह तो रही पुरानी बात, आज भी हम ने इस चीज से व्यावहारिक बना कर दिग्घा दिया है। उसे रिस्ट्रिक्टेड की तरह छोटा देश भी नहीं कहा जा सकता। न ही यह कहा जा सकता है कि वहां की केन्द्रीय सरकार कमजोर है। क्योंकि जहा गत विस्फोटाशी महासभा के पूर्व इंग्लैंड प्रथम श्रेणी की शक्तियां में और कम तीमरी श्रेणी की शक्तियों में था, वहा पिछली क्रांति के बाद का कम आज प्रथम श्रेणी की और इंग्लैंड पांचवा श्रेणी की मैनिफ शक्तियों में आ गया है।

रही दूसरी दलील, सो उसका मूल आधार तो पहली ही दलील है। जब वही कसौटी पर नहीं ठहरती तो यह उठ ही नहीं सकती। क्योंकि जैसा कि कहा जा चुका है, कि राजनीति स्कूलों में पढ़ी जाने वाली वस्तु नहीं है। वह ऐसे विषयों में से है, जो व्यावहारिक शिक्षा द्वारा ही सीखी जा सकती है। यही कारण है कि पञ्चाथ केसरी महाराजा रणजीतसिंह और महाराष्ट्र वीर शिवाजी आदि अपढ और कम पढ़े होकर भी सफलनीतिज्ञ और स्वतंत्र शासक हो गए और हंगेरी तथा रूस का शासन भी लाई रूशन के शासकों ने। *unhappy in England 17, 18* मुनहरी पिंजड़ा की युलबुलें बने हुए हैं।

रूस में भी जब पहले पहल प्राप्ति करके मजदूरों ने शासन अपने हाथों में लिया, तब पड़े लिरों ने उनसे असहयोग कर उनका मजदूर उड़ाना शुरू किया था कि—“देखो, ये लोग कैसे शासन शासक चलाते हैं?” परन्तु सत्तार भर के कूटनीतिज्ञ साम्राज्यवादी राष्ट्रों के अपनी मारी शक्ति लगा देने पर भी, मजदूरों के अकेले, नवस्थापित राज्य ने जिस प्रकार सफलता पूर्वक इनका सामना कर अन्न में मारी दुनिया को अपने साथ सहयोग करने को बाध्य किया है, वह स्वतः इस बात का प्रमाण है कि राजनीति योग्यता स्कूली योग्यता पर निर्भर रहनेवाली वस्तु नहीं है।

ठीक ऐसा ही उदाहरण स्विट्जरलैंड का है। उदाहरण स्थापिका सभा के स्वीकृत कर लेने पर ही कोई ‘बिल’ गानून नहीं बन जाता। स्वीकृत हो जाने पर उस पर आम जनता का मत लिया जाता है, जिसमें जनता की तरफ प्रभुत्व रहने वाले पचाही पशुपालक भी मत देते हैं। इस प्रकार जनता का बहुमत जिस स्वीकृत बिल को मिल जाता है वही गानून बनता है।

इस विधान के फल स्वरूप वहां की जनता ने १८६६ से १८३६ तक व्यवस्थापिका सभा के बनाए और स्वीकृत किये हुए कानूनों में से ६६ स्वीकार किये और २६ बिल अस्वीकार कर दिये। उस समय अशिक्षित जनता के द्वारा शिक्षित नोतिधों के बनाए इन विधानों के अस्वीकृत हो जाने पर योरोप में बहुत कुछ कहा सुना गया था। आम जनता को इस प्रकार अधिकार दिये जाने की निन्दा की गई थी और उसके भयंकर परिणामों के चित्र खींचे गए थे। किमी २ ने तो यहाँ तक कह दिया था कि स्वयं मंत्र शासन नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा। व्यवस्थापिका के सदस्य और शासन-विभाग के अधिकारी उदासीन हो जायेंगे। आदि आदि। परन्तु पांटित्याभिमानों स्वार्थियों की ये सब भविष्यवाणियाँ भूठों साबित हुईं। इतना ही नहीं, कुछ वर्षों के बाद उन्होंने नीतिज्ञों को यह मान लेना पड़ा कि “जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दूरदर्शिता का काम किया था। वे स्वीकृत हो जाते तो उनसे राष्ट्र को बड़ी हानि पहुँचती।” अस्तु

इस पुस्तक का विषय प्रजावाद का इतिहास देना नहीं, प्रत्युत पाठकों के सामने केवल मतदान की वर्तमान पद्धतियों के भेद और उनके गुणावगुण रक्खना है, ताकि प्रजावाद के इस महत्वपूर्ण अंग के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाकर वे लाभ उठा सकें। अतः अब हम उम्मी विषय को प्रारम्भ करने हैं।



ए. ए. ए.

आधुनिक-सत्ताधिकार

६६६६६६६६

आधुनिक मताधिकार



इंग्लैंड

आधुनिक मताधिकार प्रथायें, उपरोक्त दोनों (रूस और स्विटजरलैंड) देशों से छोहकर, यद्यपि ये सब प्रजातंत्र के ही नाम पर जारी हैं, तथापि किसी भी देश में ये पूरे प्रजातंत्रीय सिद्धान्त के अनुसार नहीं हैं । इर्मालिये इन्हे विद्वान लोग प्रायः प्रतिनिध्यात्मक सरकारें Representative Government कहते हैं । इनके विषास का इतिहास भी कम बेचीदा नहीं है । आज तो ये शासन प्रणालियाँ फिर भी किसी हद तक इस नाम को चरितार्थ करती हैं, परन्तु अपने रीशर काल में तो ये मर्यादा विपरीतार्थ वाली थीं । अर्थात् नाम के लिये ये प्रजा की प्रतिनिध्यात्मक संस्था कहाँ जानी थीं, परन्तु वास्तव में हानों की राज्यसत्तावादियों की प्रतिनिध्यात्मक सरकारें ।

उदाहरण के लिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट—जो पार्लिया-
मेट की मानी थी—सन १८३२ के सुधारों के पहले सर्वथा
लार्ड्स (शिमींदारों और जागीरदारों) के प्रतिनिधियों की
संस्था थी । प्रजा के अन्य वर्गों का उम्मेद एक भी प्रतिनिधि न
होता था ।

१२३२ के सुधारों ने पहले पहल मध्यम वर्ग के कुछ भाग को मतधिकार दिया। इसके पहले इंग्लैंड का शासन ठीक वैसा ही था, जैसा कि मरदारों की प्रधानता के युग में मेगाइ में था। खजाने पर राजा का अधिकार था और शासन के द्वार में वह जैसे और जंग चाहे आर्टिनेम निकाल सकता था। हाँ, जार्ज-द्वारों पर वह हाथ न टालता था और इमलिये वे भी मुले मुंह जनता को लुटते थे। व्यापारी वर्ग की भी चुरी दृशा थी। प्रायः देश भर के लिये आवश्यक कपड़े और ममाले भारत से इंग्लैंड जाया करते थे। प्रजा भरपेट परिश्रम करके भी भूखों ही मरती थी।

आन्दोलन

आखिर प्रजा ने तंग आकर मन्. १६६० ई० में अपने प्रतिनिधित्व के लिये आन्दोलन शुरू किया। शासकों ने भी अपने स्वभाव के अनुसार इसे दबाने की चेष्टा की। परन्तु इस चेष्टा ने उसे दबाने के बजाय और बढ़का दिया। अन्त में मन्. १६८८—८९ में वहाँ क्रांति हो गई एवं तब वहाँ जाकर प्रजा को थोड़े से प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिला।

परन्तु इस ने जनता को लाभ कुछ नहीं हुआ। क्योंकि प्रथम तो इस के प्रतिनिधि बहुत थोड़े थे। दूसरे उन्मेद्वारों की योग्यताएँ ऐसी निर्दिष्ट की गई थीं कि इस हैमियत के आदमी उनके वर्गों में प्रायः मिलते ही न थे और इमलिये उन्हें उन ही वर्गों के लोगों में से अपने प्रतिनिधि चुनने पड़ते थे, जो गामकों से मिल जा सकते थे : यथा बड़े २ व्यापारी आदि।

स्वभावतः यह न्यायि देगकर तीसरे जार्ज के समय में जनता ने फिर आन्दोलन शुरू किया। परन्तु इसी समय फ्रांस में राज्य क्रांति हो गई। और इसके बाद तो नैपोलियन के युद्धों

का नाता ही पथ गया। अधिकारिया ने भी डम रिति में स्व लाभ उठाया। उन्होंने देश की रक्षा के नाम पर गरीबों से अपना अमन्तोष हृदय में ही दबा रखने की अपील की और भायुक जनता मान गई। यह भी विश्वास दिलाए गए कि अशान्ति और युद्ध से दुष्टकारा पाते ही प्रजा के लिये स्वर्ग का द्वार खुल जायगा। उसे मुँह मागे अधिकार दे दिये जायेंगे।

परन्तु प्राम की प्राप्ति को धीरे धीरे चालीस वर्ष बीत गए। उसकी पैलाई हुई चिंगारिया भी बुझ गई और उसकी स्मृतियाँ भी धुंदली पड़ चलीं। फिर भी स्वर्ग का द्वार नहीं खुला। प्रजा को कोई अधिकार नहीं दिया गया। यही क्या, शासन वर्ग वाले उस "दु स्वप्न" को मानों भूल ही गए।

दूसरा आन्दोलन

बिप्लव हो जनता ने फिर आन्दोलन शुरू किया। इस आन्दोलन की गति भी पहले से तीव्र थी। शासकों ने भी फिर एक बार इसे दबा देने की कोशिश की। जनता ने भी दृढ़ता से सामना किया।

इसी बीच प्राम में दूसरी राज्य प्राप्ति हो गई। अधिकारिया ने पहले ही की तरह इस अवसर से भी लाभ उठाना चाहा। देश-रक्षा के नाम पर जनता से आन्दोलन रोकने की अपील की गई। परन्तु अब जनता इन चालों को समझ चुकी थी। पाठ की हाडी एक ही बार चढ़ती है। इसी लिये उसने आन्दोलन को घन्ट करके के बजाय प्रान्ति पर डाली, और इसी का फल थे १८३२ के सुधार।

परन्तु ये सुधार भी चाला में खाली न थे। उनमें भी मताधिकार इनका संकुचित रखा गया था कि हिंदू, मजदूरों

और कारीगरों के मन्चे प्रतिनिधिया का शामिल यत्र म धुमना प्राय अमम्भय था। हों, इस बार जनता के आर्थिक कष्ट कम करने का विशेष रूप में प्रयत्न किया गया। व्यापार ग्ना के लिये भी नई योजनाओं की गई। इसी उमाने में भारतीय माल पर मनमान टैक्स लगाकर इंग्लैंड के "योग" उन्नों को "तन करने का" प्रक्रम किया गया।

१८६६ की क्रांति

परन्तु ऐम पायों में जनता अधिक दिन शान्त नहीं रह सकती। विशेषतः जब कि रूसी औरों के सामने प्राम की क्रांति हो चुकी थी। और भी कुछ बातें उसे उल देनेवाली हो गई। इस समय पालियामेंट में चुनकर जाने वाले तो प्राय दो ही वर्गों जिमीनारों और बड़े-बड़े व्यापारियों के व्यक्ति होने थे, परन्तु मताधिकार मध्यम श्रेणी के लोगों से भी था। स्वभावनत हमारे नेगलिस्ट, लिबरल और म्बगजिस्ट आदि दलों की तरह इंग्लैंड के इन दोनों दलों में प्रतिद्वन्द्विता चलती रहती थी। प्रत्येक दल यह चेष्टा करता था कि वह अपना बहुमत बना ले, ताकि वह अपने वर्ग के लिये हित कर कानून बना सकें। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रत्येक वर्ग जनता का अपनी ओर आकर्षित करने को नाथ्य था। अतः स्वभावनत व्यापारी वर्ग ने साधारण जनता को अपने पक्ष में लेने के लिये उनके मताधिकार का प्रश्न उठाया। "ब्राइट" और "मैटमन" नेमे व्यक्ति इस आन्दोलन के अगुआ बन गए और इस प्रकार प्रगतिशील चलती हो गई।

इसके फल में १८६७ ईस्वी में फिर सुधार हुए। इस बार कारीगरों और किसानों के भी पूरा भाग को मताधिकार मिला। परन्तु इसका लाभ भी विशेष रूप से एक दो वर्गों को ही

मिलता था। कारण, प्रथम तो उम्मेदवारों की योग्यताएँ ऐसी निश्चित कर दी गई थीं कि उस श्रेणी के व्यक्ति इन वर्गों में बहुत कम निकलते थे। दूसरे चुनाव पद्धति इतनी व्यवस्थित रखी गई कि गरीब वर्ग जब तक पूर्णतः संगठित न हों, उसका पूरा लाभ न उठा सकते थे। तीसरे, इसी वर्ग के लोग जनता के नेता बन गए थे और राज्य जाल द्वारा उन्हें अपने पजे में फसाए हुए थे।

धीरे धीरे यह स्थिति जनता की दृष्टि में आने लगी। सच तो नहीं, कुछ लोग ऐसी चालों को समझने लगे। चलत फिर आन्दोलन उठा और १८८४ ई० में पुनः कुछ सुधार हुए जब इस पार किसानों और कारीगरों के बड़े कारी भाग को मताधिकार मिल गया।

मजदूरों में जागृति

परन्तु मजदूरों और स्त्रियों को अब भी मताधिकार न था और चूँकि इंग्लैण्ड उद्योग प्रधान देश बन चला था और गाँवों की जनता निरन्तर कारखानों में भरती होकर मजदूरों की संख्या बढ़ा रही थी, अब देश का बहुमत अब भी अधिकारहीन ही रहा। ऐसा करने का मुख्य कारण यह भी था कि शहरों में रहने से मजदूर लोग राजनैतिक प्रश्नों को जल्दी समझने लग जा सकते थे। गाँवों में तो राजनैतिक ज्ञान को पहुँचाने काही समय लगता है और इसलिये वहाँ के लोगों के अज्ञान का लाभ उठा उपरोक्त वर्ग आसानी से उनके प्रतिनिधि पर नेता बने रह सकते थे। किन्तु शहरों में यह अधिक दिन सम्भव न था। यही कारण था कि मजदूरों को मताधिकार देने में बराबर टक्का-टुली होती रही।

आखिर इस वर्ग में भी असन्तोष पैदा हुआ, और स्त्रियों तथा मजदूरों ने भी मतधिकार के लिये आवाज उठाई । उस प्रगति को दवाने में भी कसर नहीं रखी गई । परन्तु गिरते पड़ते अन्त में वह बलवती हो ही गई । और इस प्रकार ३० वर्ष में अधिक आयु की स्त्रियों तथा मजदूरों के अधिकांश भाग को १९१८ ईस्वी में मतधिकार मिल गया ।

परन्तु इस मतधिकार का भी पूरा उपयोग अमम्भव बना दिया गया । क्योंकि "हाउस आफ कामन्स," जिसमें इन सब वर्गों के प्रतिनिधि चुने जाते थे, अकेला ही किमी बिल को स्वीकार करके कानून नहीं बना सकता था । उसका "हाउस आफ लार्ड्स" से भी स्वीकार होना अनिवार्य था । और हाउस आफ लार्ड्स में तो वंशानुगत ज़िमीदारों एवं जागीरदारों के ही प्रतिनिधि होते हैं । जनता पक्ष के लिये उसमें स्थान न तो पहले था, न अब है ।

दो व्यवस्थापिका सम्भाग

प्रतिनिध्यात्मक शासन के नाम पर अप्रतिनिध्यात्मक शासन या प्रजावाद के नाम पर वर्गवाद की यह दूषित पद्धति इङ्ग्लैण्ड की पार्लियामेण्ट की ही विशेषता नहीं है । अधिकांश देशों में इन देशों में भी, जहाँ प्रत्येक बालिग व्यक्ति को मतधिकार प्राप्त है वहाँ भी भिन्न-भिन्न उपायों से धास्निक लोकमत का प्रभाव शासन पर न पड़ने देने की ऐसी व्यवस्थाएँ हैं ।

ऐसे उपायों में से एक प्रधान उपाय दो व्यवस्थापिका (कानून बनानेवाली) सम्भागों की पद्धति है । आम तौर पर इनमें से एक मावागण जनता के भिन्न-भिन्न वर्गों के वा सम्मिलित चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी होती है, और दूसरी

अल्पमत—कम सदस्य वाले समूहों के प्रतिनिधियों की । और चूँकि दुनिया भर में अल्प संख्या धनवाना और भूसामिया की ही है, जानि, धर्म आदि के आधार पर अधिकांश देशों में चुनाव नहीं होता, अतः इस दूसरी सभा में बहुमत आम तौर पर राज्यवादियों और पूँजीपतियों का होता है। यह बनाई है। इमालिण जानी है कि यदि जनता के प्रतिनिधियों की व्यवस्थापिका सभा शासन क्षेत्र में फ्राई एम्मा नातिकारी परिवर्तन करना चाहे, जिससे बड़े लोगों के स्वार्थ का धक्का पहुँचता है, तो दूसरी व्यवस्थापिका सभा उसे अस्वीकार कर देती है। यह उस नव नव कानून नहीं बनने देती, जब तक कि वह सर्वथा या अधिकांश में उमफ अनुकूल न बन जाय। यही कारण है कि इंग्लैंड और दूसरे देशों में अनेक बार मसदूर या रिमानों के प्रतिनिधियों का बहुमत हो जाने पर भी, वे कभी साधारण गरीब जनता के लिए वह स्थिति पैदा नहीं कर सके, जो बड़ा की बनी हुई है। इस प्रकार फूटनीति पूर्ण चुनाव पद्धति की पड़ोसत नाम के लिए देश के बहुमत या प्रजा के हाथ में शासन होने पर भी, सर्वत्र प्रायः अल्प-संख्यक सत्ता धारियों की ही नृती घोलती है।

और चालें

इस के अतिरिक्त और भी बहुत सी चालें सम्पन्न लोगों की ओर से अपना गोलार्ध पंजा शासन पर जमाए रखने के लिए पली जाती हैं। गरीबों में से जो व्यक्ति कुछ योग्य निम्नता है, उसे पद, प्रतिष्ठा, सम्पत्ति आदि देकर खरीद लिया जाता है। यह ऊपर से गरीबों का मेरक बना रहता है। पूँजीपतियों और राज्यसत्ता को दोमता रहता है और इस प्रकार गरीबों का सर्वत्र प्रतिनिधि बन जाता है। परंतु जब व्यावहारिक रूपसे कुछ करने

का प्रश्न आता है, तब वह पू जीपतिया और मत्ता का ही लाभ पहुँचाना है। कभी गरीबों की हितरक्षा के अवसर पर वह बीमार हो जाता है और सभी अन्य कारणों में अनुपस्थित हो जाता है। इस प्रकार लोग उसे भ्रम में डालकर वह सारी श्रमों में तब प्रतिष्ठा के साथ उनका नेना बना रहता है।

इसके अनिश्चित पटुत में पू जीपति या मत्तावारी स्वयं भी जनता का रख देकर कभी मामूली आँख कभी कम्यूनियन्त तक बन जाते हैं। इन में खरीडे हुए प्रचारक और समाचार पत्र ता उनके हाथ में होते ही हैं, अतः उनके पल पर बिना कोई त्याग की टोम मेवा किये, जोड़े में जोड़े समय में वे प्रसिद्धि नेना बन जाते हैं। और जनता के मस्तिष्क पर विचारों का निर्माण तो आज कल अपेक्षा का माधनों में होता ही है। अतः वह भी हम पर जल्दी विग्राम करने लग जाती है।

इसी तरह भिन्न-भिन्न आकर्षक और धामक नामानाली समस्याएँ गूँथी जाती हैं। आश्रम स्थापित किये जाते हैं। इनमें तैन्तिक नौकर रखे जाते हैं। उन्हें अच्छे लेखक पर मगठनकर्ता बनाया जाता है। हा, इन की मस्याआ की चोटी अपने हाथ में रखी जाती है। इनके कार्यकर्ता स्वयं रुझाचिन् हो किसी व्यवस्थापिका के लिये खड़े होने हैं। उन्हें आश्चर्य होता है क्या है, जब कि भिन्न-भिन्न रूपों में उन्हें प्रतिष्ठा के साथ कारी धन मिलता है। वे केवल निम्नार्थ सेवा का चोला पहने रहते हैं। यहाँ तक कि मार्गजनिक सेवाआ और उनके कामों में भी जनता में कुछ व्यवस्था नहीं करते। ऊपर से कहते हैं—“इन गरीबों के पास क्या है, जा इन में खर्च करावें। इनके लिये तो धन इन धनियों में लाना चाहिये, जो इन्हीं को लूट कर मोटे पने हुए हैं।” मोली जनता इन बातों पर मुग्ध हो जाती है। वह विचारों का ममने

कि इन का वास्तविक ध्येय कुछ और है। यदि यशे को सदा गोदी में रखा जाय एवं अपने हाथ पैरों में काम निवृत्त न करने दिया जाय तो वह पशु हो जायगा। इसी प्रकार जो समूह अपना संगठन, अपनी शिक्षा, अपनी रक्षा और अपने भरण पोषण के लिये दूसरों पर ही निर्भर रहता या रक्खा जाता है, उसमें स्वायत्तत्व नहीं आ सकता। वह सदा के लिए पर मुत्तापेजी बन जाता है। और जिस दिन वह स्वतंत्र विचार का आश्रय लेना चाहे, उसी दिन क्षान्ता लोग अपनी मुट्ठी उदर कर के पलक मारते हैं उसके माया के मसार को चीपट कर दे मारते हैं। इससे अति रिक्त, इस विधि से ऐसे संगठनों में काम करने वाले भय कार्यकर्ता दाताओं के हाथ में और उनके इंगित पर चलने वाले रहते हैं उनका ध्येय केवल कमाना होना है, न कि सेवा।

इस दृष्टि में ऐसे दल शरीरा का संगठन स्वायत्तत्वन व आधार पर नहीं करते। अपना धन स्वयं करके करते हैं। तब ही उनके आन्दोलन का उपयोग अपने लाभ के लिये, जो जरूर आवश्यक हो, कर लिया जा सके और फिर जिस दिन इच्छा हो, उसे तुरन्त रतम पर दिया जा सके। यही इस परापर और दया की भावना का रहस्य होता है। ऐसी संस्थाओं का राजनैतिक होना जरूरी नहीं होता वे मिश्रित धार्मिक (मिश्रकारी) भी होती हैं और जो बालक सच जैसी अर्द्धराष्ट्रीय अथवा शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी भी। परन्तु विचार अशिष्टित शरीर इन पेचीदगियों को क्या समझें ?

यस इस प्रकार प्रभाव जमा कर चुनाव का अवसर आते हैं उस प्रकार का उपयोग कर लिया जाता है और दाताओं की पसन्द के आदमी चुन लिए जाते हैं।

उही क्यों, यदि मत्तारियों को छीं टानन्दाय अथवा पाप जैसा व्यक्ति भिन्न जाना है तो वे उसे शीघ्र अवतार बना देने दें और फिर उसके प्रभाव की दृष्टान्तदारी करते हैं।

उसके अलावा ऐन नीति पर भिन्न भिन्न प्रकार की गिनतों से मनदान और उम्मेदवारों और प्रचारकों को खरीदा जाता है। किसी का पद का किसी को नोकरी का, किसी का ठेके आदि देने का और किसी को व्यापारिक प्रयत्न बन दिया जाता है। भिन्न २ समूहों और जातियों की समस्याएँ उनका हर उन की मागों अपने पण्डितों के हाथों में ली जाती हैं। मातृ महन्तों और प्रमाचारों को खरीदा जाता है। समाचार-पत्र खरीदे जाते हैं। प्रतिकारी मान लिये जाते हैं। शिक्षा समस्याओं के द्वारा जनता के सम्मुख या निकट कराया जाता है। जातियों और प्रमों में दलबन्धिता कराई जाती है। पदोन्नति करने जाते हैं। नृदमर और मातृपौट कराई जाती है। छोटे प्रबन्धनों और मध्यमवर्ग के लोगों को भिन्न २ प्रकार के प्रलोभन दे अपने पक्ष और गरीब जनता के विरुद्ध आग्रह बनाया जाता है।

मात्र यह कि उन मत्तारों और पूर्णता की त्रिपुर्ण द्वारा तो कुछ भी होना है, मन किया जाता है, ऐसी अवस्था में क्या आश्चर्य है यदि मातृवर्ग जनता मन कुछ करने पर भी अन्न में अपने को असमर्थ पाती है ?

परिणाम

उस स्थिति का परिणाम यह हुआ है कि आज प्रत्येक देश में पुराने अधि, पण्डित, पुरारियों और मन्तों की जगह Professional Politics के पिछे रह गये हैं। ये लोग प्रत्येक चुनाव में जनता का आकर्षित

करने के लिये नष्ट = स्वाग रचते हैं और नित्य नष्ट मेल मेलने हैं। जनता विचारी इन चाला को तो समझने में असमर्थ है, परन्तु इतना उसे अवश्य विरास हो चला है कि ये प्रति-निध्यात्मक संस्थाएँ निरुद्धी हैं वे उसका कुछ भला नहीं कर सकती। लागा का व्यवस्थापिकासभाओं में ही नहीं, प्रजातंत्र आदि पर में भी विश्राम उठ चला है। वे प्रायः कह उठते हैं कि "इस बेलगाम प्रजावाद में तो राज्यवाद ही भला।" क्योंकि आखिर इसमें इन सार कूट चक्रों में जो अनन्त धन व्यय होता है, वह भी तो भिन्न भिन्न रूपों में साधारण प्रजा में ही उसूल किया जाता है और इसीलिये प्रत्येक शासन सुधार का अनिवार्य परिणाम कर-वृद्धि होता है। और साधारण प्रजा का अशिक्षित व्यक्ति उन पैर्वाद्गिथा का क्या समझे, जिनके द्वारा प्रजावाद को अमफल बनाया जा रहा है। यह तो अपने सुख दुख पर में ही शासन की घुराई भलाई का अनुमान करता है और इसीलिये प्रजावाद को बोलने लगता है।

परन्तु धूर्त सत्तावादी उसको इस निराशा में भी लाभ उठाते हैं। वे उसकी इस धारणा को यह कह कर और हट करने की चेष्टा करते हैं कि हम तो पहले ही कहते थे कि 'प्रजावाद घुरा है। सर्व साधारण में शासन करने की योग्यता नहीं होती।' इत्यादि

गनीमत यही है कि साधारण प्रजा में भी अब मन ही मन नहीं हैं। इस के अतिरिक्त समष्टिवाद के प्रचार ने बहुत कुछ लोगों का भ्रम दूर कर दिया है और इसलिए अब जहाँ साम्यवादी सरकार स्थापित करना असम्भव है, वहाँ भी लोग निराश हो जाने के स्थान पर वर्तमान चुनाव पद्धतियों में ही भिन्न-प्रकार के मशोर्धन कर आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। यही

कारण है कि आज प्रायः प्रत्येक प्रजातंत्रीय देश में चुनाव पद्धति के सुधार का आन्दोलन चल रहा है ।

नए उपाय

लोगों का अविश्वास, उपरोक्त कारणों से, व्यवस्थापिका समारोहों में इतना गहरा हो गया है कि यूनान में वेगों में उनके सदस्यों से लोग पूर्ण-भ्रष्ट Plunder Band "लुटेरा बल" Puppets or Party Bosses "पूँजीवादियों के बल के प्रजेक्ट" Selfish Pack "स्वार्थी टोली" Mercenaries "भाड़े के दूढ़" आदि नामों से पुकारते हैं । (Demand of Democracy) ।

इतना ही नहीं, व्यवस्थापिकाओं द्वारा और उनके चुनावों में उपयोग किये जाने के कारण ही लोगों को पुलिस, अदालतों और शिष्टकों तक पर अविश्वास हो गया है और आज प्रायः सर्वत्र यूनान की तरह यह चेष्टा हो रही है कि इन मयरी चांदी सीरी भागए उनका के हाथ में हो ।

इस ग्रेम की पूर्ति के लिये रोगों के गजनीनि विगारकों ने चार नए उपायों का आविष्कार किया है—Referendum Initiative, Recall and Plebiscite, हमारे देश में भी बहुत से शिल्पित तक इन गजनों ने परिचित भी नहीं हैं । इन राज्यों की तो बात दूर, बम्बई कांग्रेस में जो कांग्रेस चुनावों के लिये Single Transferable Vote की पद्धति स्वीकार की गई, उसी के सम्बन्ध में कई विद्वान और सम्पादक तब उस समय यह पूछने देगे गे थे कि "मिलन ट्रामकरेंचन बोट" किसे कहने हैं ।

चूँकि हमारा देश भी प्रजापद के उम्मेदवारों में से एक है और ये सब कठिनाइयाँ किसी न किसी रूप में उसके सामने भी आने लगी हैं और आवेंगी, अतः इस पुस्तक में इसी दृष्टि से भिन्न-भिन्न चुनाव पद्धतियों का विवेचन किया जा रहा है कि देशवासी इसमें लाभ उठाकर, हो सके तो उन रास्तों में प्रचुर चले, जिनमें न बचकर और देशों की जनता ने हानि उठाई है।



१९५७

चुनाव पद्धतियाँ

१९५७

सुधार की आवश्यकता



आजकल कानूनों का युग है। क्या पुराई और क्या भलाई, आजकल सब कुछ कानून के नाम पर और कानून द्वारा की जाती है। व्यवस्थापिका सभाएँ इन कानूनों के घड़े जाने के कारणाने हैं। परन्तु चूँकि मानव समाज में हम समय बड़े २ भेद, उपभेद वर्तमान हैं, जिनके स्वार्थ एक दूसरे से पृथक् ही नहीं, एक दूसरे के विरुद्ध भी हैं, अतः इनमें सदा एक दल नहीं रह पाता। कभी किसी दल का बहुमत हो जाता है, कभी किसी का। इसीलिए इन व्यवस्थापिकाओं के बनाए कानूनों में भी बहुत कम स्थिरता होती है। इस चुनाव में आया हुआ दल एक कानून को बनाना है और दूसरे चुनाव में विजयी हुआ दूसरा दल उसे रद्द कर देता है।

यही कारण है कि लोग नित्य की इस उथलपुथल में डूब गए हैं और किसी ठोस अस्स की गोज में हैं, जिसके द्वारा हम अस्थिर और अनिश्चित जीवन में यथार्थ स्थिरता लाई जा सके। और यह उपाय इसके सिवाय और क्या हो सकता है कि शासन और व्यवस्था की बागडोर उस माध्यम जनता या बहुमत के हाथ में दे दी जाय, जिसके हितों में समानता है।

इसका एक और भी कारण है। आखिर “राज्य” है क्या ? जनता की सामूहिक व्यवस्था के लिये गमकी ओर में बनी और

उनाई हुई संस्था ही न ? ऐसी अवस्था में वह मस्या राष्ट्र की जनता के मनोनुकूल चलने वाली और उनकी इच्छाओं को ठीक व्यावहारिक रूप देने वाला होनी चाहिये । तब ही यह जनता की प्रतिनिधि कही जा सकती है, अन्यथा नहीं । यदि जनता का प्रबल बहुमत किसी देश की व्यवस्थापिकाओं में अल्पमत में रहता है, तो यह निश्चित है कि ऐसी सरकार अपने को प्रजातन्त्र या अपनी प्रजा की सरकार कह कर सत्ता को धोखा देती है । ऐसी सरकार अधिक दिन तक जनता की विरामपात्र पर श्रद्धाभाजन नहीं रह सकती । पार्टी के अनुगामन के नाम पर कोई सरकार या दल अपने व्यवस्थापिका के सदस्यों और उनके सहायकों को भले ही गुलाम बना ल, परन्तु जनता की स्वतन्त्र विचारशक्ति को कोई मक्का केलिये गुलाम नहीं बना सकता । यह आगे पीछे ऐसी सरकार के अनुगामन को भग करेगी और अशान्ति को जन्म देगी । Gerrymandering (सामान्यतः दल का अगले चुनाव में मजबूत होने के लिये मतान्तरिक्ष और चुनाव-क्षेत्र आदि के सम्यन्वय में गुप्त चालें चलना—यथा चुनाव क्षेत्रों का पुनर्विभाजनादि) और Dark Horses (किसी क्षेत्र में किसी एक दल का बहुमत न होने पर परस्पर विरागी दल मिल कर समझौते द्वारा जिस किसी एक को गढ़ा करें) उस समय कुछ काम नहीं आते । अन्तु,

अब हम प्रत्येक प्रकार की चुनाव-पद्धति और उनके गुण दोष मलेप में पाठकों के सामने रखते हैं ।

सिंगल वोट (SINGLE VOTE)

इसका ध्येय था योग्यतम उम्मेदवार का मत्र वोटों-मन-प्येय दाताओं के बहुमत में चुना जाना । साथ ही यह भी कि एक मतदाता को एक ही वोट देने का अधिकार देने में यह

उसका प्रयोग विशेष प्रिवेक के साथ करे। फल प्रमत्त करने के लिये किसी को न दे दे।

इस पद्धति में प्रत्येक मतदाता (वोटर) को एक ही मत प्रावधिक किसी एक उम्मेदवार को देने का अधिकार होता है। यह सन् १९०० ई० में पहिले पहल जापान में प्रचलित किया गया था।

प्रारम्भ में यह कुछ लाभदायक साबित हुआ था। परन्तु आज चल कर राजनैतिक मद्धारियों ने इसे और भी हानि-प्रारक बना डाला। इसमें सन्देह नहीं कि यदि एक चुनाव क्षेत्र से दो ही उम्मेदवार खड़े हों और मतदाता अपने मत का मूल्य जानते हों, तो अधिकांश मत से अधिक योग्य व्यक्ति ही इस पद्धति में चुना जा सकता है और वह प्रजा के बहुमत का प्रतिनिधि हो सकता है, परन्तु आज तो चुनाव क्षेत्र ईमानदारी के अग्राडे नहीं हैं। आज तो समर्थ उम्मेदवार अपने पक्ष के वोटों की सख्या निश्चित कर शेष बाटा को विभाजित कर देने के लिये चाहे जितने बरखी उम्मेदवार भी खड़े कर देते हैं। उदाहरण के लिये मान लीजिये कि एक चुनाव क्षेत्र में एक धनिर या सत्ताधीश के पक्षपाती २००० वोट हैं और कुल क्षेत्र में ६०००० वोट हैं। ऐसी दशा में वह उम्मेदवार भिन्न भिन्न वोटों के दल में लोकप्रिय ६-७ उम्मेदवार खड़े कर देता है। यदि मान लीजिये कि इसके पक्ष स्वरूप सत्र के पाँच-पाँच सौ रुपये, जो प्रोस के जमा कराए जाते हैं, खर्च हो जाँय तो भी तीन सार्द तीन हजार रुपये का ही सट्टा (जूआ) होता है जो निम्नी सम्पन्न व्यक्ति के लिये कठिन नहीं है।

परिणाम यह होता है कि जेथे मार मन इतने उम्मेदवारों से घेरे का दा-दा हजारों में कम संख्या में रह जाते हैं और घनिक उम्मेदवार अपने निश्चिन्त बोटों में जीत जाता है। इस प्रकार यदि इन सब मनों को मचे भी मान लें तो भी वह जनता या मतदानियों के बहुमत का प्रतिनिधि नहीं, केवल पंचमांग का प्रतिनिधि होता है। और यदि ये 'मन' रूपों के यत्न से या अधिकारियों के प्रचार कर्त्तव्य, अहंमान, जानि, धर्म या रिश्ते के दबाव द्वारा प्राप्त किये हुए हों, जैसा कि प्रायः होता है, तो वह रिश्तों का भी प्रतिनिधि नहीं होता। यह केवल मक्कारी और धन का प्रतिनिधि होता है। और ऐसा प्रतिनिधि या ऐसे प्रतिनिधियों में कौन व्यवस्थापिका जनता के हितों की क्या रक्षा करेगी? बहुधा इसके फल में एक दल का—यह भी प्रजा पर अन्याचार करने वाले दल का—गामन रह जाता है। कहीं कहीं इसे "मिगल ट्रांस्फरेंस बॉट" भी कहा जाता है, परन्तु वह युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता।

मेकण्ड बॉलट (SECOND BALLOT)

"मिगल बॉट" पद्धति के अत्यन्त जटिल को दूर करने के लिये और इस पद्धति का आधिकार हुआ था। इसका प्रयोग फ्रांस, जर्मनी, इटली, आस्ट्रिया, बेल्जियम आदि देशों में हो चुका है। इसके मित्र मित्र देशों में मित्र २ रूप हैं। इसका मुख्य ध्येय यह है कि सफल उम्मेदवार मतदानियों के बहुमत में ही चुना जाय।

उसकी सब से महत्वपूर्ण पद्धति यह है कि प्रत्येक उम्मेदवार के लिए प्रत्येक मतदान को दो बार दो जगह मन देना पड़ता है। पहला मन इसका मुख्य माना जाता है और दूसरा गौण। इस प्रकार दोनों बार के मन

ज्यावहाकि
पद्धति

मिलकर जिसके पक्ष में सबसे अधिक मत आ जाते हैं, वही उम्मेदवार चुना जाता है।

फ़ार्म में उम्मेदवार का सफल होने के लिये यह आवश्यक होता है कि वह पहिले ही मतदान में बहुमत प्राप्त करे। अर्थात् यदि उस चुनाव क्षेत्र में १०००० वोट्स हों तो उसे ५००० से ऊपर पहले मत मिलने चाहियें। परन्तु यदि किसी उम्मेदवार में इतने मत न मिलें, तो दूसरे 'बैलट' में उसको औरों की अपेक्षा अधिक मत मिल जाना ही काफी सम्भवा जाता है।

परन्तु अनुभव से मान्य हो चुका है कि यह पद्धति भी पहली पद्धति की तरह ही सद्बोध है। जहाँ कई उम्मेदवार एक ही 'सीट' के लिये गड़े हो जाते हैं, वहाँ यह पद्धति भी जनता के हित की रक्षा नहीं करता। जो व्यक्ति 'घाले' पहली पद्धति को दुपित बनाती हैं, वे ही इसे भी निरुद्धी बना डालती हैं। पहली में तो व्यक्ति का ही पतन होता है। परन्तु इसमें तो दल का भी पतन होता है। क्योंकि किसी उम्मेदवार को सफल बनाने के लिये कई दलों को मिलाना आवश्यक होता है और इसलिये दूसरे दलों में सहयोग करने के लिये प्रत्येक दल का किसी भीमा तक अपने सिद्धान्त छोड़ने पड़ते हैं। चुनाव हुआ व्यक्ति भी 'मात मामाओं के भानजे' की तरह किसी भी दल का सच्चा प्रतिनिधि नहीं बन सकता। न वह अपने विवेक के इंगितानुसार उहा लाऊ-हित के लिये कुछ कर सकता है, न किसी राजम दल के कार्य-क्रम के अनुसार। उसे दुबारा चुने जाने के लिये मतदानियों का जो दल में अधिक संगठित हो—और इस युग में यह सम्भव नहीं का ही हो सकता है—उसी का गुलाम बना रहना पड़ता है। इसीलिये लोग इस पद्धति को पूर्णतः मानने लगे हैं।

सिंगल ट्रांसफरेंसल वोट

(एकाकी हस्तान्तरित मत)

यह एक प्रकार से मेकडवैलट का ही दूसरा रूप है। उपरोक्त पद्धति में जो दो-चार चुनाव और अनिश्चित व्यय तथा श्रम की कसौटी पड़ती थी, उसे दूर करने के लिये ही इसका आविष्कार हुआ था। इसका उद्देश्य एक ही बार हुए चुनाव में 'दूसरे वैलट' का कार्य पूरा कर लेना था।

इसको भी व्यावहारिक रूप देने का कई पद्धतियाँ हैं। मत्र में मरल पद्धति यह है कि जिनने उम्मेदवार एक पद के लिये हैं, उनमें से जिने वह मत्रमे योग्य समझता हो उसे वह अपना पट्टा वोट देकर उसके सामने (१)—चिन्ह बना देगा परं जिसे प्रथम उम्मेदवार के मर्यादा अमरल होने की प्रवस्था में सान्द्रनीय समझे, उसका मत देकर उसके आगे (२) का चिन्ह बना देगा। इसी प्रकार और उम्मेदवारों के लिये करना जायगा।

इस प्रकार मत ले चुके जाने पर, जिस उम्मेदवार के पत्र ने मत्र मे कम मत आए हा, उसे अमरल गोपिन कर दिया जाता है और उसे मिले मत (२) के चिन्ह वाले मतों में सम्मिलित कर दिऐ जाते हैं। इसी क्रम मे जिने या जिन्हें मत्र मे अग्रिम मत प्राप्त होते हैं, वह या उन्हें 'मरल हुआ' गोपिन कर दिया जाता है।

यह पद्धति पहले पल्लू प्रोलेट और न्यू मान्य वेल्थ क्लासों में, पट्टो पद्धति द्वारा होने वाले मोटा के विभाजन को रोक्ने के लिये प्रचलित की गई थी। परन्तु इसमें यह उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। क्योंकि प्रायः विद्वत् संसर्ग से एक दल को हराने से दूसरे दो दल मिल जाने थे। किन्ती निदान

या जनहित का ध्यान नहीं रखा जाता था। और अनेक बार तो इसी उद्देश्य से दो दलों में विरोध तफ़फ़ा दिया जाता था।

ALTERNATIVE VOTE (आल्टर्नेटिव वोट) (या हस्तान्तरित मत पद्धति)

इस का ध्येय थोड़े वोटों के मिलने पर भी ऊपर वर्णित घाला में ध्येय किसी उम्मेदवार को अफल न होने देना है। इस ध्येय को यह एक सीमा तक पूर्ण भी करना है।

परन्तु वास्तव में यह "सिंगल ट्रांसफ़रेबल वोट" का ही दूसरा व्यवहार पद्धति रूप या भेद है। अन्तर इतना ही है कि यहाँ "सिंगल ट्रांसफ़रेबल वोट" एक ही दूसरे उम्मेदवार को दिया जा सकता है परन्तु 'आल्टर्नेटिव वोट' में यह सीमा नहीं है। इस पद्धति के अनुसार जिस चुनाव-क्षेत्र में जितने उम्मेदवार चुने जाने हों, उतने ही मत प्रत्येक मतदाता दे सकता है।

हस्तान्तरित मत पद्धति

इस पद्धति से ठेमे ही निर्वाचन-क्षेत्रों में काम लिया जाता है जहाँ से कई-यह प्रतिनिधियों का निर्वाचन होने वाला है। अलग अलग दलों के उम्मेदवार रखे होते हैं। इस पद्धति में हर एक वोटर को यह बताने का मौका दिया जाता है कि वह रखे हुए उम्मेदवारों में से सबसे अच्छा जिसे समझता है और जिन्हें दूसरे, तीसरे और चौथे आदि नम्बरों के योग्य। मतदाता जिस उम्मेदवार को सबसे अच्छा समझता है उसके नाम के आगे नम्बर १ लिख देता है, इसी तरह दूसरे उम्मेदवारों के नाम के आगे भी वह अपनी समझ के अनुसार २, ३, ४ आदि नम्बर लगा देता है।

पर्याप्त संख्या

इस पद्धति में एक बात यह भी समझ लेने लायक है कि चुनाव पर्याप्त संख्या में होता है। अर्थात् जितने प्रतिनिधि जिस क्षेत्र में चुने जाने जरूरी हों उनमें इस क्षेत्र के मत परा-
 यर २ वोट दिये जाते हैं। इस प्रकार वोटने पर जो संख्या निकलती है, वह पर्याप्त संख्या मानी जाती है; यानी उतने वोट जिस उम्मेदवार को मिल जाँय वह चुन लिया जाता है। इस पद्धति को एक उदाहरण देकर हम और भी स्पष्ट कर देते हैं। मान लीजिये कि कुछप्रांत में अखिल भारतीय महाममिति के लिए ५० मदन्यों का चुनाव होना है और प्रांत की और में चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या ५०० है, इस सूत्र में ५०० को ५० में भाग देने पर पर्याप्त संख्या १० आयेगी। इस हिसाब में जिस उम्मेदवार को १० मत मिल जाँयें वही चुन लिया जायगा।

विशेष लक्ष्य इस पद्धति में यह है कि इसमें किसी मतदाना का 'मत' पैकार नहीं जाता क्योंकि एक उम्मेदवार को पर्याप्त संख्या में अधिक जो 'मत' मिलते हैं वे रह नहीं कर दिये जाते बल्कि दूसरे उम्मेदवारों को वह वोट दिये जाते हैं। उदाहरण के लिये मान लीजिए कि हरिहर नाथ ने जिस उम्मेदवार को अपना मत दिया उसके दस मत पाइले ही मिल चुके हैं मर हरिहरनाथ का मत 'अतिरिक्त' मत गिना जायगा और वह उसके वोटों में जोड़ा जायगा, जिसके नाम पर उसने नन्दर २ लगाया है। अगर उसमें भी आवश्यकता न होगी तो ३, ४, ५ आदि जिसमें भी आवश्यकता समझी जायेगी उन्हीं में जोड़ लिया जायेगा। यह प्रक्रिया उस वक्त तक बराबर चलती रहेगी जब तक कि पूरे मदन्य न चुन लिए जाँय।

दूसरा भेद ALTERNATIVE VOTE

दूसरा भेद इसका यह है कि २, ३, ४ आदि नम्बरों का खयाल छोड़कर जितने अतिरिक्तमत बचते हैं, वे उन उम्मेदवारों को दे दिये जाते हैं जिनकी पर्याप्त संख्या पूरी होने में बहुत थोड़ी कमी रह जाती है।

दोष

इस प्रणाली में एक दोष तो यही है कि इसका उपयोग केवल अप्रत्यक्ष चुनाव में हो सकता है। दूसरा यह है कि यदि मत गिनने और बांटने वाले निष्पत्ति न हुए तो वे मतों को बांटने में काफी गड़बड़ी कर सकते हैं। तीसरी गुराबी यह है कि जो दल अधिक संगठित होगा और अपने मत समझ चुक कर देगा वही इसमें ज्यादा लाभ उठा सकता है। अज्ञान और असंगठित दल बहुमत वाला होकर भी हार गया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिये कि बिहार प्रांतिक कांग्रेस के कुल ६६ प्रतिनिधि हैं। इनमें ४० जमींदार हैं। और बिहार प्रान्त को अखिल भारतीय महासमिति के लिए केवल १२ सदस्य चुनने हैं। उस सूरत में पर्याप्त संख्या ८ होगी। अब मान लीजिये कि जमींदार एका करके अपने मध्य मन अपने ही आदमियों को देता है और दूसरे प्रतिनिधियों से गौण अर्थात् दूसरे-तीसरे आदि नम्बरों के मत अपने आदमियों को दिला देता है तब क्या स्थिति होगी ? इसे हम एक नकशा देकर और भी स्पष्ट करे देते हैं:—

नाम उम्मेदवार बिस्म अपने वोट गौण अपने गौण मन किसे दिये

१ प्रतापसिंह	जमींदार	६	२	२	गोविन्द
२ गिरधरसिंह	"	६	३	२	हरीसिंह
३ रामसिंह	"	६	२	३	गोविन्द
४ हरीसिंह	"	६	४	४	मोहम्मदखाँ

नाम उम्मेदवार किस्म अपने वोट, गौण, अपने गौण मत किसे दिये

५ मोहम्मदगर्ग ४ ३

६ इस्माइलगर्ग " ४ ४

७ गोविन्दप्रसाद " ५ १

नाम उम्मेदवार किस्म अपने वोट गौण अपने गौण वोट किसे दिये
जमोदारगर्ग को, व्यापारी को

१ जीवनलाल काप्रेस ४ ४ ० ०

२ हरस्यरूप " " १ ० ०

३ भोगीलाल " " १ ० ०

४ ग्यामस्यरूप " " १ ० १

५ हरगोविन्द " " १ १ १

६ बशीर " " १ १ १

७ मुमताज " " १ १ १

८ हीरा निमान मभा ५ ३ १ १

९ गोविन्द " ५ ० १ १

३ जग्गा " ५ ० १ १

४ गुलान " ५ १ १ १

१ रामलाल व्यापारी वर्ग ३ ७ X १ व्यापारी

२ चोखेलाल " ० ४ X ० "

३ छोटे लाल " १ ५ X १ ,

४ ग्याप्रसाद " ४ ४ X

इस प्रकार व्यापारी जमोदार वर्ग के ना १० आदमी चुन लिए जायेंगे ग्व काप्रेस और निमानो का बहुमत होने हुए भी ग्व ० ही । प्रतिनिध चुना जायगा । कारण स्पष्ट है । व्यापारी और जमोदार वर्ग के लोगो ने अपने मुख्य और गौण मत 'मत' अपने ही उम्मेदवारों को दिये । परन्तु काप्रेस और निमान मभा वालों ने प्रभाव या मुलाहिजे में आकर अपने मत बांट दिये ।

फल इमका भी बही होता है, जो 'मिगल ट्रास्फरन्स पोर्ट' का।
 हालांकि हार जीत इसमें भी किसी मिद्वान्त या जनता के
 बहुमत पर नहीं, प्रत्युत राजनैतिक बालों पर निर्भर
 करती है। उदाहरण के लिए सन् १९०० ईस्वी में इंग्लैंड के
 मजदूर-दल को पोर्टिंग (मतदान) में ना अल्प मत मिला था,
 परन्तु "होउस आफ कॉमन्स" में बहुमत मिल गया।

इसी प्रकार जब सन् १९१६ ई० में इस पद्धति का प्रयोग
 "नास्ट्रोलिया" की "मीनेट" के चुनाव में किया गया तो उसका
 परिणाम नीचे लिखे अनुसार आया —

	पोट्स	मीट्स
नेशनलिस्ट	८६०१४८	१७
मजदूर और साम्यवादी	८१६८८६	१
रिमान और स्वतंत्र	१७३२४३	०

पाठक देखेंगे कि मजदूर और साम्यवादी दल को भाग्य
 नेशनलिस्ट दल के बराबर ही मत मिले। फिर भी मजदूर और
 साम्यवादियों को मज ही स्थान मिला और नेशनलिस्टों को १७
 मिल गए। कारण स्पष्ट है। नेशनलिस्टों में मज बड़े २ लाख थे।
 उनके मतदानांशों ने अपने दुमरे, तीमरे, चौथे आदि पोर्ट भी
 उम्मीदल प लोग को दिये। परन्तु शीघ्र यों ११ में बहुतों ने
 यहाँ को भी, रुश रखने को अपने पहले याद याद दिये। फलतः
 मजदूरों के पक्ष में मत तो काफी आ गए परन्तु अमेरिका और
 गीण मजदूरों के होने में बेकार हो गए।

इन परिणामों में अन्दाजा लगाया जा सकता है कि ये
 पद्धतियाँ विनीत दूषित और भ्रष्टपूर्ण हैं। फिर अगर मतदानांशों
 और उम्मेदवारों की योग्यता के बन्धनविरोध स्वार्थ लक्ष्मिने स्वयं

गण हों, तब तो कहना ही क्या ? इस अवस्था में तो ये पद्धति का प्रसार के स्थान पर स्राप बन जाती है।

THE CUMULATIVE VOTE (दि क्युमुलैटिव वोट वा मंचित मत)

इस पद्धति का ध्येय अल्पमत को मरणा वा व्यवस्थापिका आ
ध्येय में अपनी प्रधानता का लेने का अवसर देना है। स्मार
देरा में भी बम्बई में इस का प्रयोग किया जा रहा है।

यह केवल जहाँ चुनाव क्षेत्रों में प्रयोग में लाया जा सकता है
व्यावहारिक जहाँ सम्मिलित निर्वाचन प्रथा हो और साथ ही
पद्धति जहाँ एक ही क्षेत्र में कई सदस्य चुने जाते हों।

उदाहरण के लिए मान लीजिये कि बम्बई में ४ सदस्य असेम्बली के लिए चुने जाते हैं। ऐसी दशा में हर एक मतदाता को पांच वोट देने का अधिकार होगा। साथ ही इन चारों को इकट्ठे या अलग २ देने का भी वही अधिकार होगा। अर्थात् यह चाहे तो पांचों में से प्रत्येक को एक एक द दे, चाहे एक ही को पांचो दे दे और चाहे किसी को एक और किसी का दो।

परन्तु इन पद्धति का यदि सामान्य जनता को लाभ मिल
आलोचना सकता है, तो तभी मिल सकता है जब कि चुनाव
जातिगों और धर्मों के आधार पर न होकर, पेशा (धरा)
के आधार पर हो। क्योंकि आज जग २ जाति या धर्म के
आधार पर मतदान या चुनाव होता है उदा इन का फल अच्छा
ही देगा जाता है।

उदाहरण के लिये किमान और मजदूर अगिनि हैं और
इसलिए भिन्न २ सम्प्रदायों की चिन्ता चुपचा मतों में आकर
वे अपने जोर जनमें बांट देने हैं। परन्तु पागलों विविध, न,

एंग्लाइडियन आदि शिक्षित वर्ग स्थिति को समझ कर अपने मजबूत सचित्त बोट किसी एक को या अपने २ एक २ उम्मेदवार को वे देते हैं। वैसी दशा में स्वभावतः बहुमत होते हुए भी किसान मजदूर हार जायेंगे और ये अल्पमत वाले समूह जीत जायेंगे।

धन के प्रलोभन अनुचित प्रमाण आदि भी इस पद्धति पर अमर कर ही सकते हैं। खाम कर भारत जैसे देश में, जहाँ साधारण जनता का मन से बड़ा भाग अज्ञान गर्त में पड़ा है और उसका विरोधी भाग बहुत आगे बढ़ा हुआ है, अतः यह पद्धति औरों में अच्छी होते हुए भी अधिक लाभदायक नहीं हो सकती।

साथ ही इसके लिए चुनाव क्षेत्र भी कारी घंटे २ होने चाहियें। क्योंकि छोटे क्षेत्र में यह दुष्प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दे सकती है। प्रत्येक आदमी के कई वोटस होने और थोड़े ही मत दाना होने से किसी सम्पन्न व्याक्ति में उन्हें रसीद लेने का लालच पैदा हो सकता है।

इस में कुछ और भी दोष हैं। उदाहरण के लिए विचारशील छोटे समूहों को अपनी सफलता के लिए इसमें यथासाध्य कम उम्मेदवार रखे करने या होने देने का प्रयत्न करना पड़ता है, ताकि उनके मत बंटें नहीं। दूसरी ओर प्रतिद्वन्दी किसी न किसी को बढ़ा कर देने का प्रयत्न करते हैं। पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और दलबन्दी को भी इससे काफी प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही कई बार किसी अधिक लोकप्रिय व्यक्ति को आवश्यकता में अधिक मत मिल जाते हैं और इसी कारण कई दूसरे अच्छे उम्मेदवार भी सफलता प्राप्त करते - रह जाते हैं। इस प्रकार एक ओर बहुत से मत व्यर्थ जाते हैं और दूसरी ओर देश कुछ मजबूत सेवा की सेवा में व्यस्त रह जाता है।

कई बार तो प्रतियुद्धों अधिक बढ़ जाने पर किमी भी दल का प्राधान्य नहीं हो पाता और इसका लाभ सरकार उठा लेती है।

फिर अब मे बड़ा दोष यह है कि यह प्रथा घनवानों को अपने दल संगठित करने और भिन्न-प्रलोभनों द्वारा लोगों को गिराने की ओर मजबूत अधिक प्रवृत्त करती है। वे नेगेने-लिस्ट, लिबरल, स्वराजिस्ट आदि भिन्न-भिन्न नामों के नीचे अल्पसंख्यक वाले धे-बड़े, उन संगठित करते हैं और उनके चल पर स्थानीय लोगों के मत का प्रतिनिधित्व नहीं होने देते। नतीजा यह होता है कि प्रत्येक दल को अपना संगठन ऐसा ही करने से घुन मरगा हो जाती है और फिर वे मागारण जनता को भ्रम बनाने के लिए निम्न नए सुझावों का आविष्कार करते रहते हैं।

THE LIMITED VOTE SYSTEM

अथवा

(नियमित मत-दान पद्धति)

इसका ध्येय 'मरित मत-दान पद्धति' के दोषों को कम करना था।

इसका प्रयोग भी वही क्षेत्रों में होता है और यह मरित है।
 व्यवहारिक यहाँ एक ही क्षेत्र में मरितित निर्वाचन द्वारा
 पद्धति कई मतभ्य चुने जाते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक
 मतदान को उस मतभ्य से कम वोट देने का अधिकार होता है, तितने कि उन क्षेत्र में मतभ्य चुने जाते हैं। साथ ही यह उन मतों में से एक उम्मेदवार को केवल एक ही मत दे सकता है, मर दृष्टि वा एक से अधिक नहीं दे सकता।

आलोचना

इसमें सन्देह नहीं कि इस पद्धति के कारण बहुमत सत्र की सत्र जगहों (सीट्स) पर कब्जा नहीं कर सकता। प्रत्येक विचार के लोग किसी न किसी रूप में चुन लिये जाते हैं। किंतु शोष दायों को दूर करने में यह भी असमर्थ है। हाँ, इसमें चुने हुए व्यक्ति को स्वतंत्रता काफी रहती है।

THE PROPORTIONAL REPRESENTATION (सख्यानुपातिक मतदान)

इस पद्धति का ध्येय उपरोक्त सत्र पद्धतियों के दोषों को दूर कर व्यवस्थापिकाओं में सच्चा लोकमत प्रतिबिम्बित ध्येय हो, ऐसी स्थिति पैदा करना था। अब तक यह लोकप्रिय भी पानी है और इसका काफी देशों में प्रयोग हो रहा है।

यह तरीका सच से पहिले सन् १८५५ रूसी में 'डेन्मार्क' में जारी किया गया था। सन् १८५७ में इसे "मि० थॉमस" हर इतिहास ने प्रकाशित किया और सन् १८६१ से 'मि० मिल' भी इसके समर्थक हो गए। फिर भी १६ वीं शताब्दी तक इसे बहुत कम देशों ने अपनाया था। तब तक डेन्मार्क में भी इसका नियन्त्रित प्रयोग ही होता था। किन्तु १८६० ई० के बाद, जब सभी देशों में प्रचलित मतधिकारों के विरुद्ध असन्तोष फैलने लगा तब इसे तेजी से अपनाया जाने लगा। पहले यह स्विट्स केण्डिस में प्रचलित हुआ और फिर बेल्जियम तथा जर्मनी का कुछ रियासतों में। इसके बाद फ्रांस, इंग्लैंड और इटली में इस का प्रयोग हुआ और आजकल यहाँ बंगाल की योरोपियन पार्लियामेन्ट में भी प्रयोग में लाया जा रहा है।

वैसे तो इमरु प्राय ३०० मेरु हैं। क्योंकि प्रत्येक देश की सरकार ने अपने - बड़ा की स्थिति और अपनी मनो-
 व्यावहारिक वृत्ति के अनुसार परिवर्तन पक्किद्धन करके इमरु
 पदसि प्रयोग किया है। परन्तु मूल रूप प्राय सर्वत्र एकमा
 है। अर्थात् इमरु आधार न्याय या वर्ग-विशेष न होकर राजनै
 तिक विचार माने जाते हैं। भिन्न - नामों और ध्येयों वाले
 राजनैतिक व्यक्ति ही इमरु में सम्मेलित रह सकते हैं, किसी
 जातीय दल या वर्ग के प्रतिनिधि हो कर नहीं। उनमें से जोटर
 जिसके विचारों का उचित समझ में मन दे सकता है। प्रत्येक
 मतदाता किसी एक ही सम्मेलित को एक मत दे सकता है।
 साथ ही चुनाव क्षेत्र बड़े - बनाए जाते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में
 कई मतदाता चुने जाते हैं। इमरु प्राय प्रत्येक विचार मण्डली
 वाला वर्ग संगठित रूप से मत देकर अपना एक - प्रतिनिधि
 भेज सकता है। उन्हीं - प्रत्येक मतदाता को सब सम्मेलितों की
 सूची दी जाती है जिस पर वह जिसे पसन्द कर, उसके नाम
 के आगे (+) क्रॉस का चिन्ह बना देता है। उन्हीं प्रत्येक राज
 नैतिक विचार मण्डली के अनुगामी सम्मेलितों के समूहों को मिले
 मत अलग - गिने जाकर उनमें से प्रत्येक दल के अधिक मत के
 भागी सम्मेलित को मफल घोषित कर दिया जाता है। इम
 प्रकार प्राय सब राजनैतिक दलों का शासन में प्रतिनिधित्व हो
 जाता है। सम्मेलित के लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वह
 उन्हीं जिले का रहने वाला हो, उन्हीं से कि वह चुना जायगा।

इम पद्धति की आर योगेपीय देशों के राजनीतिज्ञों का विशेष
 आकर्षण है। हमारे देश के भी कुछ नरमदली नीतिज्ञों
 ने इमकी बड़ी प्रशंसा की है। परन्तु हमें इममें अपनी
 विशेषताएँ नहीं दिखाई देती। न ही यह प्रतिनिधित्व करी जा

मरती है। इसकी विशेषता यह बनाई जाती है कि इससे दलबंदी कम होगी और दूषित प्रलोभनों आदि का मार्ग बन्द होगा।

इसमें मन्देह नहीं कि यह जाति, धर्म आदि के स्थान पर राजनैतिक विचारों को चुनाव का आधार बनाती है और इस आश में आरों से उत्कृष्ट कही जा सकती है। परन्तु इतने ही में तो चुनाव पद्धति के सारे दाप नहीं मिट जाते। उम्मेदवार चाहे किसी जाति या समूह विशेष की तरफ से गढ़ा न हो, मत-दाताओं के ना दल बनाए ही जा सकते हैं और स्वार्थ-वश बनाए जायेंगे। अन्तर इतना ही होगा कि वे जाति या धर्म के नाम पर न बनाए जाकर राजनैतिक विचार के नाम पर बनाए जायेंगे।

एक और दोष भी ध्यान में रखने योग्य है। आजकल की राजनीति सत्य से उतनी ही दूर रहती है, जितना दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। हम दिन रात देखते हैं कि राजनैतिक चुनावों में बहुसंख्यिकता की भरमार रहती है। इस अगाड़े में खेलने वाले अधिकांश खिलाड़ियों का ध्येय, किसी सिद्धांत या विचार-सरणी की विजय की अपेक्षा, अपनी व्यक्तिगत विजय ही अधिक होता है। यही कारण है कि एक व्यक्ति पहले कांग्रेस की ओर से गढ़ा होने की उत्सुक होता है, परन्तु यदि किसी कारणवश उसे उसमें स्थान नहीं मिला तो दूसरे दिन "नेशनलिस्ट पार्टी" में जा घुसता है और फिर वहां भी स्थान न मिला, तो 'लिबरल दल' में दौड़ लगाना दिखाई देता है। इसी तरह अनेक 'नरम-दली' समय २ पर कांग्रेस का लेबल लगा लेते हैं और कितने ही स्वराजिस्ट चुनाव के बाद नरमदल या किसी अन्य दल में जा घुसते हैं।

यही क्यों पिछले दिनों जो कांग्रेस साम्यवादी दल की धूम मची थी, उस समय के साम्यवादी बनने वालों की ही मूर्खी

गुना कर देव्य ली जाय। उनमें कानो मरुता ऐसे लोगों की दिग्गई देगी, जो अरुमर आने पर भास के 'राज्यपीर' की तरह सान्यरादिया को फासी पर लटकाने में मर मे ज्यादा बारी भार ले जायगे।

छोटे क्षेत्र में भी हम मनोवृत्ति के नित्य दृश्य देखे जाते हैं। एक प्रदेशक मनावन धर्म समा में दूट कर आर्यममान में नौकरी मिलते ही कट्टर आर्यममानी बन जाता है और आर्य ममान का एक नेता या आचार्य बनने वाला व्यक्ति, घर में कट्टर मनावनी के उदाहर दूतद्धाव गवना दिग्गई देता है।

ऐसी स्थिति में केवल राजनैतिक विचारों के आधार पर व्यवहार होने के कारण जनता किर्मी का अधिक दिन विग्राम करती जाय, और मात्र ही खडा होने वाला व्यक्ति गान्ध में पैना ही प्राचरण करेगा, जैसा कि बर कहता है, ऐसा निश्चय किमी कर होना अशक्य मा है। फिर जन हम आधार पर चुनाव क्षेत्र ग पिले में यात्रा का व्यक्ति भी गड़ा हो सके, नर तो हम गान्ध में पचने के मावन जनता के निरे और भी कम ग जाते हैं। व्यक्ति अपने मामले ग गाम-गाम रहने वाले लोगों में वा प्रत्येक व्यक्ति परिचित होता है। वे यदि अपने विचारों का कृत्रिम जामा पहना कर जनता को धान्य देना चाहें, तो बर पने पहचान ग मरुती है। परन्तु यदि गड़ा होने वाला व्यक्ति दूरस्थ अचल ग है, तो हमके बारे में सुनी सुनाई जाता पर निर्भर रहनेके अतिरिक्त मनुष्या के लिये और कोई मार्ग हो नहीं रद जाता।

रहा सुने हुए ज्ञान का, मो न्मदी स्थिति स्पष्ट है। आज प्रचार द्वारा कौन मे दैत्य पैना नहीं बनाए जाते और कौन मे देवता गान्धों की श्रेणी में नहीं बिठा दिये जाते ? इमी स्थिति की बदौलत मुमोल्नि और टिटलर कोहों के देवता भन

हुए हैं या नहीं ? और आज हमारे देश के चुनावों में क्या होता है ? क्या अपने अपने उम्मीदवारों के मन्त्रे गुण दोष उनके वृष्ट पोषको द्वारा जनता के सामने जथा के त्याग रखे जाते हैं ?

इसके अतिरिक्त जिनकी बुराइयों के लिये दूसरी चुनाव पद्धतियों में गुच्छाहरा है, उतनीही केलिये इसमें भी है। इसमें भी बुद्धिशील दल, प्रगट रूप से दल के नाम पर न मन्त्री, अप्रत्यक्ष रूप अपने आदमियों को रखे कर सकते हैं। प्रचार द्वारा उन्हें देना का स्थान दे सकते हैं, चोट मरीद सकते हैं और अन्य प्रभागों का उपयोग भी कर सकते हैं।

रहा राजनैतिक विचारों के आधार का प्रश्न, तो अवरय ही यह सम्प्रदायवाद से एक मोमा तर राजनीति को मुक्त करता है, परन्तु बुराई की जड़ तक उमरी भी पहुँच नहीं होती। क्योंकि आज जिन देशों में सम्प्रदायवाद राजनैतिक इन्द्रो का आधार नहीं है, वहाँ भी तो इससे कोई मौलिक लाभ नहीं हुआ है। उन देशों में भी और हमारे देश में भी राजनैतिक दल हैं ही। लिबरल, इण्डिपेण्डेन्स, नेशनलिस्ट, स्वराजिस्ट, रिस्पॉन्सिबलिस्ट, मसदूर दली—सब राजनैतिक दल ही तो हैं। परन्तु इनके व्यावहारिक कार्यों में साधारण जनता के व्यापक हितों की दृष्टि से क्या अन्तर होता है ? यदि उनके कार्यों के गतों की जाँच की जाय तो पता लगेगा कि व्यावहारिक रूप में उन सब के द्वारा केवल उच्च वर्ग को ही सर्वाधिक लाभ पहुँचा है और अशिक्षित जनता को वास्तविक राजनैतिक ज्ञान से वञ्चित करने के पक्ष्यन्त्र में वे सब एक हैं। अब मि० Renouvier का यह मतना ठीक ही है कि “इस पद्धति की उदीलत नण-नण राजनैतिक दल और उन के द्वारा जनता को धोमे में डालने वाले नण-नण मिद्धांत पाश्यही चढ़ेंगे। परिणाम में विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा !”

फिर आखिर चुनाव का ध्येय क्या है ? 'बर्नार्डशा' केंशब्दों में कहें तो "जनमत्ता न्यापित करने की पहली सीढ़ी व्यवस्था-पिकाओं में सब समूहों के हितां का उनकी मंन्त्र्या के अनुमाग प्रतिनिधित्व है ।" समूह का हित बाल्स्व में उनके आर्थिक हित के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? मालियों और कुँजड़ा के समूहों का सम्मिलित और सबसे बड़ा हित उनके अपने व्यवसाय की उन्नति एवं उसे मंरक्षर मिलना है और यह किमी निवरल या डेमोक्रेट के द्वारा नहीं हो सकता ।

आखिर एस्तंत्री मत्ता दुनियाँ में क्यों उठाई जा रही है ? डर्मीलिये न, कि वह शामन द्वारा सब समूहों के हितां की रक्षा नहीं कर सकती । यह उनके लिये है भी अशक्य ? प्रत्येक समूह अपने लिये आवश्यक और व्यावहारिक मंरक्षर स्वयं ही अधिक जान सकता है । एक पंसागी यह नहीं जान सकता कि बर्कीलों एवं बकालत की उन्नति के लिए किन-किन बातों की आवश्यकता है ?

ऐसी अवस्था में यदि हम पद्धति में जनता का कुछ नात्विक लाभ हो सकता है, तो तभी, जबकि चुनाव और प्रतिनिधित्व का आपार राजनैतिक विचारों में पहले विभिन्न धन्वों और पेशों को बनाया जाय ।

बाल्स्व में लोगों में मशी राजनैतिक बुद्धि और राष्ट्रीयता जागत करने का उपाय यही है । चूँकि किमी भी धन्वे को किमी एक ही जाति या धर्म के मानने वाले व्यक्ति नहीं करते । अतः एक धंधा करने वाले विभिन्न धन्वों और जातियों के लोगों को अपने न्यार्थ के लिए ही, ऐसा होने पर अपना एक समूह बना लेना पड़ेगा और धीरे धीरे अन्य समान हित रखने वाले समूहों में मिल कर बड़ी एक विशेष राजनैतिक विचार मगगी जाने ढल में परिणत हो जायगा । और चूँकि इस प्रकार बने हुए राजनैतिक दलों का विकास वैज्ञानिक होगा, अतः उमें धोम-धडी की गुञ्जायश प्रायः मर्बया नगर्य हो जायगी ।

जनता की सत्ता

जनता की सत्ता

जनता की सत्ता



उपर के अध्यायों में दिये विवेचन में पाठक समझ गये होंगे कि आधुनिक चुनाव पद्धतियाँ के दोषों का प्रश्न उसके जन्म काल में ही उपस्थित रहा है। उन्हें दूर करने के प्रयत्न भी होते रहे हैं, परन्तु सफलता बहुत कम मिली है।

कारण स्पष्ट है। एक ओर जनसत्ता की भावना प्रबल होती जा रही है। साधारण से माधारण जन समूहों में यह विचार पहुँच चुका है कि शासन-यन्त्र उनकी वस्तु है। और आज तो शासक भी इस बात को मानने लगे हैं। कहना व्यर्थ है कि उनकी यह मान्यता, उन सारों बलिदानों का ही फल है, जो प्रत्येक देश में स्वाधीनता के सघे पुजारी युवकों ने किये हैं। परन्तु जिन समूहों और व्यक्तियों में राज्य-सत्ता का मोह गहरी जड़ पकड़ चुका है, वे केवल स्थिति से विरश होकर ही इसे मानने लगे हैं। हृदय से वे अभी अपनी वर्तमान स्थिति को बदलने के लिये तैयार नहीं हैं। इसीलिए जिस प्रकार विरश होकर धीरे-धीरे हजारों वर्षों में, चींटी की चाल से—आगे बढ़ते हुए उन्होंने इस जनसत्ता के सिद्धान्त को स्वीकार किया है, उम्मी विरशता और उम्मी धीमी गति के साथ वे उम ओर आगे पैर धकाते हैं।

दुमरी ओर समाज में आर्थिक भेदभाव इतना अधिक बढ़ गया है, ज्ञान का बटवारा इतनी अममानता के साथ हो चुका है और शक्ति के पलड़े इतने हल्के एवं भारी हो गये हैं कि इन मध्व बातों के बीच के अन्तर को आज सामञ्जस्य पर लाना एक असाध्य कार्य है। सामञ्जस्य पर लाने की चेष्टा भी नहीं होती। जिम ओर से होती है, उस ओर ज्ञान, धन, शक्ति, संगठन मध्व का अभाव माहै। जियर से नहीं होती और उसका विरोध किया जाता है उधर ज्ञान, शक्ति, साधन, अर्थ और संगठन आदि मध्वकुछ हैं। इसी लिये चेष्टा यह की जा रही है कि मध्व अपने अपने स्थान पर जैसे हैं, वैसे ही बने रहें और साथ ही जनमत्ता का नाटक भी पूरा कर दिया जाय। भेड़िया, भेड़िया ही बना रहे और बकरी, बकरी ही, परन्तु फिर भी दोनों साथ साथ रह सकें और एक-दुसरे को हानि न पहुँचावें।

परन्तु यह असाध्य-साधन की चेष्टा है। भेड़िया जब तक घाम खाना न मीसे और बकरी को अमर्त्य न मान ले, जब तक उनका साथ किसी 'भरकम' में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं।

हां, भेड़ियों के बच्चे निरामिष भोजी बनाए जा सकते हैं। आखिर अपनी प्राकृत अवस्था में कुत्ते, बिल्ली आदि भी तो आमिष भोजी ही थे। परन्तु वे बनाए जा सकते हैं नमी, जब वे वैसी ही स्थिति में पैदा हों और पोषित किये जायें। और वह स्थिति तब ही आ सकती है, जब कि एक बार शासन बकरीयों के हाथों में आ जाय। आखिर बौद्ध लोग भी अनेक आमिष-भोजी मनुष्यों को तब ही निरामिष भोजी बना सके थे, जब शासन-यन्त्र उनके हाथ में आगया था।

ऐसी दशा में उपरोक्त मनोवृत्ति को मामने रखते हुए याम्नि-विक्रम जनमत्ता का भवज देखना तो मृग-मरीचिका में प्याम

मुक्ताने की चेष्टा करना है। हा अधिक मे अधिक, जन-सत्ता का मार्ग कुछ परिष्कृत करने और साथ ही भेदियों को भी प्राति द्वारा नष्ट करने की नौतव कुछ दिना और न आने देने के लिये शासन यन्त्र को एक 'सरकस' की शक्ल दी जा सकती है। इससे दाना को लाभ हो सकता है। एक बार दिन रात अपनी अपनी स्थिति के लिये जो सघर्ष हो रहा है और जिम्मेकी बदौलत ही ये सारे सुधार विफल होते जा रहे हैं, उसमें बहुत कुछ कमी आ जायगी और दूसरी ओर शासक गण सम्पन्न वर्ग की आयु भी काफी बढ़ जायगी। यही क्या, मौन क स्वतंत्र में वे चाहें या ना जायेंगे।

जनसत्ता और प्रतिनिधि सत्ता

फिन्तु इस प्रश्न पर विचार करने के पहले हमें जनसत्ता और प्रतिनिधि सत्ता के बीच के भेद को समझ लेना चाहिए। बहुतों लोग अंग्रेजी के शब्द Democracy और वर्तमान प्रतिनिधि सत्तात्मक (जिनमें जिस दल का बहुमत हो, उसके हाथ में शासन रहता है) प्रजातन्त्र, निन्द Oligarchy भी कहते हैं, का एक ही रूप मानते और बताने लगते हैं। परन्तु यह भूल है। डेमोनेसी शब्द यूनानी भाषा में अंग्रेजी में आया है और इसका वास्तविक अर्थ है जन माधारण-गरीबों के प्रबल बहुमत का शासन। यूनानी भाषा में Demos शब्द का वही अर्थ है, जो अंग्रेजी में Masses (मामेस) शब्द का है। आज हम उसका अर्थ अधिक में अधिक सींचतान कर दें, तो गरीब अमीर मयका सम्मिलित-शासन कर सकते हैं।

ऐसी दशा में 'डेमोनेसी' शब्द तभी चरितार्थ होता है, जब कि शासन विधान को कम से कम अगोश अन्तर्गत में माधारण जनता हो।

असमानताओं का संघर्ष

इन बातों के साथ एक और बात ध्यान में रखने योग्य है। यह यह कि यद्यपि आजकल के मुख्य समारोह भावना की समानता को मान लिया है। वह मानता है कि जनता चाहे शिष्ट हो वा अशिष्ट, वह राज्य सत्ता की जननी और स्वामिनी है। इसी लिये अनेक देशों में सर्वसाधारण को, जिसमें सब से अधिक भाग अशिष्ट जनता का होता है, शासन करने वाले और शासन रख के लिए विधान बनाने वाले व्यक्ति चुनने का अधिकार दे दिया गया है। अर्थात् उद्मान लिया गया है कि एक अशिष्ट नागरिक भी शासकों को चुनने के लिये अपना ही योग्य है, जिसका कि एक अशिष्ट शिष्ट। इस प्रकार इस मामले में सब का समान दरजा है।

परन्तु व्यावहारिक अर्थान् साम्यचिन्त वा आर्थिक समानता को ध्यान देने और स्वीकार करने में हम उगड़ आनाकाहनी की जा रही हैं। इस में सन्देह नहीं कि इस बात की न्याय्यता किसी युक्ति से सिद्ध नहीं की जा सकती। जनता ने चुनावों पर दिये अपने फैसलों के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया है कि हममें विवेक पूर्वक राय और चुनाव करने की योग्यता है। इस प्रकार हमने शासकों को कुछ गलतियों वाले भी जाने वालों उन गलतियों को संस्था गान्धी मानित कर दिया है कि शासन सन्धियों लोगों की बुद्धि और योग्यता केवल शासक वर्ग में ही होती है। ऐसा दृष्टा में, जो व्यक्ति योग्य शासक या कानून बनाने वाला चुन सकता है या Referendum में इनका के दाय या गलत होने का फैसला दे सकता है, वह शासन और कानून बनाने के लिए अयोग्य कैसे ठहरा जा सकता है। यह वास्तव में

तर्ज का मञ्चाक उढ़ाना है कि एक आदमी जिस विषय पर मत देने को योग्य है, उसी को स्वयं करने में अयोग्य है।

इसके अतिरिक्त मनुष्य में समानता की भावना सब में प्रमुख है। एक शताब्दी में अधिक समय हुआ जो Tocqueville ने कहा था कि "मनुष्य को स्वतन्त्रता से भी समानता अधिक प्रिय है, इसलिए यदि मनुष्य की इस भावना को सन्तुष्ट कर दिया जाय, तो शान्तिपूर्वक एक ऐसे राष्ट्र के बने रहने की कल्पना ही जा सकती है, जिसमें साम्प्रतिक समानता अधिक दूर तक न हो।"

REFRENDUM अर्थात्

(क़ूननों पर लोकमत लेने की पद्धति)

जनता की अन्तिम स्वीकृति



उस समय की यह मनस्थिति मनुष्य में आज भी मौजूद है। यद्यपि वास्तव में बिना साम्प्रतिक समानता के राजनैतिक वा सामाजिक समानता का विशेष मूल्य नहीं होता। फिर भी हम देखते हैं कि जहाँ मनुष्य के शासन में समानता मिल जाती है, वहाँ वह साम्प्रतिक असमानता के अन्याय को भी काफी सह लेता है। स्विट्जरलैंड आदि देशों में यही नुस्खा यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के लिए अगोप्य कचरा का काम कर रहा है। इसी प्रकार प्रायः शासन में समानता मिलने के कारण ही, हम देखते हैं कि, उन लोगों के भाग भी शासन समूह के साथ मिल कर एक हो जाते हैं, जिन्हें राजनैतिक समानता प्राप्त नहीं होती। इसी अस्त्र का उपयोग कर सत्तावादी समाज में नित्य नए दल गढ़े करते रहते हैं।

इस प्रकार व्यावहारिक जीवन नियमों से स्पष्ट है कि प्रवाह में यहकर, या कृत्रिम उपायों से पैदा किये सत्कार के यहीभूत

कुछ बातों से मनुष्य भले ही स्वतंत्रता, उम्र आदि को सर्वोपरि मानता रहे और समानता के प्रश्न से दूररे दूर पर खड़ा रहे, परन्तु व्यवहार में, उसमें समानता की आकांक्षा और भावना ही मरने से प्रबल होती है।

फिर जब, जिन लोगों को मताधिकार दिया गया है, उन ही की पसन्द के प्रतिनिधि व्यवस्थापिकाओं में लेने की न्याय्यता स्वीकार कर ली गई है, तब सम्मेलनवादी की योग्यता-निरोधन साम्प्रतिक योग्यता-नियन करने का न्याय्य अर्थ? मतदान में यह क्यों फटा जाय कि यह असुख प्रेणी के या इन्कमटैक्स देने वाले व्यक्तियों में से ही रिम्मी को चुन करना है। गिना और इन्कमटैक्स या सम्पत्ति का तो कुछ अविच्छेद सम्बन्ध है ही नहीं। एक धनपति महामुर्ख हो सकता है और एक दरिद्र अन्धे से अच्छा जन मेवक। फिर यदि मतदान एक दरिद्र या अपने समूह के किसी गरीब को ही अपना प्रतिनिधि चुनना चाह, तो हमकी उन्हें स्वतंत्रता क्यों न हो?

परन्तु जैसा कि हम उता चुके हैं, इन अधिकारों को रोड भी मत्ता प्रमत्तता में नहीं दे रहे हैं। इसी लिए भिन्न भिन्न स्पास में प्रयत्न यह किया जाता है कि मताधिकार जनता से भी दिया जाय और व्यक्ति भी ऐसे चुनने लिये जाय, जो सर्वथा जनता की पसन्द के या उसके उम्र के न हों। इस का परिणाम स्वभावतः यही होता रहा है कि व्यवस्थापिकाओं में जो प्रतिनिधि पहुँचते थे और पहुँचते हैं, उनमें बहुत कम ऐसे होते थे जो काम करने हैं। वे प्रायः एक बार चुन लिये जाने के बाद अपने मर दूकानों और जनता के लिये हुए कार्यक्रमों को भूल जाते हैं। उनका ही नहीं, उदाहरण में, धनियों में रिजलन

ले ले कर उनके अनुकूल कानून बना देते । और फिर नैतिकता की सीमा भंग होने पर ता उस के विकास की सीमा नहीं रहती । मनुष्य विचारों का पुतला है ही । अतः एक की देखा देखा दूसरे में यह छूत का रोग बड़ी तीव्र गति से फैलता है ।

उधर जय व्यवस्थापिकाओं की आयु समाप्त होने पर आती, तब आलाक प्रतिनिधि लोग जनता के हित का कोई न कोई ऐसा प्रश्न उठा लेते, जिसे वैयक्तिक सरकार स्वीकार न करती ।

यस इसी का वे घण्टा बजा देना डालते । और साधारण जनता की स्मरण-शक्ति तो ऐसे ही क्षणस्थायी होती है, अतः वह भी थोड़ा आन्दोलन होते ही वायुमण्डल के प्रवाह में बह निकलती । वह उन्हीं धोखेबाज प्रतिनिधियों को सच्चे हित मान बैठती और फिर उनकी प्रशंसा करने लगती ।

दूसरी ओर, और सदस्य लोग ऐसे ही किसी प्रश्न का लेकर एक दल बना लेते । घोषणाएं करते कि इस घाट हम बहुमत बना कर इसी बात को स्वीकृत करारेंगे । जनता से अपील करते कि यस इसी दल के सदस्यों को चुनना ताकि सरकार समझ ले कि जनता अमुक कानून या सुधार के पक्ष में थी । भिन्न भिन्न प्रचार माधनों द्वारा इसके लिए जनता को उत्तेजित किया जाता । फल यह होता कि जनता फिर भुलाने में आ जाती और ये लोग फिर चुन लिये जाते । शताब्दियों से प्रतिनिधि मस्थाओं में यही खेल होता रहा है और आज भी अनेक देशों में होता है ।

इस प्रकार व्यवस्थापिका सभाओं वदाचित ही लोकमत का साथ प्रतिनिधित्व प्रमाणित होती । इसी लिये अन्त में जनता के कुछ सच्चे प्रतिनिधियों ने यह आन्दोलन शुरू किया कि व्यवस्थापिका के स्वीकृत कानूनों पर अन्तिम निर्णय लोकमत द्वारा लिया जाना चाहिये ।

इस आन्दोलन का जन्म आधुनिक युग में मनु से पहले 'स्विटजरलैंड' में हुआ। उद्योग जनता में व्यवस्थापिकाओं के प्रति योग्य अविश्वास उत्पन्न हो ही चुका था, अतः यह आन्दोलन बहुत जल्दी प्रचलित बन गया और अन्त में मन् १६१८ ई० में वहाँ नियन्त्रित रूप में "रिफ़ोरेण्डम्" की पद्धति प्रचलित हो गई।

मन् १८१६ में इस पद्धति का रूप भी वैसा ही संकुचित था, जैसा आरम्भ में और सुधारों का रहता आया इतिहास है। अर्थात् व्यवस्थापिका जिस कानून पर लोकमत लेना आवश्यक समझती, उसी पर लोकमत लिया जाता था, औरों पर नहीं।

इसका परिणाम वही हुआ जो हो सकता था। अर्थात् व्यवस्थापिका ऐसी ही कानूनों पर लोकमत लेती, जिन पर उममें और गवर्नर में मतभेद होना और जिनके लिए उन्हें गवर्नर के अमन्तोप की बला अपने मिर से जनता के मिर पर डालनी होती अथवा जिन पर तीव्र मतभेद होने के कारण यह आशंका होती कि कुछ सदस्य इस प्रश्न को जनता के सामने उठावेंगे। ऐसी अवस्था में स्वभावतः इससे जनता की यह आशंका पूर्ण नहीं हुई जिसे पूरी करने को उमने इसे स्वीकार कराया था। राजनैतिक चालों ने इसके रूप को निरुपयोगी बना दिया।

अन्त में इस संकुचितता के विरुद्ध आन्दोलन शुरू हुआ। जनता ने "रिफ़ोरेण्डम्" को व्यापक बनाने पर जोर देना शुरू किया और कहा कि रिफ़ोरेण्डम् की मांग करने का अधिकार जनता के हाथ में होना चाहिये। उसे हक होना चाहिये कि वह वरिष्ठ सत्ता की तरह जिस कानून को चाहे अपनी राय के लिये पेश करने की आज्ञा व्यवस्थापिका को दे सके।

फल यह हुआ कि क्रमशः शासन को अपना शिक्का ठोका करना पड़ा एवं भिन्न भिन्न देशों और राज्यों में कुछ परिवर्तन के साथ यह अधिकार जनता को मिल गया। उनमें से कुछ उदाहरण पाठक की जानकारी के लिये यहाँ दिये जाते हैं

अमेरिका—के कुछ राज्यों में व्यवस्थापिका और भ्रजा दोनों को “रिफ़रेंडम्” का आह्वान करने का अधिकार है। अर्थात् व्यवस्थापिका तो जिस कानून या उसके अंश पर लोकमत लेना चाहे, ले ही सकती है, परन्तु जनता में से भी किसी राज्य में से ४०००, किसी में से ३००० (जैसा जहाँ नियम है) मतदाता मिलकर चाहे जिस कानून के बारे में “रिफ़रेंडम्” की माग कर सकते हैं। कुछ राज्यों में (जैसे Lug St Gall etc) व्यवस्थापिका के अल्पमत को भी “रिफ़रेंडम्” की माग करने का अधिकार होता है। यहाँ यदि एक तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षरों से माग की जाय, तो सरकार को उसे मानना ही पड़ता है।

जर्मनी—में मतदाताओं की माग पर भी रिफ़रेंडम् लिया जाता था और यदि दोनों व्यवस्थापिकाओं में किसी कानून पर मतभेद खड़ा हो जाता, अथवा पेंडेशन के प्रेसिडेंट का उससे मतभेद होता, तो वह भी स्वेच्छा से ऐसा कर सकता था। इस प्रकार जनता का माग हुआ “रिफ़रेंडम्” “Referendum ordered by the Petition of the people” (जनता के आवेदन पत्र द्वारा आदेशित रिफ़रेंडम्) कहलाता है, और प्रेसिडेंट द्वारा निश्चित किया हुआ Referendum called by the president” (समापति द्वारा आहूत रिफ़रेंडम्) कहलाता है।

“आर्थिक रिफ़ारेण्डम्”

यह हमका दूसरा भेद है। इसके अनुसार व्यवस्थापिकाओं की वजत, खर्च, कर्ज आदि मंजूर करने की शक्ति नियन्त्रित कर दी जाती है। उदाहरण के लिये Aargau Canton में दस लाख फ़्रांक में अधिक का कर्ज बिना जनता की स्वीकृति के न तो सरकार ले सकती है, न व्यवस्थापिकाएँ स्वीकार कर सकती हैं। इसी प्रकार कहीं-कहीं वजत की सीमा यँची हुई है। बससे अधिक किमी वर्ष में खर्च करना हो, तो वह जनता में स्वीकृति लिए बिना नहीं किया जा सकता। Berne Canton में तो वजत भी प्रति वर्ष उक्त पद्धति द्वारा जनता में मंजूर कराना पड़ता है।

“रिफ़ारेण्डम्” की दृष्ट्यात्म पर भिन्न २ देशों व राज्यों में नीचे दिये हुए क्रम में मनत्राताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने पड़ते हैं:—

जर्मनी	५०	मिडजरलैंड	३००००
अमेरिका के राज्य:—		स्विम कैण्डम्:—	
अर्कंसाम	५०	वमले	१०००
कैलिफ़ोर्निया	५०	जेनेरा	३५००
कोलोरेडो	५०	ल्युसैरने	४०००
मैन आर मेरीलैण्ड	} १००००	न्युशतल	३०००
मिमीरी		मैण्ड गान	४०००
मोएटना	५०	वॉट	६०००
नेब्रास्का	१०	अग	४००
विस्कॉन्सिन	१०		
वयोमिंग	२५०		

ग्राम तौर पर बड़े प्रान्तों या राज्या में प्रतिशत और ट्राटे जिलों में १०% से लगा कर २५% तक मतदाताओं के हस्ताक्षर हाने का नियम है।

इन मन पद्धतियाँ की उद्दीष्ट यह है कि लोग भारी टैक्सा व वाक से बहुत कुछ बच गए हैं। उन वहाँ की सरकारों का भी और व्यवस्थापिकाओं का भी खर्च करने में काफी मायधानी रखनी पड़ती है। यही नहीं, इसके फल में राजनैतिक धूमधोरा भी द्वार बहुत कुछ बन्द हो गए हैं।

THE ADVISORY REFERENDUM

ऐडवाइजरी रीफरेंडम

यह इसका तीसरा भेद है। यह कुछ अनुभव के माध्यम प्रचलित किया गया है। जिस गानून पर जनता में तीव्र मतभेद होने की सम्भावना होती है अथवा जिसके लिये यह आशा की जाती है कि इस पर *Isoterendum* की मांग की जायगी तो व्यवस्थापिका पहले ही उसमें मुख्य मिथ्यान्त आदि पर लोकमत ले लेती है। जब यह स्वीकृत हो जाता है, तब अपने आधार पर कानून बनाया जाता है।

आस्ट्रेलिया की विशेषता

आस्ट्रेलिया में भी रीफरेंडम का पद्धति प्रचलित है। किन्तु यहाँ सार्वजनिक मताधिकार नहीं है। रीफरेंडम भी सन कानूनों पर नहीं लिया जाता। हाँ, व्यवस्थापिका के प्रतिनिधियों की सत्या घटाने उद्देश्य वाले, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने वाले और शासन-विधान को बदलने वाले कानूनों पर रीफरेंडम लिया जाता अनिवार्य रक्खा गया है।

शेष कानूनों में जितने संशोधन होते हैं, वे व्यवस्थापिकाओं में स्वीकृत होने के बाद व्यवस्थापिकाओं को चुनने वाले मतदाताओं के सामने अन्तिम स्वीकृति के लिये रखे जाते हैं।

मारी जनता या म्यूनिमिपैलिटी नया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आवि के मतदाताओं को इन पर मन देने का अधिकार नहीं होता ।

हाँ, यदि कोई मंशोधन एक व्यवस्थापिका में दो बार स्वीकृत हो जाय और फिर भी दूसरी व्यवस्थापिका मद्मन न हो, तो उस पर सार्वजनिक लोकमत लिया जाता है ।

यदि प्रत्येक राज्य का बहुमत और मारे देश का सम्मिलित बहुमत—दोनों उनके पक्ष में हों तो वह कानून बन जाता है और तबतक जनरल के पास शाही मंजूरी प्राप्त करने के लिये भेज दिया जाता है । Parliamentary papers cd. 5778 & 5780 (2) Federal & United Constitutions, By A.P Newton P 357.

परन्तु यह ध्यान में रखने योग्य है कि Referendum की पद्धति को केवल संघ-प्रजातंत्रों (Federated states or Republics) ने ही अपनाया है । स्विटजरलैंड, अमेरिका, और आस्ट्रेलिया ही अब इसके प्रधान क्षेत्र हैं । जहाँ नियंत्रित राज्यमत्ता या दलगत शासन की प्रजातंत्र के नाम पर प्रधानता है, वहाँ इस पद्धति को स्थान नहीं मिल रहा है । कारण कि ऐसी मत्ताएँ अभी लोकमत से शासित होने के दिन तो जहाँ तक हो सके टालना चाहती हैं । फल यह है कि उन ही में मरमे अधिक अमन्तोष भी दिखाई देता है ।

इसका एक मुख्य कारण और भी है । संघ में प्रत्येक राज्य अपनी स्वतंत्रता कायम रखने को उन्मुख रहता है साथ ही वह अपने शासन को किसी सार्थी राज्य से कम उन्नत भी नहीं रखना चाहता । इसके विपरीत जिस प्रकार दो नाटक मंडलियाँ जब प्रतिस्पर्धा करती हैं, तब प्रत्येक दूम्गी में अच्छा नाटक खेल कर जनता को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, उम्मी

प्रकार इनमें से प्रत्येक राज्य उद्योगधन्यों में पूँजी लगाने वाले और भूमि की उर्वरता बढ़ाने वाले जनसमूहों को आकर्षित करने के लिये अपने राज्य में अधिक सुविधाएँ बढ़ाने को उत्सुक रहता है।

सीसरा कारण इनका व्यापारिक एवं अन्य सब प्रकार का दिन रात का सम्बन्ध है। एक समान और देश भर के लाजमत के समर्थन से बने हुए श्रानूनां द्वारा शासित होने के कारण प्रत्येक राज्य की जनता उन्हें अपने ही समझती है। इस प्रकार अलग अलग राज्य होने पर भी उनमें ऐक्य एवं एक-राष्ट्रीयता की भावना बनी रहती है।

एक और सब में बड़ा लाभ इस पद्धति का इन राज्यों को यह है कि वे छोटे हों चाहे बड़े, अपनी रक्षा के प्रश्न से निश्चिन्न रहते हैं, क्योंकि मारे देश की जनता स्वयं उनकी रक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार रहती है। स्वेच्छाचारी राज्यों की प्रजा की तरफ़ वह यह नहीं मोचती कि —

कोउ नृप होय हमे का फानी।

चेरी छौंड़ि न होउय रानी ॥

यह तो स्वयं अपने को राज्य की शासन और इसलिये उसरी रक्षार्थ जिम्मेदार मानती है। यह 'रिट्रैरेण्टम्' का ही प्रभाव है कि संसार में चारा ओर प्रातियां और असतोष का घोलनाला होते हुए भी स्विट्जरलैण्ड, अमेरिका आदि में जहाँ जितना इस पद्धति का विकास है, वहाँ उतना ही अधिक शांति एवं मन्तोष का साम्राज्य है। यद्यपि वहाँ साम्यवादा शासन नहीं है, व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने की भी प्रथा है, फिर भी वहाँ न इतना अमन्तोष है न इतना कष्टपूर्ण और दमि

जीवन। 'गिकैरेएडम्' का अंकुश दोनों ही वर्गों को अपना-अपनी भीमा में रग्वना है।

यही क्यों, वह प्रत्येक मंच के सदन्य राज्य को भी दूसरे राज्य पर कुछछि टानने में रोक्ने की मज में बड़ी मशीन है। देश भर की जनता से म्यौकृत होने के कारण कोई बड़े से बड़ा राज्य भी छोटे से छोटे राज्य के विधान की अपेक्षा नहीं कर सकता। इसे भी मज अपने बराबर का मानने का बाध्य है।

इसके साथ ही जिन देशों में Referendum की पद्धति जारी है, वहाँ कभी गामन-यन्त्र के बेचार होने की नाँवत नहीं आती। यदि व्यवस्थापिकाओं में मतभेद हो तो जनता निर्णय दे देती है। इसी लिए इङ्ग्लैंड की जनता में भी इसके लिये आन्दोलन शुरू है। फ्रांस और इटली में तो इसका प्रयोग भी होने लगा है।

इस पद्धति के सम्यन्त्र में मेटगाल के विधान में कहे गये शब्द स्वर्णितों से लिखे जाने योग्य हैं। कहा गया है कि:—

“परिष्टु सत्ता, जो सब राजनैतिक अधिकारों की चानक-शक्ति है, मार नागरिकों की मन्यत्ति है और इसलिये जनता का अधिकार है कि वह चाहे जिस कानून को स्वीकार करे और चाहे जिस कानून को अस्वीकार कर इसका प्रयोग में आना रोक् दे” (Deploige P. 71)

ए. ए. ए. ए. ए.

सफलता की कुञ्जी

ब. ए. ए. ए. ए.

सफलता की कुंजी



यह आज योरोप में भी सर्वमान्य बात है कि "रिक्रैरेण्डम" की पद्धति जनमत्ता, के भिन्न-भिन्न अङ्गों और जनता की स्वाधीनता एवं समानता की आकांक्षा को पूर्ण करने का सर्वप्रधान साधन है, परन्तु साथ ही इसकी सफलता बहुत कुछ इसके प्रयोग की उदारता पर है। संकीर्णता के साथ इसका प्रयोग विरोध लाभप्रद तो होता ही नहीं, हानिकारक भी हो सकता है।

आपत्तियाँ

कहना व्यर्थ है कि जब इस पद्धति का आविष्कार हुआ, तब इसके विरुद्ध काफ़ी आपत्तियाँ उठाई गई थीं। आज भी जो देश इसे प्रचलित नहीं करना चाहते, वे अनेक आपत्तियाँ उठाते हैं। और चूंकि पाठक, उन्हें सामने रखकर इस पद्धति की उपयोगिता अनुपयोगिता के सम्बन्ध में अधिक विचारपूर्ण निर्णय पर पहुँच सकते हैं, अतः हम उनमें से मुख्य-मुख्य यहाँ दे रहे हैं। वे इस प्रकार हैं—

- १—व्यवस्थापिका के सदस्यों को अपनी जिम्मेदारी टालने में प्रोत्साहन मिलना है।
- २—रिक्रैरेण्डम से व्यवस्थापिका सभाओं की शक्ति कम हो जाती है।

३—जनता को उभार कर चालाक लोग अवांछनीय और भयंकर कानून भी बनवा सकते हैं ।

४—यह चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता के गुलाम बनाता है ।

५—जनता कानूनों को मममत्ते और उन पर मत देने के योग्य नहीं होती ।

६—यह शिक्षितों के कार्य का फैसला अशिक्षितों से कराने के समान है ।

७—‘रिफ़ॉरेण्डम’ में बहुत कम मतदाता भाग लेते हैं ।

८—साधारण जनता भूल कर सकती है, परन्तु चुने हुए विशेषज्ञ प्रतिनिधि भूल नहीं कर सकते ।

९—यह शासन में किसी एक दल की प्रधानता नहीं होने देती और इसलिये उन्नति की घातक है ।

१०—जनता टैक्स बढ़ाने के डर से बड़े-बड़े काम करने की मंजूरी नहीं देती और इसलिए देश उन्नति नहीं कर सकता ।

११—यह पद्धति प्रतिनिधि-शासन की नाशक है ।

पाठक देखेंगे कि इन आपत्तियों में १, २, ४, ५, ८, ९ और ११ प्रायः एक ही आशय को भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट करने वाली हैं । अर्थात् प्रतिनिधि मत्तात्मक शासन ही अच्छा है । स्पष्टतः ये आपत्तियाँ प्रतिनिधि मत्तान्मक वा एक वर्ग के शासन के पृष्ठ-भोषकों द्वारा उठाई हुई हैं । फिर भी, आइये, हम इसमें से प्रत्येक को मचाई मुठाई की परीक्षा करें ।

(१) यह हम उपर बता ही चुके हैं कि वर्तमान प्रतिनिधितंत्र का उमके आधार पर बने प्रजातंत्रों एवं नियंत्रित राज-

तथा म रास्त्र म प्रजा का शासन नहीं, बड़े-बड़े धनिकों के वर्ग या शासक वर्ग का शासन होता है। साथ ही यह भी उपर के अध्यायों में दिये हुए विवेचन से स्पष्ट है कि प्रतिनिधित्व की प्रणाली सब में अधिक बुराइयों को उत्तेजना देने वाली है। चूंकि कानून बनाने और उसे स्वीकार वा अस्वीकार करने की सज्जोपरि सत्ता व्यवस्थापिका के सदस्यों के हाथ में होती है, अतः प्रत्येक दल इन सदस्यों में बहुमत अपने पक्ष का चुनवाने और इस प्रयत्न में सफल न होने पर दूसरे वर्गों या दलों की आर से आय हुए सदस्यों को, रिश्वत, पद, प्रतिष्ठा विशेष सुविधा आदि द्वारा खरीदने का प्रयत्न करता है। प्रतिनिधि लोग भी एक बार चुन लिये जाने पर एक निश्चित मियाद के लिये ये लक्ष्य हो जाने के कारण अपनी जेबें भर कर अनाद्वनीय कानून बना और स्वीकार कर डालते हैं, क्योंकि उससे बुरे भले फल तो जनता को भोगन पड़ते हैं। उनका क्या गिगड़ता घनता है। वे तो अपनी व्यक्तिगत स्थिति सुध बन ही लेते हैं।

इस स्थिति के फल से जहाँ एक ओर इन व्यवस्थापिकाओं में जाने को स्वार्थी और चालार लोग उत्सुक हो, भिन्न-भिन्न सिद्धांतों की भूठी घोषणा कर जनता को धोखे में डालने के लिये उत्साहित होते हैं, वहाँ दूसरे स्वार्थी दल और स्वयं सरकारें या शासनारूढ दल व्यवस्थापिका का उपयोग अपने लाभ के लिये करने को उतने ही चिरारों के शिरार घनते हैं। ये दल खोल कर सार्वजनिक धन में जुआ खेलते हैं और फिर इन खरीदे हुए प्रतिनिधियों में ही भिन्न-भिन्न रूपों में उक्त स्वयं की मांगें स्वीकृत करा उसे जनता के मिर डालते हैं। जनता के हाथ में एक बार चुन देने पर इन प्रतिनिधियों को ठीक मार्ग पर लाने का दूसरे चुनाव के पहले कोई अस्त्र नहीं रहता।

यही कारण है कि जिस देश की व्यवस्थापिकाएँ जितनी ही अनियमित हैं, वहाँ की व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों को उनका ही अधिक व्यय मिलता है, उदाहरण के लिये जहाँ निवट्रलैण्ड में व्यवस्थापिका के सदस्यों को सदस्यत्त्व के अलावा की उपस्थिति ४ गिलिंग (प्रायः ४ रुपये) एवं कार्य-कारिणी के सदस्यों को १२५) मासिक मिलते हैं, वहाँ हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों को ६००००) से २०००००) वार्षिक तक मिलते हैं।

इस परिस्थिति का फल हम स्वयं अपने देश में भी देख रहे हैं। क्या भगानक से भगानक जनकारी कानून हमारी व्यवस्थापिकाओं में भाग्योप प्रतिनिधियों की ही उपस्थिति में स्वीकृत नहीं होते? क्या आज भी 'किमान रजक' कानूनों के नाम पर "इमोडार रजक" और 'महदुर रजक' कानूनों के नाम पर 'थनिक रजक' कानून नहीं बनाये जा रहे हैं। भला हम प्रकार के प्रतिनिध्यात्मक प्रजापंथों या नियंत्रित राज्यपंथों का कौन समर्थन कर सकता है?

ऐसी अवस्था में (जैसा कि अब तक के इस पद्धति के प्रयोग में भी प्रमाणित हुआ है) 'रिटैरेंशन' ने तो इन्फे रीर डिम्मेडार व्यवस्थापिकाओं को डिम्मेडार बनाया है। क्योंकि जब स्वार्थी लोगों को मान्य हो जाता है कि अब किसी कानून का अन्तिम भाग्य निर्णय व्यवस्थापिका के सदस्यों के हाथ में नहीं है, तो वे न तो सदस्यों को खरीदने की चेष्टा करते हैं और न अपने डिम्मेडार गटे करने या किसी अप्रत्यक्ष डिम्मेडार को मदद बनाने के लिये उनका से बोम्बे में टालने की।

दुसरी ओर व्यवस्थापिका के सदस्य भी प्रत्येक कानून बनाने या स्वीकार करने के पहले सब बातों पर भरीभोति

विचार कर लेते हैं। फिर वे तब ही कानून बनाते या स्वीकार करते हैं जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि इस की आवश्यकता है, वह जनता के लिये हितकर है और इसका विरोध जनता के बहुमत की ओर से न होगा।

(२) दूसरी आपत्ति के समर्थक कहते हैं कि राष्ट्र के लिये आवश्यक बहुत से रस्खों की महत्ता को साधारण जनता नहीं समझ सकती। साथ ही विशेष स्थितियों में तात्कालिक कानूनी उपाय इस पद्धति से प्रयोग में नहीं लाए जा सकते।

इस प्रश्न का उत्तर स्वयं स्विटजरलैंड का शासन है, जिसमें बहुत बड़ी लम्बे अरसे से इस पद्धति का प्रयोग हो रहा है। उदाहरण के लिए जूरिच में जनता ने विश्वविद्यालय के ३० लाख फ्रांक्स खर्च करने का बिल प्रसन्नता से मंजूर कर लिया। तमाम बड़ी रेलों को खरीदने की मजूरी प्रबल बहुमत से दी। इसी प्रकार विशेष स्थिति के लिये आवश्यक शक्ति प्रयोग के अधिकार भी जनता ने केन्द्रीय सरकार के लिये स्वीकृत कर दिये हैं। हाँ, यदि उनका दुरुपयोग किया जाय तो ये भी 'रिफ़ेरेण्डम' की कमीटी पर घसीटे जा सकते हैं और इससे यह लाभ ही है कि सरकार और अधिकारी भी उनका दुरुपयोग नहीं करते।

उतना ही नहीं मि० रिस्साउएट माइस के शब्दों में यह ता 'विशुद्ध उपयोगी-कानून बन ही उस देश में सकते हैं, जहाँ रिफ़ेरेण्डम की पद्धति जारी हो। क्योंकि जहाँ 'रिफ़ेरेण्डम' की पद्धति नहीं होती, और व्यवस्थापिका बेलगाम होती है, वहाँ प्रायः मधे सुधारकों को भी दूसरे दलों का सहयोग प्राप्त करने के लिये अपने बिल में ऐसे संशोधन कर लेने पड़ते हैं, जिनसे

वह मन्त्रोप हो जाता है। कई बार तो उसके उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। परन्तु स्विट्जरलैंड में ऐसे पंचायतों का दायरा हो चुके हैं, जिन में जनता ने ऐसे कानूनों को मन्त्रोप होने के कारण नामजूर कर दिया, परन्तु जब दुबारा वे ही विद्युद्ध रूप में उसके सामने रखे गए, तब जने तुरन्त स्वीकृति दे दी।”
(Modern Democracies Vol I)

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन ही २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ और ११ वीं आपत्तियों का भी उत्तर दे देता है। क्योंकि अनुभव से यह स्पष्ट हो गया है कि गिनिन कहलाने वाले प्रतिनिधि समन्वित के लिये वा अधिक चालाक लोगों की नीति में फैसल कर मन्त्रोप कानून बना और स्वीकार कर लेते हैं, परन्तु जन-साधारण कभी ऐसी भूल नहीं करने और इस प्रकार उनकी सामूहिक बुद्धि, गिनिनों की योग्यता से श्रेष्ठ होती है।

इसके अनिरिक्त यह आरोप तो दुबारा तलवार है। वह जिस प्रकार मायागर जनता पर लागू होती है उसी प्रकार गिनिनों के लिये भी प्रयुक्त हो सकती है। प्रश्न यह है कि राजनैतिक दलों के आदर्श, कार्यक्रम और जान बूझ कर गजब-गजब पूरा बनाई गई उनकी वही-वही गम्भीर घोषणाएँ कौनसी कानूनों से कम जटिल होती हैं ? वे भी तो आदर्श के मुहाविरों के अनुसार ‘राजनैतिक भाषा’ में होती हैं। कानून को देखकर तो मायागर व्यक्ति भी, पूरा नहीं हो कुछ, उसके आग्रह और अपने हितों पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को मनन सकता है; परन्तु उनकी सामग्री के तो मिर या पूँछ-कियाँ का भी ज्ञेय पता नहीं लग सकता। ऐसी दशा में राजनैतिक मिष्टान्तों के आग्रह पर दल बना कर उन पर लोभन लेना भी तो इतना ही अनुचित ठहरता है, जितना कि कानूनों पर उनका मन लेना

और यदि इसके लिए साधारण जनता योग्य है, तो कानूनों पर मत देने के लिये और भी अधिक योग्य है।

रही चौथी आपत्ति जो वह वैसे ही मार-शून्य है। जो लोग (व्यवस्थापिकाओं के प्रतिनिधि या उनके पक्षपाती) जनता के इस अधिकार का "अशिक्षितों की गुलामी" समझते हैं, वे यह आपत्ति उठाने समय इस बात को भूल जाते हैं कि न केवल उन्हें शिक्षित बनाने वाली संस्थाओं का स्वर्ण यही अशिक्षित जनता उठाती है, प्रत्युत उन्हें चुन कर भी वही भेजती है। यदि उन्हें अपनी कृतियों पर उमका मत जानना अपमान जनक मालूम होता है, तो उनके द्वारा चुना जाना तो और अधिक अपमान-जनक है।

रहा मतदाताओं के "रिफ़ेरेण्डम" में भाग लेने का प्रश्न तो मि० ब्राइस ने स्वयं अपने Modern Democracies नामक ग्रन्थ में कहा है कि जाँच करने से मुझे मालूम हुआ कि हमेशा ६० से ८५ प्रतिशत तक मतदाता भाग लेते हैं। प्रायः यही स्थिति साधारण अवस्था में, सब देशों में व्यवस्थापिकाओं के चुनाव में देरी जाती है।

अलगस्ता सोशलिस्ट (साम्यवादी) और कम्यूनिस्ट (समष्टिवादी) लोगों को यह शिकायत है कि इस पद्धति में उनके विचार और संगठन विशेष नहीं, यन्त्र बाते, क्योंकि जनता में उनका असन्तोष ही नहीं बढ़ पाता।

दलगत-शासन की न्याय्यता

परन्तु यार्गीय शासन के मतवाले सब से अधिक इसलिये "रिफ़ेरेण्डम" के विरुद्ध हैं कि वह वर्ग शासन या राजनैतिक

दल-वन्दिता का प्राप्ताहन नहीं देता। दलवन्दियों या वर्ग-शामन अथवा पार्लियामेण्टरी-गवर्नमेण्ट की आवश्यकता के सम्बन्ध में जब उनसे प्रश्न किया जाता है, तो वे कहते हैं, कि “उममे शामन अच्छा हाता है। देश की उन्नति होती है।”

“परन्तु कैमे ?” इस प्रश्न के उत्तर में वे कहते हैं कि—“प्रथम ता प्रत्येक दल अधिक लोकप्रिय होने के लिये नए नए कार्यक्रम और सुधार के प्रश्न जनता के सामने रखता रहता है। दूसरे प्रत्येक दल दूसरे की त्रुटियों की आलोचना करता रहता है। इन मय धानों में जनता को राजनैतिक शिक्षा मिलती रहती है। फिर दल पद्धति में एक दल जो अल्पमत में रहता है, प्रायः विरोधी रहता है और उसके मय में शामनारूढ़ दल मझ मतर्क रह कर शासन प्रणाली का ऐसी रम्बने की चेष्टा करना है जिस पर विरोधियों को आक्षेप करने का अवसर न मिले। इसी लिये पार्लियामेण्टरी पद्धति शामन की उन्नतिशील रखने वाली है।”

निःसन्देह, माधारण बुद्धि के व्यक्ति जो ये धानें अच्छी लगती हैं। परन्तु थोड़ा गम्भीरता पूर्वक विचार करते ही आधुनिक राजनीति में परिचित व्यक्ति स्पष्ट समझ जाता है कि मय जनता को भ्रम में डालने के तरीके हैं। क्योंकि प्रथम तो जिन-जिन देशों में यह पद्धति प्रचलित है, उनमें से किसी में यह शांति और उन्नति नहीं दिखलाई देती, जो “रिकॉर्डेण्टम” पद्धति को मानने वाले देशों में दिखलाई देती है। अमेरिका के शामन तक में इस पद्धति के प्रयोग के बाद ही स्थिरता आई है। जैसे भी आम तौर पर ऐसे देशों में जितने दल होते हैं, वे प्रायः सब सम्पन्न वर्गों के ही होते हैं। कोई जमींदारों का तो कोई कारखानेदारों का। कोई पदवीधारी गिजिनों का और कोई अन्य बड़े उद्योगों धानों या व्यापारियों का। इन्हीं वर्गों को मय प्रकार

की सुविधाएँ रहती हैं और इसलिए ये ही भिन्न-भिन्न राजनैतिक सिद्धान्तों की आड़ में अपने दल संगठित कर लेते हैं एवं एक दूसरे के विरुद्ध प्रधानता के लिये लड़ते रहते हैं।

यही कारण है कि वे साधारण प्रश्नों को लेकर हमारे नेशनलिस्ट और स्वराजिस्ट आदि दलों की तरह एक दूसरे की आलोचना भले ही करते रहते हों, गोल मोल शब्दों में पाहे कुछ साम्यवाद जैसे सिद्धान्तों के प्रति भी अनुरक्ति दिखाते रहते हों, परन्तु साधारण जनता में वैज्ञानिक राजनीति का प्रचार हो, अथवा उसे कुछ प्रभावशाली अधिकार मिलें, ऐसी बात भी कोई नहीं करते। अन्यथा फ्रांस और इंग्लैंड में तो आज तक यथा यथा राजनीतिज्ञ हो जाना चाहिये था। सच तो यह है कि ऐसे लोग अपने स्वार्थों की रक्षा के लिये ही रिफ़ॉर्मेशन का विरोध करते हैं।

धार्मिक और जातीय भेद भाव

दलबन्दी ही नहीं, जातीय और धार्मिक भेद भाव के रोगों—जिनका हमारा देश विशेष रूप से शिकार है—को मिटाने में भी 'रिफ़ॉर्मेशन' की पद्धति 'रामनाथ' मानित हुई है। हम मन्थन में त्रिस्तोत्र आइस कहते हैं कि—

‘रिफ़ॉर्मेशन जातीय और धार्मिक भेदभाव का राष्ट्रीयता में परिणत कर देता है। क्योंकि सब वर्गों और दलों के लोगों को मिलकर ऐसे प्रश्नों पर मत देना पड़ता है और उनके लिये काम करना पड़ता है, जो धर्मों एवं वर्गों की भावना और दलों के कार्यक्रम में परे होते हैं।

हम जानते हैं कि हिन्दू-मुसलमान अनेक और विभिन्न परस्पर विरोधी विचार रखने वाले समूह सम्मिलित हैं। लेकिन माध

ही इस ज्ञान में भी कोई इन्कार नहीं कर सकता कि इन सब में एक राष्ट्रीयता की भावना द्वारा, ऐक्य स्थापित करने का श्रेय रिफ़रेंस को ही है।

इस प्रचार का पोषक कोई प्रमाण नहीं मिलता कि रिफ़रेंस के कारण व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों की योग्यता का उनकी कदर में कोई कमी आई है अथवा योग्य आदमियों को उम्मेदवार बनने में उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता।”

(मोडर्न डिमोक्रेसी भाग १ पृ० ४४७)

श्री नालकृष्ण एम० ए , पी० एच० टी० (लन्दन) प्रिंसिपल राजाराम कॉलेज, कान्हापुर, अपनी पुस्तक (Demand of Democracy) में कहते हैं कि —“रिफ़रेंस जनमत्ता के जहाज का मस्तूल है। यह सुरे कानूनों का जनना रास्ता है। इसने जनता और शासकों के बीच के विराध और भेदभाव को मिटा दिया है। इसने व्यवस्थापिकाओं में होने वाली स्वार्थ-परायणता, रिश्तव, कूटनीति और दलबन्दी आदि की जड़ काट दी है। वह किमी वर्ग या दल के हित के विचार को हटा कर देश भर के हिताहित में मन्वन्व रखने वाले कानूनों को ही स्वीकार करता है। यह शासन यंत्र में स्थायित्व लाता है।

अपक्षय को रोकता है। जनता को राजनैतिक शिक्षा देने का यह प्रधान अस्त्र है। यह जाति और धर्मगत भेदों को नष्ट करता है और जनता की सचि शासन एवं राजनैतिक प्रगति में बढ़ाता है। यह अनावश्यक कानूनों की वृद्धि रोकता है,

साथ ही यह हिमामक अप्रतियों की मन में उड़ी ढाल है। यह प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन की मन पुराइयों को दूर करने का अच्छा नुस्खा है। सब में वही बात यह है कि

इसमें भिन्न भिन्न परस्पर विरोधी (गरीब अमार, धनिक मजदूर आदि) समूहों का मिलाने की अद्भुत शक्ति है।" (अध्याय ६ पृ० ६१-६२) ।

मि० एम० हिल्टी कहते हैं —

‘ रिफ़रेंडम द्वारा बने हुए कानून दुगने लोकप्रिय होते हैं । इसका द्वारा लोग स्वतः ही कानून की धारिक्रियाँ समझने लगते हैं । साथ ही व्यवस्थापिकाओं को भी न केवल अपने ‘निल’ (कानून का मसविदा) सक्षिप्त बनाने पड़ते हैं, प्रत्युत इतनी सरल और सीधी भाषा में भी बनाने पड़ते हैं, कि सर्व साधारण उन्हें भलीभाँति समझ लेते हैं ।

यह लागू में देश प्रेम बढ़ाता है और मतदाताओं में दायित्व की भावना का जागृत करता है । यह शासक वर्ग में जनता को उल्लू बनाकर उस पर अधिकार रखने की आकांक्षा के स्थान पर सहयोग और सेवा द्वारा अपना अस्तित्व रखने की भावना पैदा करता है ।”

(Deplonge's Reterandum p 276)

इन उद्धरणों से पाठक समझ सकते हैं कि ‘ रिफ़रेंडम ’ के विरोधियों की दलालें कितनी स्वार्थपूर्ण एवं लचर हैं और यह पद्धति वास्तव में कितनी उत्कृष्ट है ।

व्यावहारिक रूप

प्रत्येक कानून, जब व्यवस्थापिका में स्वीकृत हो जाता है, तो वह सरकारी अखबार में प्रकाशित कर के जिलों की कौंसिलों के पास भेज दिया जाता है । जिले की कौंसिलें उसकी प्रतियाँ माम पचायतों में बँटवा देती हैं । इस पर लोकमत प्रगट करने की ३ मास या ६० दिन की मियाद दी जाती है ।

इस ६० दिन की मियाद में यदि ३०००० नागरिक या अधिक मिलकर रिटिरेटमेंट की मांग करना चाहें, तो वे कर सकते हैं। परन्तु आम तौर पर डिलेरिकैरेटमेंट की मांग बहुत कम करते हैं।

क़ानून प्रकाशित हो जाने पर उनके विरोधी दल, जनता में घूम घूम कर उनकी त्रुटियाँ उसे समझाते हैं। साथ ही रिटिरेटमेंट के लिए हस्ताक्षर लेने शुरू करते हैं। कई बार इस प्रकार के प्रचार और हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए दलों और संस्थाओं का संगठन कर लिया जाता है। क्योंकि हस्ताक्षरों के बनावटी होने, न होने की कड़ी जाँच की जाती है। यह जाँच प्रत्येक मान-पंचायत के ममानति द्वारा की जाती है।

किसी किसी ज़िले में अपढ़ नागरिकों के लिए हस्ताक्षर के स्थान पर कोई चिन्ह बना देने का नियम भी होता है।

जब इस प्रकार पूरे हस्ताक्षर पहुँच जाते हैं, तब सरकार इसकी सूचना जिला पंचायतों को दे देती है और क़ानून की प्रतियाँ देश भर में बँटवा देती हैं।

इसके बाद मत लेने की तारीख घोषित की जाती है, जो कम से कम क़ानून के प्रकाशन और विवरण के एक मास बाद की होती है।

सरकार की तरफ से निर्दिष्ट क़ानून प्रत्येक मतदाना के पान भेज दिया जाता है। इसके पत्र वा विपत्र में कोई सम्मति या विवेचन नहीं भेजा जाता।

इसके बाद पत्र और विपत्र के दलों द्वारा आन्दोलन शुरू होता है। इस आन्दोलन की ममाओं में व्यसम्पादिका के मदत्य भी भाग ले सकते और भाग्य कर सकते हैं।

मत लेने का प्रबन्ध प्रत्येक जिले में उस जिले की पचायत करती है। हाँ, कानून की प्रतियाँ और 'वैलट वेपर्स' केन्द्रीय सरकार ही जिलों को भेजती हैं।

मत देश भर में प्रायः एक ही दिन और प्रायः रविवार को लिये जाते हैं। मत देने के दिन सारा काम ब्रम् धद्ध और नियमित रूप से होता है। कोई कगडे टण्टे या रिश्मत आदि की शिकायत नहीं सुनी जाती।

अवश्य ही कानून की प्रतियाँ इस पद्धति में बहुत अधिक छपानी पड़ती हैं और इस लिये व्यय अधिक होता है, परन्तु दूसरी बुराइयों के दूर होने और उनसे देश के सुरक्षित रहने के रूप में कई गुना अधिक लाभ हो जाता है। साथ ही एक लाभ यह भी है कि जब तक पूरी आवश्यकता ही न हो, व्यवस्थापिका नए कानून नहीं बनाती।

(२)

कुछ जिलों में हस्ताक्षर लेने की पद्धति नहीं है। वहाँ प्रत्येक कानून पर रिक्वैरेण्डम लेने का नियम है और इसलिये हस्ताक्षरों की आवश्यकता ही नहीं होती। और चूँकि कई जिलों में मतदाता प्रकरण मत देने न आने तो उम्र पर जुर्माना होता है, अतः मत भी पाली आते हैं।

सरकारी कानूनों का संशोधन एवं परिवर्तन



इसकी माग नीचे लिखे अनुसार हो सकती है —

(अ) किसी भी व्यवस्थापिका के सदस्य द्वारा।

(ब) किसी जिले की शासन सभा द्वारा।

(स) केन्द्रीय सरकार या सघ सभा द्वारा ।

(द) ५०००० मतदाताओं द्वारा ।

ऐसी माग होने पर, पहले सशोधन पर दोनों व्यवस्थापिकाएँ मिलकर विचार करती हैं । यदि वे सशोधित कानून पर सहमत होती हैं, तो उस पर लोकमत ले लिया जाता है ।

यदि व्यवस्थापिकाएँ परस्पर सहमत नहीं हो पातीं, तब जनता का मत पहले इस बात पर लिया जाता है कि “प्रस्तावित सशोधन होना चाहिये या नहीं । यदि जनता का बहुमत सशोधन के पक्ष में होता है, तो व्यवस्थापिकाएँ भग कर दी जाती हैं और दूसरे चुनाव में सशोधन के पक्षपाती उम्मेदवार चुने जाते हैं ।

चुनाव के बाद व्यवस्थापिकाएँ उक्त सशोधन या कानून को स्वीकार कर उस पर लोकमत लेती हैं । परन्तु यदि प्रस्ताव ५०००० मतदाताओं द्वारा आता है, तो उस पर व्यवस्थापिकाएँ विचार नहीं करतीं, उस पर लोकमत ले लिया जाता है ।

इस प्रकार यदि व्यवस्थापिकाएँ सहमत होती हैं तो लोकमत एक बार ही लिया जाता है और यदि उनमें मतभेद हो जाय तो प्रत्येक प्रश्न पर दो बार “रिपैरेण्डम” का प्रयोग होता है ।

यदि सशोधन मामूली होता है, और उस पर भी व्यवस्थापिकाओं में मतभेद होता है । तो उक्त सशोधन स्थगित कर दिया जाता है । उस अवस्था में व्यवस्थापिकाएँ भग नहीं की जातीं, अनुकूल अवसर आने पर ऐसे प्रश्न फिर उठाये जाते हैं ।

जनता के साधारण संशोधन

यदि ५०००० मतदाताओं द्वारा साधारण संशोधन पेश होना हो, तो वे दोनों प्रकार से कर सकते हैं। केवल संशोधन का उद्देश्य और रूप बता कर या स्वतंत्र निल (क्रानून का मसिदा) को शकल में पेश करके। यदि व्यवस्थापिकाएँ उससे सहमत हुई, तो उस पर लोकमत ले लिया जाता है। यदि सहमत न हो तो "संशोधन होना चाहिये या नहीं"—इस विषय पर लोकमत लिया जाता है। अथवा उसी जगह व्यवस्थापिका स्वयं दूसरा संशोधन या क्रानून बना कर दोनों पर साथ साथ मत लेती है। यदि जनता फिर भी पहले संशोधन या क्रानून के पक्ष में ही मत देती है, तो वही विरोध करने वाली व्यवस्थापिका उस का मसिदा बना कर उसे स्वीकार कर लेती है। इस प्रकार व्यवस्थापिकाओं के भंग होने की नीयत नहीं आती।

हाँ, किसी संशोधन की सफलता के लिये अकेली जनता का ही बहुमत काफी नहीं है। क्वेटन्स का भी बहुमत होना चाहिये। परन्तु यह नियम विशेष क्रानूनों के लिये है, साधारण संशोधनों में जनता का बहुमत ही काफी माना जाता है।

कुछ परिणाम

स्विटजरलैंड में सन् १८७४ ई० में रिश्रेरेण्डम की पद्धति प्रचलित हुई थी। तब से १८९८ ई० तक—

- (१) पुराने क्रानूनों के ११ संशोधनों पर लोकमत लिया गया जिनमें से ७ स्वीकृत हुए और ४ अस्वीकार किये गए।
- (२) नए प्रस्तावों और क्रानूनों (जिन पर लोकमत लिया गया) की संख्या २५ थी। इनमें से ७ स्वीकृत हुए और १८ नामसूर हुए।

सन १९०५ से १९१६ तक:—

(३) व्यवस्थापिका ने कुल तीन कानूनों और प्रस्तावों पर लाकमत लिया और वे सब स्वीकृत हुए।

संशोधनों के प्रस्तावों का भी इतिहास मनोरंजक है। उदाहरण के लिए:—

(४) इस लम्बे समय में व्यवस्थापिका की ओर से २५ संशोधन जनता के सामने रखे गए, जिनमें से उसने १६ स्वीकार किये और ६ अस्वीकार।

(५) परन्तु ५०००० मतदाताओं के हस्ताक्षरों द्वारा १२ संशोधनों पर लोकमत लिया गया, फिर भी ५ ही स्वीकृत हो सके और ७ अस्वीकार कर दिए गए।

इन परिणामों से नीचे लिखे निष्कर्ष निकलते हैं:—

- १—प्रारम्भ में, पहिले के अभ्यास के अनुसार व्यवस्थापिकाओं ने बहुत से कानून बनाए, परन्तु अन्त में वे नामजूर हुए।
- २—इस अनुभव से लाभ उठाकर फिर व्यवस्थापिकाओं ने कानून बनाने में दायित्वपूर्णता से काम लेना शुरू किया और इसलिये पीछे उसके अधिकांश कानून स्वीकृत हुए।
- ३—चूंकि पीछे कानून कम बनने से भी सामान-यंत्र और देश का कोई हानि नहीं पहुँची, अतः स्पष्ट है कि पहले बहुत से कानून अनावश्यक और प्रायः व्यवस्थापिका के मदियों के नाम कमाने या वर्ग विशेष का 'नमक अढ़ा' करने की रूढ़ि के फल होते थे।

४—ज्या २ व्यवस्थापिकाएँ अधिक दायित्वपूर्ण होने लगीं, त्या त्या, नागरिका की अपेक्षा उन के कानून अधिक स्वीकार कर जनता ने उन पर विश्वास करना शुरू कर दिया ।

५—जनता ने इतने लम्बे समय में भी कोई अनुचित बात स्वीकार नहीं की, इससे स्पष्ट है कि जन-साधारण, वर्गों और दलों की तरह अधिकार का दुरुपयोग नहीं करते, अन्यथा धनिक और शासक वर्ग को पठनाइयाँ म डाल देना उन के लिये आसान था ।

६—अब तक भी कानूनों के अस्वीकृत होने की नीरत आना इस बात का प्रमाण है कि इतने जन-सत्तात्मक शासन में भी व्यवस्थापिका लोचमत विरोधी कानून बना सकती है । फिर उन व्यवस्थापिकाओं को जनता की प्रतिनिधि कहना, जहाँ जनसत्ता अन्तिम निर्णायक नहीं है, तो प्रतिनिधित्व का मञ्जर उड़ाना है ।

स्विट्जरलैंड का विरोध किये जाने के कुछ विशेष कारण भी हैं । स्विट्जरलैंड का इतिहास ही इसका साक्षी है । उसने अध्ययन से पता लगता है कि बीच-बीच में भिन्न-भिन्न कानूनों की आड़ में केन्द्रीय सरकार यह कोशिश करती रहती है कि उसके अधिकार बढ़ जायें । परन्तु अशिक्षित कही जाने वाली जनता इस मामले में इतनी योग्य साबित हुई है कि उसने प्रायः हर बार केन्द्रीय सरकार को मात दी है ।

उदाहरण के लिये हमारे देश की सिविल सर्विस की तरह अब वहाँ की केन्द्रीय सरकार ने अपने अधिकारियों की पेंशनों के लिए एक कानून बनाया, तो जनता ने उसे इमीलिए नामशूर

कर दिया कि वह केवल केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के लिये था, न कि सारे देश के लिये। इसी प्रकार जब एक कानून समाचार पत्रों के विरुद्ध सैनिकों में अनुशासन-हीनता फैलाना रोकने के वहाने व्यवस्थापिका में स्वीकृत किया गया, तो जनता ने उसे प्रचल बहुमत में नामंजूर कर दिया। शिक्षा को भी जब केन्द्रीय सरकार ने पूर्णतः अपने अधिकार में लेना चाहा, तो जनता ने प्रचल विरोध कर उम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इतना ही नहीं, स्विस लोग स्थानीय और प्रादेशिक स्वतंत्रता के इतने पक्षपाती हैं कि जब केन्द्रीय सरकार ने मतदाताओं की योग्यता आदि नियत करने के अधिकार अपने हाथ में यह कहकर लेने चाहे कि यह अधिकार प्रत्येक जिले के होने से देश भर में इस संवन्ध में एक सा कानून नहीं बन पाता, तो जनता ने स्पष्टतः यह कह कर उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि अपने प्रदेश के मतदाताओं के संवन्ध में, प्रदेश ही सब से अच्छा निर्णय कर सकते हैं।

इस प्रकार जब २ शासनारूढ़ दल ने अपने अधिकार बढ़ाने या अपने दल को सुदृढ़ करने के लिये कोई कानून बनाना चाहा है, तभी जनता ने उसे अस्वीकार कर दिया है और जब वही कानून उस दोष में मुक्त करके उसके मामले रक्खा गया है, तभी उसने उसे स्वीकार कर लिया है।

अमेरिका की मतकीर्ता

अमेरिका ने तो इस अनुभव में लाभ उठाकर यह नियम ही कर दिया है कि जनता चाहे, तो पूरे कानून को नहीं, उसके दूषित भाग को ही रद्द कर सकती है। इसमें व्यवस्थापिकाओं की कानून को दुबारा बनाने की महन्त वच जाती है। हाँ, जो

दल व्यवस्थापिका में अपने दौब पेचों द्वारा कानूनों में अवाङ्मनीय संशोधन करा लेते हैं, उन्हें बुरी तरह निराश होना पड़ता है।

यही क्यों, पहले स्विट्जरलैंड में तात्कालिक और विशेष स्थिति के लिए बनने वाले 'आर्डिनैंसों' एवं कानूनों पर "रिफ़ेरेण्डम" लेने का नियम न होने से अधिकारी लाभ उठाते थे और "अरूरी" की आड़ में आवश्यक कानून बना लेते थे। अतः अमेरिका के कई राज्यों ने स्विस लोगों की इस कठिनाई से शिक्षा ले प्रारम्भ से ही यह नियम रख दिया कि ऐसे अरूरी कानूनों और 'डिप्रीज़' पर भी यदि ३०००० मतदाता लिखें, तो 'रिफ़ेरेण्डम' का प्रयोग कर उनके अरूरी या ग़ैर अरूरी होने का निर्णय किया जाय। इससे राजभाजत स्वार्थियों के स्वार्थ साधन का रहा सहा मार्ग भी बन्द हो गया और यही कारण है कि वर्गशासन के पक्षपाती इस पद्धति को प्रायः सर्वोत्तम होने पर भी स्वीकार नहीं करते।

अवश्य ही इस पद्धति की पूरी सफलता भी उसी अवस्था और उन अन्य सहायक व्यवस्थाओं पर ही निर्भर है, जो स्विट्जरलैंड में वर्तमान एवं प्रचलित हैं। परन्तु इस छोटी-सी पुस्तक में उन सब बातों के विवेचन के लिये स्थान नहीं है। फिर इसका ध्येय भी केवल चुनाव पद्धतियाँ का विवेचन है।

THE INITIATIVE (दि इनीशियेटिव)

अर्थात् विधान निर्माणधिकार

या

जनता का स्वयं क़ानून बनाना

—३—

परन्तु केवल 'रिफ़ैरेण्डम' से ही वर्तमान व्यवस्थापिकाओं की चालों का अन्त नहीं हो गया। हम बता चुके हैं कि समाज के वर्तमान अप्राकृतिक, आर्थिक और अन्य गहरे भेदभावों के मौजूद रहते हुए, समानता के आदर्श को व्यावहारिक रूप देना एक असाध्य-साधन का प्रयत्न है। फिर भी चूंकि मनुष्य के—स्विट्जरलैंड के अशिक्षित जन-समूह के—मस्तिष्क ने इस पुराने नुस्खे को सुरक्षित रख छोड़ा था, अतः वह इस समय काम आ गया और उसने इस असाध्य समस्या को बहुत कुछ साध्य बना दिया।

परन्तु वर्तमान राजनीति जितनी प्रगति कर चुकी है और जितनी सफल हो चुकी है, उसके लिये इतना ही काफी न था। वह रिफ़ैरेण्डम के शिकंजे में जकड़ी रहने पर भी कुछ न कुछ करती ही रहती थी। ऐसे कुछ प्रयत्नों के उदाहरण उपर आ चुके हैं। एक दूसरा तरीका यह भी उसने महण किया कि जिस समय राष्ट्र के हित की दृष्टि में जो क़ानून बनाना आवश्यक होता, उसे वह उस समय न बनानी। क्योंकि आखिर क़ानून बनाना या शासन व्यवस्था के बारे में कोई प्रस्ताव रखना तो व्यवस्थापिका और केन्द्रीय सरकार के ही हाथ में था। जनता तो केवल उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकती थी।

और व्यवस्थापिकाओं की स्थिति से तो आज सभी परिचित हैं। हमारे देश में ही क्या स्थिति है ? आज देश में औद्योगिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। मशीनों के युग के कारण असह्य युवक बेकार फिर रहे हैं। न उनके लिए नये उद्योग निकाले जाते हैं, न योरोपीय देशों की तरह कारखानेदारों की जेब से निकालकर उन्हें बेकारी का अलाउंस दिया जाता है। देश का अर्द्धाङ्ग स्त्री-समाज चक्की, चरखे, करघे आदि से तो घरी पर दिया गया है, परन्तु इससे हुई उसके स्वावलम्ब की हानि की पूर्ति के लिए कोई सोचता भी नहीं।

हमारी व्यवस्थापिकाएँ बड़े-बड़े धनिका के उद्योग धन्धों की रक्षा के लिये कानून बनाती हैं, आगारा पाताल एव करती हैं, जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए लड़ती हैं, परन्तु उपरोक्त उदाहरणों जैसे देश के बहुमत पर प्रभाव डालने वाले प्रश्नों की ओर फूटी ओंस से भी नहीं देखतीं। अर्थात् वास्तव में वे जनता की प्रतिनिधि नहीं, स्वामिनी बनकर आचरण करती हैं।

फिर यदि वे कोई कानून जनता के हित के बनाती भी हैं, तो जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, भिन्न भिन्न कारणों से उनका अधिकतर उपयोगी भाग निकाल दिया जाता है और अन्तिम रूप में वे मुख्यतः किसी वर्ग विशेष को ही लाभ पहुँचाने वाले रह जाते हैं। इसलिये यदि देश में 'रिफॉरेण्डम' की पद्धति प्रचलित हो, तो भी जनता के हाथ में किसी पूरे कानून को स्वीकार या अस्वीकार करने के अतिरिक्त कोई अधिकार नहीं रहता। आधुनिक 'रिफॉरेण्डम' के उत्कृष्टतम रूप में भी उसे सर्वत्र उसमें वाञ्छित संशोधन कर देने का अधिकार नहीं है। जनता में से आज के पक्षपातपूर्ण विधानों एवं व्यथशील चुनाव पद्धतियों के कारण व्यवस्थापिकाओं में न जा सकने वाला कोई योग्य व्यक्ति

जनता के हित का कोई कानून का मन्विदा बनाकर देना भी चाहे तो नहीं दे सकता ।

इसीलिये १८ वीं शताब्दी के प्रथम चरण में ही स्विस लोगों ने यह आवाज बुलन्द की कि हम अपने प्रतिनिधि कहलाने वालों के गुलाम नहीं बनना चाहते । हमें स्वयं कानून बनाने का हक है ।

स्वार्थियों ने इसका भी विरोध किया । अशिक्षित जनता अनर्थ कर देगी, क्रान्ति हो जायगी, बहुमत-अल्पमत को न्या जायगा; आदि मंत्र बुद्ध बका गया । परन्तु व्यर्थ । अमन्योप बढ़ता ही गया ।

अन्त में हम आन्दोलन की मन् १६३१ ई० में विजय हुई और 'सेंट गाल' की कैण्टन में "इनीशियेटिव" पद्धति स्वीकार करली गई । इसके समर्थन में उस समय कहा गया था:—

“जनता—अकेली जनता ही देश की सधमें वरिष्ठ सत्ता है । उसकी इच्छा ही राष्ट्र का कानून होनी चाहिये । वरिष्ठता का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता । जो वरिष्ठ सत्ता अपने अधिकारों को प्रतिनिधियों के हाथों में ही छोड़े देना है, वह राज-च्युत शासक के समान है । हम लिये यह कल्पना ही नहीं की जा सकती कि व्यवस्थापिका जनता की अभिभावक हो ।”

इसी तरह प्रिंसिपल बालकृष्ण कहते हैं कि:—

“व्यवस्थापिका ममारें केवल वरिष्ठमत्ता—जनता—की एजेंट

हैं। जनता को, ऐसी व्यवस्थापिकाओं की स्वीकृति के बिना किसी कानून में परिवर्तन, परिवर्द्धन का अधिकार न होना, सैद्धान्तिक दृष्टि से दोषपूर्ण और व्यावहारिक दृष्टि से खतरनाक है।

व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी कौंसिल, और न्याय विभाग-कोई भी अपनी शक्ति और अपने अधिकार अपनी ही स्वामिनी जनता-के विरुद्ध उपयोग में लाने को स्वतंत्र नहीं होना चाहिये। आज इनमें से प्रत्येक विभाग अपने स्वार्थ से बधा हुआ है। ये सब धरावर अपने अधिकार बढ़ाने की चेष्टा करते रहते हैं। और यदि अपने अधिकार घटाने घटाने का काम वे बिना जनता की मजूरी के कर डालने को स्वतंत्र हा तो स्थिति बिलकुल उलटी हो जायगी। अर्थात् जनता के बनाए-चुने-हुए एजेंट स्वामी हो जायगे और स्वामिनी-जनता उनकी दासी बन जायगी। (यही हो रहा है। ले०) यह "कुत्ते के अपनी पूछ के द्वारा पसीटे जाने" के समान है।

क्या हम व्यवस्थापिका के सदस्य को अपनी इच्छानुसार व्यवस्थापिकाओं की बैठकों की मियाद घटाने बढ़ाने और अपने ही लिये ६०००० रुपये वार्षिक वेतन, रेल के ऊँचे दर्जे का-नौकर चाकरों सहित सफर खर्च और लम्बा चौड़ा भत्ता स्वीकार कर लेने को स्वतंत्र छोड़ दें ? क्या हम किसी व्यवस्थापिका के सदस्य से यह आशा करते हैं कि वह अपने ही हाथों से अपने अधिकार कम कर देगा, अपनी शक्तियों को नियंत्रित करेगा, चुनाव के कानूनों को बदल देगा, म्यूनिसिपल के मामला में अपने अधिकार छोड़ देगा और कमीशन-रूल आदि निकालेगा ? सिद्धान्त तो यह है कि चरिष्ठ-सत्ता अपने एजेंट की सम्मति के बिना भी अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है। उदाहरण के लिये स्विटजरलैंड के मन्त्री, अधिकारी आदि सब वहाँ "संख्यानुपात चुनाव पद्धति" Proportional Represen

tation प्रचलित करने के विरोधी थे। परन्तु जनता चाइती थी और उसने 'इनीशियेटिव' के द्वारा वह प्रचलित कर दी।"
(Demands of Democracy)

इसके अतिरिक्त आजकल व्यवस्थापिकाओं में जाने वानों पर इतने कृत्रिम प्रतिबन्ध हैं और उनकी चुनाव प्रणाली इतनी दूषित हैं कि इनमें खास योग्यता वाले नहीं, प्रत्युत विशेष-साधनों में युक्त व्यक्ति ही जा सकते हैं। उम्मेदवार लटा होने वाला इतना किराया, इतना इन्कन्टेन्स, और इतना जमीन का लगान देने वाला या पाने वाला ही होना चाहिये। आदि, अर्यान् गौद्धिय योग्यता नहीं, साम्प्रतिक योग्यता उसकी रसौटी है। भेजे जाते हैं वे कानून बनाने और देश भर के हिताहितों पर निचार कर कार्य करने के लिये और उनकी योग्यता परखी जाती है सम्प्रति से।

इनसे अलावा और भी अयोग्यताएँ हैं जो कम हास्यास्पद नहीं हैं। उदाहरणार्थ स्त्री (गोया स्त्रियों ने निरुद्धिवा का ठेका ले लिया है), अपरिपक्व आयु, पिढ़ड़ी जातियों के लोग, धनहीन, अनिवामी अर्थात् चुनाव-भेद में न रहने वाले और किसी अपराध के लिये सजा पाए हुए।

इनमें से किसी एक के लिये भी यह कोई नहीं कह सकता कि इनमें कानून बनाने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति हो ही नहीं सकते। फिर भी इन कृत्रिम अयोग्यताओं द्वारा न केवल उनकी उस योग्यता का लाभ जनता को मिलने के द्वार मन्द कर दिये जाते हैं, प्रत्युत उन्हें अपनी उम्र योग्यता को अपने हृदय में ही दबाये हुए चिता में लेजा कर अपने माथ भस्म कर देने के लिए बाध्य किया जाना है। क्योंकि जिस योग्यता के लिए शराम लेने को अवकाश ही नहीं, वह बाहर कैसे आ सकती है ?

‘इनीशियेटिव’ के द्वारा जनता को ऐसी-वैसी सामाजिक-शक्तियों का लाभ मिल सकता है। इसके अतिरिक्त ‘जन सत्ता’ को चरितार्थ करने में जहाँ अकेली ‘रिफैरेण्डम’ की पद्धति असफल होती है, वहाँ “इनीशियेटिव” उसकी पूर्ति का प्रयत्न करता है। कारण, कि पहली पद्धति द्वारा तो जनता केवल व्यवस्थापिका या केन्द्रीय सरकार के कामों और इरादों पर अपना फैसला देती है और अकुश रहती है। परन्तु पिछली पद्धति के द्वारा वह स्वयं उनका या उनके द्वारा उपेक्षित व्यवस्था का काम करती है। इस प्रकार पहली पद्धति का ध्येय शासन पर नियंत्रण रखना है, तो दूसरी का स्वयं प्रत्यक्ष शासन करना है। अस्तु,

व्यावहारिक रूप

अब हम ‘इनीशियेटिव’ का व्यावहारिक रूप पाठकों के सामने रखते हैं। कहना व्यर्थ है कि ‘रिफैरेण्डम’ की तरह भिन्न भिन्न देशों और जिलों में इसके भी अनेक रूप हैं।

उदाहरण के लिये अमेरिका के प्रांत वा राज्यों में १० प्रतिशत और छोटे जिलों में ५ प्रतिशत मतदाता अपने हस्ताक्षरों से युक्त पत्र द्वारा यह माग कर सकते हैं कि हमारे प्रस्तुत किये हुए प्रश्न वा कानून पर लोकमत लिया जाय।

तैक्स (Texas) में १० प्रतिशत मतदाता हस्ताक्षर करके किसी बिल पर जनता के विश्वास वा अविश्वास का प्रस्ताव तक ला सकते हैं। इसे ‘पार्टी इनीशियेटिव’ कहते हैं। (Beard's Documents on the Initiative, Referendum & Recall)

परन्तु आमतौर पर रिफैरेण्डम की अपेक्षा “इनीशियेटिव” के पत्र पर अधिक मतदाताओं के हस्ताक्षर लिये जाते हैं। नीचे दी हुई सूची से यह विषय और भी स्पष्ट हो जायगा —

देश या जिला	'रिक्रैडम' के लिये हस्ताक्षर, इनीशियेटिव के लिये	
स्विट्जरलैंड	३००००	५००००
जर्मनी	५ प्रतिशत	५ प्रतिशत
जुग	५००	१०००
बसले, राफर्हासेन	१०००	१०००
न्युशानल	३०००	३०००
सेण्ट गाल	४०००	४०००
ल्युमेरने टिसनो	५०००	५०००
बौद	६०००	६०००
अर्केसास	५ प्रतिशत	५ प्रतिशत
कैलिफोर्निया	"	"
कोलोरादो	"	"
मिस्सोरी	"	"
मोन्टाना	"	"
उक्लाहोम	"	"
उरगोन	"	"
मैन	१००००	१२०००

फारम्युलेटेड इनीशियेटिव

प्रारम्भ में 'इनीशियेटिव' के द्वारा प्रस्ताव और फानून तो बन सकते थे, परन्तु पहले के बने देश-व्यापी कानूनों में सशोधन नहीं हो सकना था। उनमें सशोधन व्यवस्थापिकाएँ ही कर सकती थीं। किंतु जनता के आग्रह पर मन् १८६१ में यह अधिकार भी उमे पहिले स्विट्जरलैंड में और पीछे अन्यत्र मिल गया।

इस पद्धति के अनुसार नागरिक, योग्य व्यक्तियों से अपनी पसन्द के फानूनों या सशोधनों के मस्विदे तयार करा लेने हैं और फिर सगठित रूप में उससे लाभ हानि जनता को समझाने हैं। विरोध करने वाले उसका विरोधी पक्ष जनता के सामने

रखते हैं। फिर हस्ताक्षर लिये जाते हैं और जब पूरे हस्ताक्षर हो जाते हैं, तब सरकार उस पर रिफ़ेरेण्डम लेने को बाध्य हो जाती है। इसे "रीरम्युलेन्डे इनीशियेटिव" कहते हैं।

जनरल इनीशियेटिव

दो कैबिनेट्स में इसके विपरीत, आवश्यक हस्ताक्षरों से युक्त प्रस्ताव या मस्यदा आते ही कौंसिल उसका मूल सिद्धांत जनता में वितरण कराकर इस बात पर उसका मत ले लेती है कि इस प्रकार का कानून बनना आवश्यक है या नहीं। यदि जनता विपक्ष में मत देती है तो प्रस्ताव गिर जाता है। यदि पक्ष में देती है, तो कौंसिल उसका नियमित मस्यदा तैयार कर उस पर फिर लोकमत लेती है।

जो, मतदाताओं का बनाया हुआ प्रस्ताव या कानून, केन्द्रीय सरकार को पसन्द आ जाता है यह साधारण रूप में भी पेश किया जाय तो सरकार उसे स्वीकार कर निरोपकों द्वारा उमरा मस्यदा तैयार कराती है। फिर उस पर कार्यकारिणी, विचार, और आवश्यक परिघर्तन-परिचर्चा कर, उसे व्यवस्थापिका को भेज देती हैं। व्यवस्थापिका में फिर उस पर विचार संशोधन आदि होते हैं और तब उस पर लोकमत लिया जाता है। इसे "जनरल इनीशियेटिव" कहते हैं।

आम तौर पर 'इनीशियेटिव' का प्रयोग जनता बहुत कम करती है। बहुधा छोटे मोटे दल या अल्पसंख्यक समूह ही इसका आश्रय लेते हैं। नीचे लिखे एक इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि इस पद्धति के विरुद्ध जितनी बातें लोगो ने कही थी, वे अनुभव में मिलनी वे बुनियाद साधित हुई हैं —

जिले वर्ष 'इनीशियेटिव' की संख्या कितने स्वीकृत

बौंद	१८४५ से १९१२ तक	७	३
वर्न	१८६३ से १९१२ ,,	६	४
जूरिच	,, से १९०८ ,,	११	१
आरगाउ	१८६३ से १९१२ ,,	६	३
धुरगाउ	,, ,, ,, ,,	३	१
मैंट गाल	,, ,, ,, ,,	३	१
जेनेवा	,, ,, ,, ,,	६	२
बमले (नगर),,	,, ,, ,, ,,	१२	२

इन में बहुत से प्रस्ताव क्रांतिकारी और धनिकों की मन्पत्ति पर हाथ डालने वाले भी थे, परन्तु जनता ने मन्त्र अस्वीकार कर दिये। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि वर्ग शासन में शिष्टि कहलाने वाले दल इतने शक्तिहीन हो जाते हैं कि वे प्रजा को चूमने वाले और हमका जीवन कष्ट मय बना देने वाले कानून बट्टे किचिद् भी नहीं दिखाने, किन्तु अशिष्टि और उनकी घृणा की पात्र जनता कभी उनकी स्वार्थी, अनुदार और अत्याचारी नहीं बनती।

यह प्रथा अनेक देशों में इतनी लोकप्रिय हो गई है कि यह म्युनिमिपैलिटीज़ में तो प्रायः अमेरिका, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के प्रत्येक शहर में प्रचलित है। हाँ, प्रत्येक जगह 'इनीशियेटिव' के प्रयोग के लिए मनदावाओं के हस्ताक्षरों की संख्या भिन्न-भिन्न है।

कहीं, यदि 'इनीशियेटिव' द्वारा आए हुए प्रस्ताव, मंशोधन या कानून को म्युनिसिपल कॉमिन ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेनी

है तो उस पर लोकमत नहीं लिया जाता। हाँ यदि उसमें कुछ संशोधन किया जाय तो मूल और संशोधित दोनों पर लोकमत लिया जाता है। (Commission Government. Page 153-162, Beard's American City Government Page 68 & Burnett's Operation of the Initiative, Referendum and Recall in Oregon)

‘इनीशियेटिव’ की मिसाल के लिये प्रायः वे ही नियम हैं, जो रिटैरेण्डम के। हाँ, जिला में कहीं २ प्रस्तावित कानून या संशोधन के पक्ष में प्रस्तावक की दो हुई मुख्य दलील भी जिला कौंसिल की तरफ से छपवा कर मतदाताओं में घाटी जाती हैं।

जिले का ‘इनीशियेटिव’

यदि कोई बैरटन कोई नया कानून या संशोधन रखना चाहती है, तो वह बैरटन की कौंसिल में रक्खा जाता है। कौंसिल के स्वीकार कर लेने पर वह दूसरी बैरटन्स की कौंसिलों को भेजा जाता है। यदि ८ बैरटन्स उसका समर्थन कर देनी हैं तो केन्द्रीय सरकार उस पर रिटैरेण्डम लेने को बाध्य हो जाती है।

मन लेने का समय

‘इनीशियेटिव’ द्वारा जितने कानून या संशोधन आते हैं, उन में कोई अत्यन्त आवश्यक हा, तो उस पर जल्दी लोकमत लिया जाता है। अन्यथा प्रत्येक जिले में और केन्द्रीय सरकार की ओर से भी वर्ष में दो या तीन ऐसे मसौदा निश्चिन कर दिये जाते हैं, जिनमें ऐसे मसौदा कानूनों और संशोधनों पर मन ले लिये जाते हैं।

कुछ विशेष मरक्षण

हम बता चुके हैं कि यह भव होतें हुए भी स्वार्थीदल बीच २ में अपनी चालें चलते रहते हैं। जब 'रिक्रैरेण्डम' का प्रश्न उठा था और वह स्वीकार किया जा रहा था, तब स्विम संघ के प्रेमिडेंट रहे हुए वहाँ के एक नेता मि० वैनटी ने उसका विरोध किया था। उसने जनता का मज़ाक उड़ाने हुए कहा था कि —

“एक ग्वाले या माईम के, कमर्शोन रोड गगन में लेकर, उस पर मत देने का जाते हुए की कल्पना तो करों, कितनी हास्यास्पद बात मालूम होती है ?”

यद्यपि उनके इस प्रलाप का अनुभव और जनता ने झूठा साबित कर दिया और आज वहाँ की जनता इस प्रकार के राज-नैतिक दलों और नेताओं की बातों पर धमल न कर के अपनी स्वतंत्र बुद्धि का उपयोग करती है, तथापि ऐसे लोगों को जब अवसर और अधिकार मिलता है, तब वे अपनी चाल में बाध नहीं आते।

ऐसे लोगों के अपने अधिकार बढ़ाने के कुछ उदाहरण हम ऊपर दे चुके हैं। एक और भी चालाकी वे करते थे। सर्वत्र की तरह वहाँ भी व्यवस्थापिका को कानूनों से मंजोर्जन करने या उन्हें रद्द कर देने का अधिकार था ही। प्रेमिडेंट सा भी विरोध अवस्थाओं में विभी कानून को स्थगित या नामजूर कर देने के अधिकार थे। इसी प्रकार व्यवस्थापिका को बिना 'रिक्रैरेण्डम' के कानून जारी करने का तो अधिकार न था, परन्तु ज़रूरी प्रश्न स्थगित होने पर प्रस्ताव पार करने का अधिकार था। ये प्रस्ताव तात्कालिक आरग्यस्ताओं के लिये एर्दिनेन्मों के समान ही होते थे।

यस इन्हीं अधिकारों का उपयोग करके उन्होने जनता के बनाए कानूनों को रद्द और स्थगित करना एवं प्रस्तावों के बहाने अपने अनुकूल कानून आदि बनाने शुरू कर दिये ।

परन्तु जनता ने जल्दी ही उनकी इस चाल को परख लिया और उसने उन का इलाज नीचे दिये संरक्षणों द्वारा कर दिया, अर्थात् जनता ने क्रमशः निम्न नियम बना दिये:—

- १—कोई जरूरी कानून (Emergency Bill) या प्रस्ताव म्यूनि-सिपैलिटियों के ब्योरोस के अधिकार कम न कर सकेगा ।
- २—किसी का मताधिकार एवं किसी संस्था या व्यक्ति का 'लाइसेन्स' एक वर्ष से अधिक के लिए स्थगित न कर सकेगा ।
- ३—किसी जायदाद या जिम्मीदारी को मोल लेने, बेचने, या पांच साल से अधिक के लिए किराये पर लेने का अधिकार न देगा ।”

पाठक समझ सकते हैं कि ये सब उपाय अपने दल के मत-दाता बढ़ाने के लिए व उन्हें मताधिकार दिलाने के लिए एवं विपक्षी दल के मत घटाने के लिये आज भी काम में लाये जाते हैं । इसी चाल का रोकने के लिए ये नियम हैं । इसी प्रकार Oregon के एक कानून में कहा गया है कि:—

- ४—“कोई जरूरी कानून, किसी पद या मसूरा करने वाले या नया उद्घाटन करने वाले, अथवा अधिकारियों के वेतन, नौकरी की मियाद एवं उनके कर्तव्यों में परिवर्तन करने वाले कानूनों को स्थगित या रद्द नहीं कर सकेगा ।”

इसी तरह कैलिफोर्निया में—

५—“किसी जरूरी क़ानून या प्रस्ताव के द्वारा किसी व्यक्ति को मताधिकार, कोई विशेष अधिकार, कोई विशेष सुविधा और कोई विशेष आय का साधन न दिया जायगा।”

मि० Lowell ने अनेकों प्रमाण देकर बतलाया है कि इन अधिकारों का अधिकारियों ने काफी दुरुपयोग किया था। अकेले दक्षिणी डकोटा में १२५१ क़ानूनों में से, जरूरी प्रस्तावों द्वारा ५३७ क़ानूनों पर जनता का मत नहीं लिया था। इसी-लिए वहाँ की जनता ने अन्त में निश्चय कर दिया कि—

६—“कोई जरूरी क़ानून बनाया जाय तो व्यवस्थापिका उसके तत्काल प्रयोग में लाए जाने की आवश्यकता प्रमाणित करने वाले कारण उसके साथ छापे। इसके बाद यदि उसे दोनों व्यवस्थापिकाओं के निर्वाचित सदस्यों के दो तिहाई मत मिल जायें और न्यूनिस्पैलिटी के (तीन चौथाई) निर्वाचित सदस्य उसके पक्ष में मत दे दें, तथा गवर्नर भी उसकी स्वीकृत दे दे, तो वह बिना जनता का मत लिये अमल में आ सकता है।

(अ) यदि गवर्नर स्वीकृति न दे और उमका बनना जरूरी हो, तो वह फिर दोनों व्यवस्थापिकाओं में रक्खा जाय। इस प्रकार दुबारा रखने पर यदि उसे दोनों ममाओं में—प्रत्येक में—निर्वाचित सदस्यों के (तीन चौथाई) मत मिल जायें, तो वह अमल में लाया जा सकता है।”

७—इसी भाँति विस्कीन्मिन में:—“कोई जरूरी क़ानून ३० दिन से अधिक, बिना जनता की स्वीकृति के अमल में न लाया जायगा। अर्थात् आवश्यक स्थिति का सामना करने के लिये व्यवस्थापिका उसे स्वीकृत कर अमल में ले आ सकती है, परन्तु एक माम के भीतर उसे जनता से स्वीकार

करा ही लेना चाहिये, अन्यथा, वह 'अपने आप रह हो जायगा ।"

इस प्रकार जब बुराई के प्रायः सब मार्ग बन्द हो गए और यह प्रमाणित हो गया कि साधारण जनता की सामुहिक बुद्धि शिक्षित व्यक्तियों और उनके छोटे मोटे दलों से अधिक विचार-शील, दीर्घ दृष्टी और उदार है, तब उन्होंने 'एक सुरील लडके' या "जिम्मेदार प्रतिनिधि" की तरह काम करना शुरू किया। स्पष्टतः इस प्रकार विचारा हुए बिना ठीक रास्ते पर न आने की मनोवृत्ति के कारण हजारों वर्षों से चले आने वाले हमारे सामाजिक और आर्थिक भेद भागों से उत्पन्न संस्कार ही हैं।

कुछ भी हो, यह स्पष्ट है कि जो लोग रूस की 'लाल क्रांति' के दिन नहीं देखना चाहते, उनके हित की दृष्टि से भी अब तक के आधिपत्य तुस्का में वे ही सर्वोत्तम हैं। और यह तो मसाले भर के इतिहास का फैसला है ही, कि जनतंत्र समाज में भेद-भाज वर्तमान हैं, लोगों में एकाग्र व्यक्ति भी कठिनता से ऐसा मिल सकता है, जो इन भेद भागों से सब अवस्थाओं में ऊपर रह सके। इसी लिए एकतंत्री-सत्ता का विरोध उसके जन्म काल से होता रहा है और आज वह नाम मात्र को यहीं यहाँ वर्तमान है। ऐसी दशा में किसी एक वर्ग के हाथ में शासन के अस्त्र धनाने का मर्याधिकार भी स्वतंत्र से खाली कैसे प्रमाणित हो सकता था? वही दुश्मन भी और उसी का फल आज का विश्वव्यापी प्रतिनिधित्व और नियन्त्रित राज्यतन्त्रों के प्रति घोर अविश्वास है। 'रिकैरेण्डम', 'इनीशियेटिव' और 'रिकाल' की त्रिपुट्टी इस अविश्वास के सब से अधिक कारणा को दूर कर देती है। इस के द्वारा जनता स्वयं एक तीसरी व्यवस्थापिका सभा बन जाती है। इस प्रकार तीनों ही व्यवस्थापिकाएँ शासन के अस्त्र धनाने और उसे चलाने को स्वतंत्र भी रहती हैं और प्रत्येक दूसरी के

दवाब और प्रभाव से 'दायित्व' की मावना के साथ भी चलती हैं। संक्षेप से कहें तो शेर-बकरी को एक घाट पानी पिलाने और एक साथ रखने की यदि कोई व्यवस्था हो सकती है तो वह यही हो सकती है।

सफलता के मुख्य साधन

किन्तु जैसा कि हम कह चुके हैं, इसकी सफलता कुछ विशेष स्थितियों पर निर्भर है। वे सब तो यहाँ नहीं दी जा सकती; परन्तु उनमें से मुख्य-मुख्य संक्षेप से हम यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए रखते हैं:—

१—स्विटजरलैंड में इसकी सफलता का रहस्य यह है कि यहाँ चुनाव की पद्धति ऐसी है, जिसमें उम्मेदवार न तो विशेष व्यय करना पड़ता है और न उसके लिए यह आवश्यक है कि उसमें कोई विशेष साम्प्रतिक योग्यता हो। चाहे तो वहाँ निःसंकोच एक गरीब किसान या मजदूर भी खड़ा हो सकता है। मत लेने आदि की व्यवस्था का सारा खर्च सरकार उठाती है। मतदाताओं के लिए कैम्प आदि भी उम्मेदवार को नहीं बनाने पड़ते। न ही उसे विशेष प्रचार करना पड़ता है। उसे राजनैतिक जीवन बनाने में यदि कुछ खर्च करना पड़ता है तो केवल समय या इधर-उधर जाने आने का किया। विस्काउंट ब्राइम के शब्दों में—
“इंग्लैंड में जितना एक उम्मेदवार को अपनी सफलता के लिए खर्च करना पड़ता है, उतने में बहाँ मारे देश की व्यवस्थापिका सभा का चुनाव हो जाता है।”

२—चुनाव के आम पास किसी उम्मेदवार का किसी संस्था या व्यक्ति को दान व पुरस्कार देना वर्जित है। क्योंकि आम

तौर पर चुनाव की रिश्तत इमी रूप ॥ दी जागी है । इस लिए मतदाताओं को गरीबने का द्वार प्राय बन्द-मा है ।

- ३—सरकार या कॉमिलों को गिना जनता की स्वीकृति न किसी को कोई 'पदवी' देने का अधिकार है, न आजीविका (जागीर आदि) न ठेके आदि लाभ के अन्य साधन । और चूं कि जो दल जीत जाना है, वह (प्रतिनिधितन्त्रा में) इस ही प्रकार की गैरता द्वारा अपने पक्ष के मतदाताओं के नेताओं को सन्तुष्ट किया करता है, अतः इस साधन के अभाव के कारण वहाँ दलबन्दी का महत्व नहीं बढ़ पाता ।
- ४—उपरोक्त व्यवस्था के कारण वहाँ न धनिक प्रजा को अधिक घुस मरते हैं न शामक, और इसलिये लोगों को गहरी दरिद्रता के फट्ट का अनुभव नहीं होता । फल यह होता है कि वहाँ भ्रष्ट बुझाने के लिए कोई किमी दल का अनुयायी नहीं बनता । साम्यवादी तक वहाँ के युवक रोटी के प्रश्न से तग आकर नहीं बनते । जो जिस राजनैतिक विचार को अपनाता है, वह उसकी उपयोगिता का पायल होने ही के कारण अपनाता है । इसी लिए वहाँ केवल मच्छेसिद्धांतों, एष सबे सिद्धान्तवादिया को ही कुछ अनुयायी मिलते हैं । दूसरे देशों की तरह राजनैतिक व आर्थिक लाभ के लिए "गगा गग गगा-दास, जमुना गए जमुनादाम" वाली कटारत चरितार्थ करने वालों का वहाँ प्राय अभाव है ।
- ५—इस पद्धति की बदौलत सम्प्रदायवादिया और नफली राजनैतिक 'लेयल' लगाने वालों की दाब नहीं गलती । अनुभव से जनता इनकी दलबन्दीयों का खोखलापन समझ गई है और वह उनकी बातों पर आवश्यक से अधिक ध्यान नहीं देती । इसके अनिश्चित सर्वसाधारण को मताधिकार है । और

सर्वसाधारण में सदा बहुमत ऐसा रहता है, जो न्याय-निष्ठता की ओर मुक्तता है। क्योंकि ग्रामों में वही भी विशेष धार्मिक द्वेष नहीं होता। यह तो शहरों ही की वरकत है और उसका क्षेत्र अधिकांश में शहर के आस-पास ही रहता है।

६—अधिकारियों को न बड़ी-बड़ी पेशानें मिलती हैं और न विशेष मान आदि। फलतः वहाँ किसी पद का कोई महत्व नहीं है। और जीतने वाले दल इसी पुरस्कार का प्रायः मतदाताओं से इत्तार किया करते हैं।

७—सर मुख्य कानून स्वीकृति के लिए जनता के सामने रखे जाते हैं और इसलिये व्यवस्थापिका ही क्या, सरकार तक में किसी दल की प्रधानता का कोई मूल्य नहीं होता। धनिक लोग जानते हैं कि इन्हें खरीदने से कोई लाभ नहीं। और सारी जनता को खरीदने या खुरा करने के लिए किसी के पास साधन नहीं हो सकते।

८—अप्रिय और जनता के कोपभाजन बन जाने के भय से कोई दल अपनी वृद्धि के लिए बहुत उग्र उपायों से काम नहीं लेता।

९—दिन-रात शासन में सीधा भाग लेने से साधारण जनता राजनीति की पेचीदगियों को बहुत कुछ समझ गई है और अब वह किसी के धोखे में नहीं आती।

१०—चुनाव के क्षेत्र छोटे-छोटे बना दिये गये हैं। उनमें से उनके जाने-बूझने व्यक्ति ही खड़े होते हैं और चुनाव की व्यवस्था भी जनता के चुने हुए व्यक्तियों द्वारा ही होती है।

११—ग्राम-मंचायतें जीवित और सुसंगठित हैं और इसलिए शहरों में सुसंगठित हुए दल वहाँ के मतदाताओं को अपने प्रचार क्षेत्र में नहीं ला सकते।

१२—न्यायाधीश, मन्दिरों के पुजारी, रजिस्ट्रार और शिक्षा विभाग के अधिकारी व अध्यापक जनता द्वारा चुने जाते हैं या अन्य विधानों द्वारा उनकी छोटी प्रत्येक जिले की जनता के हाथ में होती है और इसलिए वे संगठित रूप के किसी राजनैतिक दल से नहीं मिलते और मिल पाते। न वे मत-दाताओं पर प्रभाव डालते हैं।

१३—व्यवस्थापिका के सदस्यों को इतनी मामूली आय होती है कि योग्य व्यक्ति अन्य व्यवसाय द्वारा उससे बहुत अधिक कमा सकता है। इसलिए चालाक और लालची लोगों को उनमें जाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता।

१४—महत्वपूर्ण वैदेशिक सधियाँ भी जनता के सामने रंक्ष्यी जाती हैं और इसलिये कोई दल अकेला वैदेशिक व्यापार आदि से भी व्यवस्थापिकाओं व मंत्रिमण्डल द्वारा लाभ नहीं उठा सकता।

१५—व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी की मियाद कुल तीन वर्ष की होती है।

१७—जनता जब चाहे, किसी सदस्य वा दल को व्यवस्थापिका से हटा सकती है।

इन सब बातों के कारण ही यहाँ वे सराधारियाँ सार्वजनिक जीवन में प्रवेश नहीं कर पातीं, जिनसे दूसरे देश पीड़ित हैं। और यही कारण है कि मि० माइस के शब्दा में "स्विट्जरलैंड का शासन सबसे सस्ता (लोगों पर सब देशों से कम टैक्स लगाने वाला) और साथ ही सब से अधिक मुख्यस्थित है। न्याय शुद्ध और सस्ता है। शिक्षा का खूब प्रचार है। प्रायः प्रत्येक प्रामाण्य पढ़-लिख सकता है। न्यूनिमिपल शासन आदर्शों

है। मइकें और मार्बजनिक स्थान प्रशंसनीय हैं। सर्वत्र शान्ति है। मेना विभाग अच्छा है और जनता मैनिक शिक्षा पाती है। व्यक्ति की, बोलने की और लिखने की पूरी स्वतंत्रता है और सब लोगों में दायित्व की भावना है। छुट्टाई-बढ़ाई की भावना का अभाव है और आर्थिक अमानता भी और देशों में बहुत कम है। उमोंदार प्रायः हैं ही नहीं। पेशेवर राजनीतिज्ञ देखने की भी नहीं मिलते।" (Modern Democracies Vol I & II)

इंजीनेयरेटिव या विधान निर्माणधिकार की दरखास्त



मेवा में श्रीमान.....

हम नीचे हस्ताक्षर करने वाले..... राज्य के नियमित मतदाता..... नगर व जिले के निवासी यादर आदेश (Order) देते हैं कि अमुक नाम का कानून या अनुक आजा या कानून के लिए प्रस्तावित अनुक मंशोधन मार्बजनिक स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए जनता के मामले..... नगरीय तक पेश कर दिया जाय।

रिफ्रेरेण्डम की तरह

हस्ताक्षर

नोट—यह दरखास्त सरकारी कानूनों आदि पर ६ माम के भीतर और जिला बोर्ड, चुंगी आदि के फैसलों के रिफ्ट तीन माम के भीतर पेश हो जानी चाहिये।

PLLBISCITE प्लैबिस्साइट या आत्मनिर्णय



यह 'रिक्रैरेण्डम' का ही एक भेद है। कानूनों पर लोकमत का फैसला, जिस प्रकार 'रिक्रैरेण्डम' कहलाता है, उसी प्रकार महत्त्वपूर्ण प्रश्नों या राष्ट्रों पर विश्वास-अविश्वास के प्रश्नों पर जब लोकमत द्वारा निर्णय कराया जाता है तब उसे 'प्लैबिस्साइट' कहते हैं।

परन्तु यह 'रिक्रैरेण्डम' का भेद उसी अंश में है, जहाँ तक 'लोकमत लेने' के उद्देश्य का सम्बन्ध है। अन्य बातों में उसका वास्तविक लोकमत होना या न होना बहुत कुछ उस स्थान की परिस्थिति पर निर्भर है। कारण स्पष्ट है। 'रिक्रैरेण्डम' एक व्यवस्थित स्थिति और शासन व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाला अस्त्र है, एवं इस लिये उसका परिणाम भी बहुत कुछ यही होता है, जो होना चाहिए और जिसके लिए उसका आविष्कार हुआ है।

परन्तु 'प्लैबिस्साइट' प्रायः ऐसी स्थितियों में लिया जाता है, जिनमें लोग पदाचित ही सर्वथा स्वतंत्र और निराङ्क भाव से अपना मत दे सकते हैं। फिर भी इसमें मन्देह नहीं कि यह बहुत प्राचीन और उपयोगी पद्धति है और यदि इसका ठीक-ठीक उपयोग हो, तो सत्ता की आज्ञा की बहुत सी पठनाइयाँ सके द्वारा हल हो जाती हैं।

एक प्रकार से यह जनता के आत्मनिर्णय के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने का सब से बड़ा साधन है।

व्यावहारिक विधि

वैसे इसकी व्यावहारिक विधि सरल है। अर्थात् जिस प्रश्न पर लोकमत लेना हो उसकी तिथि कुछ मास पूर्व निश्चित हो

जाती है। इस के बाद पक्ष विपक्ष के प्रचारक जनता को अपने-अपने पक्ष में लाने के लिए प्रचार करते हैं एवं अन्त में निश्चित तिथि पर उस पर रिक्रैरेण्डम की पद्धति द्वारा लोम्मत ले लिया जाता है, जो कानून की तरह दोनों दलों को मानना पड़ता है।

स्थिति का अन्तर

पाठक देखेंगे कि कैसे इस में और रिक्रैरेण्डम में कोई अन्तर नहीं है। परन्तु जैसा कि हम कह चुके हैं, दोनों के व्यवहार की स्थिति सर्वथा भिन्न होती है। क्योंकि 'रिक्रैरेण्डम' तो जनता और जनता के प्रतिनिधियों के बीच में ही होता है। परन्तु "प्लैबिस्साइट" प्रायः दो स्वतंत्र शासकों और जनता के बीच में होता है।

उदाहरण के लिये दो राज्यों के प्रभावक्षेत्र में एक स्वतंत्र प्रदेश है। इस प्रदेश में या तो कोई सुगठित राज्य नहीं है, अथवा है, तो छोटा होने के कारण अपनी रक्षा करने में असमर्थ है। स्वभावतः उसे दोनों ही शासक या राज्य अपने अपने राज्य में मिला लेने को उन्मुख हैं। दोनों ही उसे हथियाने को अप्रत्यक्ष चालें चलते हैं और साथ ही एक दूसरे की चालों को व्यर्थ बनाते हैं।

साथ ही मान लीजें कि या तो उक्त प्रदेश या राज्य इतना छोटा है कि उस के लिये युद्ध की जोखिम लेना बेकार है, अथवा अन्य परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जिन के कारण युद्ध द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करना उचित नहीं है।

ऐसी दशा में दोनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं या कर लिये जाते हैं कि इस प्रश्न का निर्णय उक्त-प्रांत की जनता में

ही करा लिया जाय। उसमें मे बहुमत जिस राज्य में शामिल होना चाहे, हो जाय।

इसके बाद दोनों की ओर से यह प्रयत्न शुरू होता है कि जनता हमारे पक्ष में मत दे। साथ ही, इस सम्बन्ध में कोई पक्ष अनुचित रीति से मत प्राप्त करने की चेष्टा न करे, इसकी शर्तें दोनों ओर से रक्खी और तय की जाती हैं। इसके लिये बहुधा किसी मित्र या निर्पक्ष राज्य के प्रबन्ध और उसकी देख-रेख में काम होता है एवं अन्त में उस प्रान्त का बहुमत जिस राज्य के पक्ष में हो, उसमें यह प्रदेश मिला दिया जाता है। दोनों ओर से उक्त भू-भाग के निवासियों को भिन्न भिन्न प्रकार के प्रलोभन और सुखियाओं को आश्वासन दिये जाते हैं।

कहीं-कहीं की जनता स्थायी रूप से अपने भाग्य का फैसला करने से इन्कार कर देती है और केवल दस, बीस या तीस वर्ष की मियाद निश्चय होती है। वैसी दशा में उक्त फैसला उसी मियाद तक कायम रहना है। उसके बाद फिर, यदि वही स्थिति घटी रहे तो, प्लैनिस्साइट द्वारा उसका भविष्य निर्णय होता है।

वास्तविक रूप

यह इसके आधुनिक रूपों में से एक है। इसका अमली रूप इससे उत्कृष्ट है और उसके दर्शन संसार के अन्धकार में पड़े हुए इतिहास के राइदरों में कभी-कभी हो जाते हैं। हमारे देश के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि इसका जन्म सुदूर प्राचीन काल में 'जातियों' Tribes के युग में हुआ था। क्रमशः जब स्वतंत्र जातियाँ ने राज्यवाद में अपनी रक्षा के लिए 'मंच' बनाने शुरू किये, तब ऐसे प्रदेशों के बारे में, जिनमें दो या अधिक जातियाँ बसी होती

थो, प्रायः आपस में विवाद खड़ा हो जाता था कि उन्हें किस संघ में मिलना चाहिये । और चूँकि उद्देश्य सबका एक होता था और साथ ही सभी प्रजापदी शासन के पक्षपाती होते थे—इस संघ-संगठन का ध्येय भी अपनी आस्तित्व रक्षा होता था—अतः जनता स्वयं ही सार्वजनिक मत द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करती थी । सिकन्दर की चढ़ाई के समय तक यह पद्धति प्रचलित थी और कई जातियों ने उस समय भी उसकी वश्यता स्वीकार करने न करने के प्रश्न का निर्णय इस प्रकार सार्वजनिक मतद्वारा किया था । ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं, जिन्हें हम एक दूसरी “प्राचीन प्रजातंत्रों” सम्बन्धी पुस्तक में देंगे । यहाँ हमने उसके मूल रूप की विचिद्र मूलक दिसा देने के उद्देश्य से इतना-सा उल्लेख कर दिया है ।

किन्तु आधुनिक युग में इसका पुनर्जन्म जिस रूप में हुआ और अब जिन रूपों में इसका विकास हो रहा है, वे प्रायः सर्वथा दूर हैं । उदाहरण के लिए इस युगमें मग्न में पहले फ्रांस में, फ्रान्स की प्रसिद्ध क्रान्ति के बाद इसका प्रयोग हुआ था । उस समय प्रजा के मामले सन् १७९३ में यह प्रश्न रखा गया था कि वह राज (एक तन्त्रीय) व्यवस्था में रहना चाहती है या प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में ।

सन् १७८९ में सन् १७८३ के बीच में ही फ्रांस ने इटली के जो भाग जीत लिए थे उनमें से अधिगोन, सरोय और सीम की जनता में इस बात पर ‘प्लैबिस्माइट’ लिया गया था कि वे फ्रांस के अधीन रहना चाहते हैं या इटली के, और अन्त में बहुमत के अनुसार ये प्रान्त फ्रांस में मिला लिये गये थे । इसी तरह सन् १७९८ में मुल्हासन और जेनेवा के प्रजातन्त्र फ्रांस के प्रजातन्त्र में मिला लिये गये थे ।

सन १८४८, १८६० और १८७० में "प्लैबिस्माइट" के द्वारा ही इटली ने ये भाग फिर वापिस ले लिये ।

परन्तु ये मत जिस तरह लिये गए थे, उनसे देखते हुए इन्हे लोकमत का प्रदर्शन कहना, 'लोकमत' शब्द का मञ्जाक लड़ाना है । क्योंकि इन्हीं के सम्बन्ध के साहित्य से यह स्पष्ट है कि ये मत केवल गालवाजी द्वारा ही नहीं प्रत्युत भयानक अत्याचारों और आतंक एवं घुंम द्वारा प्राप्त किये गये थे ।

सन १७६६ ई० में फ्रान्स में फिर "प्लैबिस्माइट" का ढोंग रचा गया और उसके द्वारा ३ डिपटेटर बनाए गए । इसके एक वर्ष बाद ही इसी विधि द्वारा पहले नैपोलियन फ्रान्स का आर्जीवन प्रेन्सिपेन्ट बना और उसके बाद सन् १८०४ में वंशपरम्परागत सम्राट बन गया । (Historians' History Vol. XII Page 411 to 415 and, A Monograph on Plebiscites by S Wambaugh, New York).

प्लैबिस्माइट के इन परस्पर विरोधी परिणामों का देखकर बहुत लोग इस संस्था और पद्धति को ही त्याग्य समझने लगे हैं । Mr. Yves Guyot ने तो यहाँ तक कह दिया है कि "वास्तव में प्लैबिस्माइट मतदानाओं को आत्मघात कर लेने का आमंत्रण है ।" परन्तु जैसा हम बता चुके हैं, ये सब इस पद्धति के दुरुपयोग का परिणाम है । जिस तरह साम्राज्यवादियों ने प्रतिनिधिमन्त्र और प्रजामन्त्र आदि का दुरुपयोग कर इन संस्थाओं को अप्रिय बना दिया है, ठीक वही दशा और गति इस "प्लैबिस्माइट" की है ।

राज्य विस्तार का साधन

और अब तो प्राचीन कालीन धार्मिक-यज्ञ-मदति की तरह स्वार्थी लोगों ने इसे राज्य विस्तार का साधन बना डाला है। उदाहरण के लिये जब पिछले महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हो गई और जर्मन शासन अस्त व्यस्त हो गया, तब जर्मनी के दुकड़े करने और उनमें से कुछ को हड़प जाने के लिए उन्हें 'प्लैविस्माइट' द्वारा अपना भविष्य-निर्णय करने को कहा गया। जनता कुछ तो तत्कालीन शासन से ऊँची हुई थी। युद्धकाल में उसे और भी यातनाएं सहनी पड़ी थीं। यह भी आशांका होनी स्वाभाविक थी कि विजयी राष्ट्रों के विरुद्ध कुछ करने से उन्हें बेऔर सतावेंगे। इधर विजयी राष्ट्रों को, अन्य उपायों से भी लोगों को आतंकित करने का अवसर मिल गया था। परिणाम यह हुआ कि Schleswig (उत्तरी जर्मनी) डेन्मार्क में शामिल हो गया और Upen तथा Malrnedy बेल्जियम में मिल गये। इसी प्रकार 'मार' प्रांत के लिए निश्चय हुआ कि उसका भविष्य-निर्णय १५ वर्ष बाद प्लैविस्माइट द्वारा किया जाय।

सब से ताजा उदाहरण व्यक्तियों पर "प्लैविस्माइट" द्वारा लोकमत लेने का, हिटलर का है, जो हाल ही में हुआ है।

इसका दुरुपयोग एक और तरीके से भी होता है। जिस भू-भाग को कोई देश इस अस्त्र द्वारा हड़पना चाहता है, वह उसमें अपने देश या समुदाय के लोगों को भिन्न-भिन्न बहानों से और भिन्न-भिन्न अवसरों से लाभ उठाकर, बहुत बड़ी संख्या में आबाद कर देता है। और कई जगह तो अमेरिकन 'रेट इंटी-यन्स' वा अफ्रीकन जातियों की तरह स्थानीय जनता को विभिन्न उपायों से नष्ट कर मर्चबा नगण्य ही बना दिया जाता है।

इन सब बातों से स्पष्ट है कि जिस प्रकार प्रजातंत्र, डिमो-क्रेसी आदि नामों का दुरुपयोग कर वर्गशासन कायम किये और रखे जा रहे हैं, उमी प्रकार इस पवित्र मंस्था का भी भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है ।

वास्तव में इसका उपयोग होना चाहिये, प्रत्येक देश के लिए आत्म-निर्णय में । अर्थात् वह किस प्रकार की शासन व्यवस्था चाहता है ? इस समय वह जिस शासन में है, उसे वह नापसन्द करता है या नहीं ? आदि-आदि,

इसी प्रकार आज जगह-जगह देशी राज्यों से लिये हुए भूभागों और छावनियों आदि को लौटाने तथा घरमा, सीलोन आदि से भारत के सम्यन्ध आदि प्रश्नों पर इसका प्रयोग हो सकता है । परन्तु करे कौन और कहे कौन ? न प्रदेशों में इतना मनुष्यता का अभिमान है और न शासकों में उन्हें पालतू बन्दरों के जंगल से अधिक मूल्य देने की भावना ।

RECALL रिकाल (पुनरावर्तन)



उपरोक्त त्रिपुटी के एक भाग का विवेचन रह गया था । वह है "रिकाल" की पद्धति । इसका अर्थ है वापिस बुलाना अर्थात् किसी नियुक्त व्यक्ति को पदच्युत करना ।

आवश्यकता

इसकी आवश्यकता भी ऊपर के ग्यण्डों में वर्णित अधिकारों के दुरुपयोग के कारण ही हुई । वैसे तो सिद्धान्त की दृष्टि में भी जन-मत्ता की पूरी स्थापना तब ही हो सकती है, जब कि उम्मा शामन के प्रत्येक पुर्जे पर प्रत्यक्ष अधिकार रहे । वह जब देखे कि अमुक पुर्जा घिम गया है, या यंत्र के अनुकूल नहीं है, उम्मे सराही पैदा करता है, तब ही उम्मे निकाल और बदल सके । परन्तु आज की दुनिया में तो सब ही बातें उलटी हैं । उलटी बातों को सीधी कहा जाता है और सीधी बातों को उलटी कहकर बोसा जाता है । जन-मत्ता के नाम पर वर्ग सत्ताएँ स्थापित की जाती हैं और सच्ची जन-मत्ता की बातों को शेखरबिल्ली की कल्पना कहा जाता है । प्रतिनिधि कहलाने वाले मालिक बन बैठते हैं और मालिक गुलाम की तरह बरत जाते हैं । रजक कहलाने वाले भजक का काम करते हैं और रक्ष्य भक्ष्य की तरह काम में लाये जाते हैं । ऐसी दशा में यदि 'रिकाल' के अधिकार को भी "वित्तिप्रों की बकयाम" की श्रेणी में गहरा जाना है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं ।

इमीलिये यद्यपि आम नांग पर यंत्रालयों के मंचालक व्यवहार में 'रिकाल' की पद्धति पर चलते हैं और ग्यगय पुर्जे को

एक मिनट भी यन्त्र में नहीं रखते, परन्तु शासन यन्त्र में उभी नियम का प्रयोग करने का नाम लेते ही बीरला उठते हैं। यन्त्र के लिये तो कहते हैं कि यदि उसमें खराब पुर्जा रहने दिया जाय, तो उस एक पुर्जे के कारण सारा यंत्र बिगड़ जायगा। किन्तु शासन यंत्र के लिये वे ही कहते हैं कि इसमें से खराब पुर्जा हटाने से शासन यंत्र बिगड़ जायगा। पुर्जा खराब हो या अच्छा वह जितनी मियाद के लिये यंत्र में लगाया गया है, उतने समय तक उसमें रखना ही जाना चाहिये।

कारण स्पष्ट है। यंत्र के पुर्जे के सम्बन्ध में बानें करने वाले यंत्र संचालक हैं। परन्तु शासन यंत्र के पुर्जे की हिमायत करने वाले स्वयं शासन यंत्र के पुर्जे हैं। यदि यंत्रों के पुर्जे में भाषण शक्ति होती, तो वे भी इसी तर्क का आश्रय लेते और शायद अपने लिये भीमे और पेन्शन तथा कम्पेन्सेशन (मुआवजा) के नियम बनाने की मांग भी करते। इसीलिये वास्तव में इस तर्क-मरणी को उतना ही मूल्य दिया जाना चाहिये, जितना कि वास्तविक यंत्र के पुर्जे के तर्क का। अस्तु,

इंग्लैंड आदि देशों में, जहाँ यंत्र के पुर्जे ही यंत्र के मालिक हैं, वहाँ बड़े-बड़े पद आदि राजा वा शासन-सभा द्वारा भरे जाते हैं। परन्तु स्विट्जरलैंड, अमेरिका आदि देशों में, जहाँ पूरा न सही, बहुत कुछ यंत्रों पर अधिकार उनके स्यामी-जन समूह का है, वहाँ इनके निर्वाचन की प्रथा है। प्रायः सब जिलों में शासन-यंत्र के सब प्रमुख पुर्जे जनता द्वारा चुने और नियुक्त किये जाते हैं। क्या जिलों की शासन सभाओं के सदस्य, क्या उनके प्रेसिडेंट, व्यवस्थापिकाओं के सदस्य और उनके अध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, जज, रजिस्ट्रार, अध्यापक और क्या भिन्न-भिन्न विभागों के अग्नर एवं पंचायतों के अधिकारी, सब जनता

द्वारा चुनकर नियुक्त किये जाते हैं। इसीलिये यदि जिले की शासन सभा या मंत्रियों और व्यवस्थापिका में विरोध हो जाता है, तो मंत्री त्यागपत्र नहीं देते। क्योंकि वे मीधे जनता के प्रति उत्तरदायी हैं।

जब पहले पहल यह पद्धति चली, तो मनातनी—पुराने ढंग के—नीतिज्ञों ने इसका बड़ा विरोध किया था। कहा गया था कि “इसकी वजह से एक दिन भी शासन यंत्र न चल सकेगा। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ये नित्य आपस में लड़ेंगे और शासन भ्रष्ट होगा।” परन्तु अचपढ़े ज्योतिषियों की तरह उनकी ये सब भविष्यवाणियाँ भूरी प्रमाणित हुईं। इतने वर्ष हो गये, आज तक एक बार भी इसके कारण शासन यंत्र में खराबी होने की नौबत नहीं आई। *Real Democracy in Operation P. 170* आती क्या, कभी इतना विरोध ही नहीं बढ़ा। कारण यही है कि इन पुराने नीतिज्ञों का अनुभव तो वर्गशासन का है, जिसमें दूसरे विचारों का व्यक्ति निम ही नहीं सकता। परन्तु यहाँ न तो वर्गशासन की गुच्छाई है और न उसकी मन्त्रति बढ़ती है।

अमेरिका में इस चुनाव की पद्धति को Long Ballot System “लॉंग बैलट सिस्टम” कहते हैं। परन्तु वहाँ के और स्विटजरलैंड के चुनाव में एक गहरा भेद है। स्विटजरलैंड में प्रत्येक जिले के लोग अपने जिले के अधिकारियों को चुनते हैं और इसलिए उनसे वे परिचित होते हैं। उनके सम्बन्ध में वे अपने विवेक से काम ले सकते हैं और केन्द्रीय सरकार के चुनाव में अपने विवेक से काम लेने के लिए उन्हें इन चुने हुए मायियों में सहायता मिल जाती है। परन्तु अमेरिका में उपरोक्त पद्धति में जो चुनाव होना

है, उसमें देश के किसी भी कोने से उम्मेदवार खड़े हो सकते हैं। इस दृष्टि से लाभ उठाकर वहाँ के पँजीवादी राजनीति में खेल खेलते रहते हैं और प्रायः ऐसे व्यक्तियों की सूची पेश करते हैं, जिनमें दिए व्यक्तियों से मतदाता सर्वथा अपरिचित रहते हैं। उनके बारे में पूँजीवादियों द्वारा अधिकृत समाचार-पत्र जैसा प्रचार करते हैं, वैसा ही विचार बनाकर लोग उनके लिए मत देते हैं। स्वभावतः ऐसी दशा में मतदाता अपने विवेक से काम नहीं ले सकते।

SHORT BALLOT SYSTEM

इस दृष्टि को दूर करने के लिए एक और पद्धति निकाली गई है। इसे "शॉर्ट बैलट सिस्टम" कहते हैं। इसके अनुसार केवल विभागों के अध्यक्षों का चुनाव जनता से कराया जाता है, जो प्रतिद्वन्द्व और काफी क्षेत्र के अधिकारी होने के कारण काफी लोगों के परिचित होते हैं। इससे धनियों के राजनैतिक मठ में कुछ कमी आ गई है।

इस चुनाव के लिये कई जगह उम्मेदवारों को यह शपथ लेनी पड़ती है कि "वह किसी राजनैतिक दल का सदस्य वा पक्षपाती तो नहीं है।"

इन चुनावों में किसी भी उक्त पद के लिए आवश्यक योग्यता वाला कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, इसलिए प्रायः प्रत्येक पद के लिए कई उम्मेदवार होते हैं और जनता जिसे मध्यमे अच्छा समझती है, चुन लेती है।

इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक विभाग के मानहत अधिकारियों की नियुक्ति-अलहदगी वा अधिकार इन चुने हुए अधिकारियों को

होता है। यह मावधानी डभीलिये की जाती है कि किसी विशेष दल के लोग भरती होकर शामन-यन्त्र का दुुरुपयोग न करें।

इस प्रकार चुने हुए शामन के ये प्रत्येक पुर्जे किसी भी समय जनता द्वारा बदले या पदच्युत किये जा सकते हैं। इसे व्यावहारिक रूप देने की तो विधि हैं—

व्यावहारिक रूप—

१—ऐसे अधिकारी के प्रति जो जनता की निश्चित नीति या इच्छा के विरुद्ध आचरण करना है, अथवा किसी एक दल के पक्ष का समर्थन करना है, जनता समारोह पर उस पर अविश्वास का प्रस्ताव पार करती है।

—इस पर उक्त अधिकारी या किसी मौमिन का मदस्य त्याग-पत्र नहीं देता है तो उसे पृथक् करने के लिए एक आवेदन पत्र तैयार कर उस पर २५ प्रतिशत मनदानाओं के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। मनदानाभिस्को में केवल १० प्रतिशत मनदाना ही हस्ताक्षर कर ऐसा आवेदन पत्र भेज सकते हैं। ओकलैंड में १५ प्रतिशत, वल्लाम में ३५ प्रतिशत और ट्रिनिदाद नगरों में ५० प्रतिशत हस्ताक्षर होने का नियम है।

इस पद्धति के द्वारा जनता केवल चुने हुए ही नहीं, मुख्याधिकारियों द्वारा नियुक्त किये हुए अहमियों को भी निराल दिये जाने की मांग कर सकती है।

उक्त आवेदन पत्र पहुँचने पर रिक्लेस्टम की पद्धति में उस पर लोअमव लिया जाता है। 'वैल्ट पेपर' (मनदान पत्र) पर जनता के उसे हटाने के कारण भी छपे रहते हैं और यदि दोषी अहमिर चाहता है, तो उसकी निर्दोषिता प्रमाणित करनेवाली शर्तों भी छपी रहती हैं।

रूस की विशेषता ।

रूस ने इस पद्धति को कुछ विशेषताओं के साथ प्रचलित किया है । यहाँ के विधान के अनुसार, सोवियट रूस में चुन कर भेजे हुए अपने प्रतिनिधि को भी जनता जर चाहे वापिस बुला ले सकती है (\ Rothstein & Soviet Constitution P 20)

कहना व्यर्थ है कि इसका प्रयोग बहुत कम होता है । व्यवस्थापिका के सदस्यों और शासन सभा के विरुद्ध तो और भी कम होता है । कमल जनता के हाथ में इस अधिकार का हाना ही अधिकारियों को ठीक पथ पर रखने के लिये काफी होता है । फिर भी कोई दल व्यर्थ प्रचार कर इसका दुर्प्रयोग न कर सके इसलिए नीचे लिखे सरक्षण अमेरिका ने रखे हैं —

१—दोपी अफसर को अपनी भर्खाई देने का अवसर दिया जाता है ।

२—उसे ६ मास का समय अपनी निर्दोषिता प्रमाणित करने और फिर जनता का विश्वास प्राप्त कर लेने के लिए दिया जाता है । तब तक वह अपने पद पर बना रहता है ।

३—यदि रिजर्वेशन लेने पर जनता “रिफ़ाल” के आवेदन पत्र को नामज़ूर कर देती है, तो इस भगड़े भ अफसर को जो रक्ष्य करना पड़ता है, यह उसे सरकारी ख़ाते में मिल जाता है ।

४—एक बार ऐसा होने पर फिर उसके विरुद्ध पदच्युत करने का आवेदन पत्र नहीं दिया जा सकता ।

(अ) नवादा और उरगोन आदि कुछ राज्यों में ऐसा नियम है कि यदि आवेदन पत्र दुबारा पेश किया जाय और उसके

साथ, पेश करने वाले, पहली बार का मरकारी खर्च शेष में जमा करा दें, तो वह स्वीकार कर लिया जाय।

५—कुछ राज्यों में ऐसा भी नियम है कि उक्त आनेदन पत्र के पक्ष में, कम से कम उतने मतों का बहुमत आने पर ही अधिकारी अलग किया जाय जितने कि उसे चुनने के समय उसके पक्ष में पड़े थे।

इस प्रकार अधिकारियों के लिए इतने सरक्षण हैं कि वे आसानी से हटाए ही नहीं जा सकते। इतना ही नहीं, उल्टे कभी-कभी इन सरक्षणों का दुरुपयोग भी होता है और दोषी अधिकारी बचा लिया जाता है।

“रिकाल” के विरुद्ध दलीलें



हम यह चुके हैं कि इस पद्धति के विरुद्ध बहुत कुछ कहा गया है और कहा जाता है। एक मुख्य दलील यह दी जाती है कि यह अधिकारियों की स्वतंत्रता को छीनती है, उनका साहम कम करती है और उसे अपने कर्तव्य की अपेक्षा लोगों के भाग्य का ध्यान अधिक रखने को बाध्य करती है। और जनता में, विशेषतः चोरी से नशीले पदार्थ आदि लेने देने वाले तथा दूसरे ऐसे धन्धे करने वाले दल होते हैं। वे लोग अधिकारियों पर इस पद्धति की उद्दीलत रौं गाठ लेते हैं। विशेषतः इस लिए कि ऐसे-ऐसे गुटों में बड़े-बड़े प्रभावशाली व्यापारी भी होते हैं। वे किसी अहमर को प्रचार द्वारा अप्रिय बना सकते हैं। अतः यह पद्धति खतरनाक है।

इसमें मन्देह नहीं कि दलील जोरदार है। परन्तु क्या यह भी बात इतनी ही सत्य नहीं है कि, यदि अधिकारियों को बेलगाम

छोड़ दिया जाता है, तो वे बड़ी आसानी से उन प्रभावशाली लुटेरों के हाथ बिक जाते हैं, जिनसे उन्हें नियमित और बड़े-बड़े इनाम मिलते रहते हैं। फिर जब हम सरक्षणों पर दृष्टि डालते हैं, तो तो इन दलीला की कोई गुञ्जाइश ही नहीं रह जाती। सिद्धान्त की दृष्टि से भी जो नियुक्त करता है, उसे निकालने का अधिकार होना ही चाहिये और चासतौर पर हमारे कारखानों और दफ्तरों में क्या नियम होता है ? नियुक्त करने वाला ही निकालने का अधिकारी होना है न ? फिर जनता के लिए ही यह आपत्ति क्यों ? इसके अतिरिक्त इतने वर्षों में भी इस नियम द्वारा कितने अन्याय किये जाने का कोई प्रमाण आज दे सका है क्या, जितने कि दूसरी स्थितियों में होते हैं ? वास्तव में इतने फड़े सरक्षणों के मुकामिले में जनता तो ही ऐसे अस्त्र का प्रयोग करने को उद्यत हो सकती है, जबकि उक्त अधिकारी ने बहुत ही फड़ी अनियमितता या बेईमानी की हो। और उसकी महानुभूति उन मक्कार दलों से तो हो ही नहीं सकती, जिनका उदाहरण दिया गया है, फिर चाहे वे कैसे ही प्रभावशाली क्यों न हों ? यदि यही बात हो तो उसे सब से अधिक, सबसे सम्पन्न राज्य-सत्ताओं से प्रभावित होना चाहिये। परन्तु यह सदा राज-सत्ता की विरोधी रहती है। अतः यदि ऐसा हो भी, तो अफसर के उसका भंडाफोड़ करते ही जनता की महानुभूति उसके माथ हो जायगी।

और आज तो कई देशों में एक दल के बहुमत वाली शासन सभाएँ, न्याय और शासन को अलग करनी हैं। क्या जनता उनसे भी अधिक पक्षपातिनी हो सकती है। मि० गिल्बर्टसन (American City Govt. P 74) ने तो अनुभवों और इतिहास द्वारा यह सिद्ध किया है कि इस पद्धति से शासन की

सर्वाङ्गपूर्णता होती है। और प्रेसिडेंट विल्सन तो इस पर अपने मुख्य थे कि उन्होंने इसे कठिनाई के समय काम आने वाली 'The Gun Behind the Door' 'दरवाजे के पीछे रखी हुई बन्दूक' बताया है। (Commis 107 Government and the Civil Manager Plan P 163)

न्यायाधीशों का पुनरावर्तन

राज्याधिकारियों और प्रतिनिधियों के पुनरावर्तन का बयान हम ऊपर दे चुके हैं। परन्तु अन्त में भी न्यायाधीश और शिष्ट भी चुने जाते हैं। वास्तव में सामान और गानों के समान ही इन दोनों विभागों का सम्बन्ध जनता के हितान्वित से बहुत गहरा है।

यदि न्याय विभाग शुद्ध न हो तो लफ्फों और धनिका की बन आती है। समाज में अनाचार फैल जाता है। न्यायाधीशों को पक्षपात करने में तर नहीं रहता। वे न्याय से अपना परावर्तन का मायन बना लेते हैं।

यही स्थिति गिना की है। शिष्ट की जनता और न्याय के माता पिताओं का कोई भय नहीं रहता। वे अपने ऊपर के अस्मरणों को लुप्त रखकर चाहे जो करते हैं, कोई पृष्ठने वाला नहीं। वे चाहें अपने ढाँचों से दुर्भाग्य बनावें चाहे, 'नमो' कोई हुम्नहार पैदा करें, माता पिता कुछ नहीं कर सकते।

इसी लिये स्विट्जरलैंड, अमेरिका, रूस आदि में उन्हें चुनने की पद्धति है। और पद्धतियों की तरह इसका भी शुरू में काफ़ी विरोध हुआ था। कहा गया था कि न्यायाधीशों को तो मर्यादा स्वतंत्र रखना जाना चाहिये, अन्यथा 'नहीं' यही स्थिति होगी, जो राजाओं के आधीन रहने वाले न्यायाधीशों की होती

है। ये शुद्ध न्याय न कर सकेंगे। लोकमत को देखकर न्याय करेंगे। आदि आदि—

परन्तु व्यावहारिक अनुभव ने साबित कर दिया कि लोगों की ये शकाएँ निर्मूल थीं। जनता एक व्यक्ति की तरह छोटी छोटी बातों में और अनुचित रूप में कभी किसी की आज्ञा की में हाथ नहा डालती। (See-Beards' American City Government P 74)

“निर्णय”—प्रत्यावर्तन

फिर रही सही आराकाओं को दूर करने के लिये एक और विधि निकाल ली गई है। इसे The Recall of Decisions कहते हैं। इसके अनुसार जनता न्यायाधीश को नहीं हटाती, किन्तु उसके जिस फैसले को गलत समझती है, उसे रद्द कर देती है।

परन्तु आश्चर्य है कि यह सुधार भी बिना विरोध के स्वीकृत नहीं हुआ। इसे लोगों ने पुनरावर्तन से भी बुरा बताया और साथ ही दिलायी यह कि व्यवहार में आने पर इसके विरुद्ध की गई दलीलें भी वैसी ही भूठी साबित हुईं।

इस सम्यन्ध में मि० एच० एस० गिल्वर्टसन लिखते हैं—
“क्या यह नागरिक जीवन की उन्नति के लिये बाधक है?—
हमारे यहाँ इस प्रथा ने जो लाभ पहुँचाए हैं और हमारे शासन और न्याय को उन्नत बनाने में इसने जितनी मदद की है, उसे देखते इस प्रभका उत्तर नहीं’ के सिवाय कुछ नहीं हो सकता।”

१९७९

चुनावनियमावली

१९७९

आवश्यकता

आजकल हमारे देश में चुनावों का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। ब्रिटिश भारत में ही प्रायः ४ करोड़ व्यक्तियों को मत-धिकार मिला है। अब जिला बोर्डों एवं म्यूनिसिपैलिटियों के विधानों में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनसे मतदाताओं की संख्या और भी बढ़ जाने वाली है। देशी राज्यों में भी प्रतिनिधि संस्थाओं के लिए आन्दोलन चल रहे हैं। अनेक राज्यों में स्थानीय शासन संस्थाओं में प्रतिनिध्यात्मक है भी।

इनके अलावा सार्वजनिक प्रतिनिधि संस्थाओं देश के हर भाग में मौजूद हैं, और जहाँ नहीं थीं, वहाँ अब बन रही हैं। इधर जम में कांग्रेस के द्वाधा में शासन सूत्र आए हैं, तब से चुनावों में दिलचस्पी लेने वालों की संख्या दिन दूनी, रात चाँगुनी बढ़ रही है। देहात के किसान, शहरों के मजदूर और मध्यम वर्गीय युवक बहुत बड़ी संख्या में चुनावों में भाग लेने लगे हैं। इस स्थिति को देखकर जो लोग अब तक सार्वजनिक और सरकारी संस्थाओं के ठेकेदार बने हुए थे, उनके आमन डगमगा उठे हैं। वे इस प्रवृत्ति का भिन्न भिन्न उपायों से विरोध करते हैं, उसे चुरा बनाते हैं और भिन्न-भिन्न लथपट्टों से नए आने वाले, मुख्यतः गरीब उम्मेदवारों को असफल कर मनोत्साह करते हैं।

वास्तव में बुरा है क्या ?

इसमें शक नहीं कि इस प्रवाह से बहुत से ऐसे लोग भी लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका आगे आना वाञ्छनीय नहीं है। लेकिन साथ ही ऐसे लोग प्रायः इतने माधन-सम्पन्न और योग्य होते हैं कि वे अच्छे खिलाड़ियों के मुकाबिले में भी, और कई बार खिलाड़ियों को खरीद कर मफ़्त हो ही जाते हैं। अतः हम विरोध की अधिकतर मार पड़ती है, वनही लोगों पर, जिन पर नहीं पड़नी चाहिये।

परन्तु क्या यह प्रवाह वास्तव में बुरा है ? हमारे खयाल से तो यह धारणा सत्य है। जिनके स्वार्थ को घक्का पहुँचना है, वे तो इसे बुरा कहेंगे ही, परन्तु वास्तविक दृष्टि से हमें इसमें कोई घुसाई नहीं दिखाई देती। सच तो यह कि चुनाव पद्धति और चुनाव लड़ना आधुनिक राजनीति का सब में पहला और जरूरी पाठ है। और देशों में तो जनमाधारण की चुनावों में रुचि पैदा करने के लिए मिर तोड़ प्रयत्न किए जाते हैं। क्यों ? इस लिये कि जब तक चुनावों में रुचि न ले, तब तक वह अपने मत का महत्व एवं उसने शासन के सम्बन्ध को समझ ही नहीं सकती। इस दृष्टि से हमारे लिये तो यह अपने यहाँ की जनता को जनतंत्र की शिक्षा देने का स्वर्ण प्राप्त अवसर है।

इसमें शक नहीं कि पहले पहल अरुआड़े में उतरने वालों की तरह हमारे नये मतदाना गलतियाँ करेंगे। पटकें ग्यारेंगे। बार-बार हारेंगे। इससे कुछ नुक़मान भी होगा। कुछ सलत आदमी भी चुन जायेंगे। परन्तु यह जोखिम किम नये परिवर्तन में नहीं होती ? हाँ, वह जगहस्थायी होती है। परन्तु आगे चलकर इसमें

जो अमित लाभ होंगे उनके मुकामिले में यह हानि और अव्य-
वस्था कितनी नगण्य होगी ?

और आरिख ये गलतियाँ भी क्यों होती हैं ? इसीलिए न,
कि हमने जनता को चुनाव सम्बन्धी राजनैतिक ज्ञान नहीं
कराया है। वे न चुनाव के नियमों से परिचित होते हैं न
उम्मेदवारों के हथकण्डों से। अतः अब भी यदि हम अपने इस
कर्तव्य का पालन करें, तो यह गड़बड़ी और भी जल्दी दूर हो
जायगी। अस्तु,

इसी दृष्टि से हम यहाँ अपने देश में प्रचलित चुनाव पद्धतियों
सम्बन्धी त्रास-त्रास नियम और सूचनाएँ दे रहे हैं।



निर्वाचन और निर्वाचक



निर्वाचन के आम तौर पर दो भेद हैं:—

प्रत्यक्ष ।

परोक्ष ।

प्रत्यक्ष—प्रत्यक्ष निर्वाचन उमे कहते हैं, जिसमें प्रत्येक उम्मेदवार को माधारण मतदाता चुनते हैं ।

साधारण मतदाता—विधान के अनुसार कई प्रकार के होते हैं:—

- (१) जहाँ प्रत्येक बालिग व्यक्ति को मनाधिकार होना है, वहाँ प्रत्येक बालिग व्यक्ति माधारण मतदाता है ।
- (२) संस्थाओं में नियमित चन्दा देकर बनने वाले प्राथमिक मदस्य माधारण मतदाता होते हैं ।
- (३) म्युनिमिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि में मतदानाओं की योग्यताएँ निश्चित होती हैं:—

(अ) जैसे इतने समय से उक्त संस्था की हद में रहने वाला ।

(ब) इतना किराया—रहने के मकान का—इतने समय से देने या लेने वाला ।

(स) इतने लगान की जमीन जोतने वाला ।

(द) इतनी स्थावर सम्पत्ति वाला ।

(ए) इतनी शिक्षा पाया हुआ ।

(फ) इतना धैर्य पाने वाला । आदि-आदि

ऐसी जगहों में उपरोक्त योग्यता वाले व्यक्ति ही साधारण मतदाना होते हैं ।

परोक्ष निर्वाचन

परोक्ष निर्वाचन—उसे कहते हैं जिसमें प्रत्येक प्रतिनिधि को साधारण मतदाता नहीं चुनते । साधारण मतदाता स्थानीय सस्थाओं के सदस्यों को चुनते हैं और ये संस्थाएँ उनकी ओर से बड़ी सस्थाओं के लिए प्रतिनिधि चुनती हैं ।

उदाहरण के लिए पहले काम्रेस की प्रत्येक सस्था के लिए प्रतिनिधि प्राथमिक (प्रति वर्ष चन्दा देकर बनने वाले) सदस्यों द्वारा ही चुने जाते थे । परन्तु अब अप्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति जारी की गई है । इसके अनुसार प्राथमिक सदस्य सिर्फ अपनी-अपनी वार्ड या मण्डल-कमेटियों के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं ।

ये चुने हुए प्रतिनिधि फिर शहर और जिले के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं ।

इसी तरह नये मंच विधान के अनुसार न्युनिमिपैलिटी, जिला बोर्ड और प्रान्तिक व असेम्बलियों के प्रतिनिधियों को तो साधारण मतदाता चुनते हैं, परन्तु केन्द्रीय असेम्बली के प्रतिनिधि अब साधारण मतदाताओं द्वारा न चुने जाकर, उनकी ओर से न्युनिमिपैलिटियों, जिला बोर्डों और प्रान्तिक असेम्बलियों आदि द्वारा चुने जायेंगे।

यही परीक्ष निर्वाचन पद्धति है।

निर्वाचक संघ

चुनाव की सुविधा और प्रत्येक समूह व भू-भाग का ठीक ठीक प्रतिनिधित्व होने की दृष्टि से, साधारण मतदाताओं के जो विभाग स्थिर किये जाते हैं, उन्हें निर्वाचक मंच कहते हैं। इसके कई प्रकार हैं। जैसे—

- (१) धार्मिक निर्वाचक संघ।
- (२) जातीय निर्वाचक संघ।
- (३) व्यवसायिक निर्वाचक मंच।
- (४) सम्मिलित निर्वाचक मंच।

(१)

धार्मिक निर्वाचक संघ

यह निर्वाचक मंच किमी विशेष धर्म के अनुयायियों के प्रतिनिधित्व के लिये बनाया जाता है। इसके अनुसार किमी

चुनाव क्षेत्र में जितने मतदाता उस धर्म के अनुयायी होते हैं, वे ही उक्त सभ के प्रतिनिधि के चुनाव में मत देते हैं। जैसे ईसाई निर्वाचक संघ, मुस्लिम निर्वाचक संघ, आदि। ऐसे सभ प्रायः उन धर्मों के अनुयायियों के बनाये जाते हैं, जिन की संख्या उक्त क्षेत्र में कम होती है।

(२)

जातीय निर्वाचक संघ

इन निर्वाचक संघों का आधार धर्म न होकर जाति विशेष होती है। जो जाति, और मतदाताओं से कम संख्या में होती है, उसे भय रहता है कि बहुमत न होने के कारण शायद उसका एक भी प्रतिनिधि न चुना जा सके। इसी लिये उक्त जाति का एक पृथक् संघ बना दिया जाता है। किसी चुनाव-क्षेत्र में उस जाति या जाति-समूह के जितने मतदाता रहते हैं, वे ही उस में मत दे सकते हैं। जैसे हरिजन, एंग्लोइण्डियन, यहूदी, पारसी आदि।

(३)

व्यावसायिक निर्वाचक संघ

इन निर्वाचक संघों का आधार, जाति या धर्म न होकर, पेशा होता है। उदाहरण के लिये सन्धी और फलों का धन्धा करने वाले, कारखानों के मजदूर, छोटे दुकानदार, मिष्ठान, छोटे जमींदार, बड़े जमींदार, रुई के कारखाना के मालिक आदि समान धन्धा करने वाले। उपरोक्त संघों की तरह अमुक अमुक धन्धा करने वालों के अलग अलग संघ होते हैं और

उनके प्रतिनिधियों के चुनाव में उक्त धन्या करने वाले साधारण मतदाता ही मत दे सकते हैं।

सम्मिलित निर्वाचकसंघ



इस में जाति या धर्म का भेद नहीं होता। इसका रूप ग्राम-तौर पर साधारण निर्वाचकसंघ का होता है। चुनाव क्षेत्र के सब मतदाता मिल कर निश्चित संख्यानुसार प्रतिनिधि चुनते हैं।

नोट—जिम क्षेत्र का ग्राम्य या नगर, हिन्दू या मुस्लिम निर्वाचक संघ होता है, वहाँ के निर्वाचक संघ के साथ उसका नाम जोड़ दिया जाता है। जैसे:—“आगरा शहर मुस्लिम निर्वाचक संघ” या “सादाबाद देहाती गैरमुस्लिम निर्वाचक संघ।”

संरक्षित स्थान

चुनाव में एक विशेष पद्धति ‘संरक्षित स्थानों’ की भी है। इस आचार पर कि श्री साधारण मतदानार्थी में मर के दिताहित का समान आदर करने की बुद्धि नहीं है, या कहीं बहुमत में ऐसे स्वार्थी दल का प्रधानत्व हो जाते पर, जो अल्पमत के साथ उदार व्यवहार नहीं करता, इस पद्धति की मांग की जाती है। इसके तीन भेद मुख्य होते हैं:—

- (१) मतदाता तो मिश्रित होते हैं, परन्तु ऐसे धर्म या जाति के लोगों के लिए स्थान निश्चित कर दिये जाते हैं।

मतदाताओं को उन्हीं धर्म या जाति के लोगों में से उतने उम्मेदवार चुनने पड़ते हैं।

- (२) संरक्षित जाति या धर्म के लोगों का अलग निर्वाचक संघ बना दिया जाना है।
- (३) प्रथक निर्वाचक संघ बनाने के साथ-साथ स्थान भी निश्चित कर दिये जाते हैं। यह प्रायः अत्यल्प मत वाला के लिए ही होता है। उदाहरण के लिए एक निर्वाचन-क्षेत्र में २००० मतदाता हों और वहाँ से ५ प्रतिनिधि चुने जाते हों, परन्तु वहाँ पारसी मतदाता १०० ही हों। ऐसी दशा में जरूरी समझकर यह नियम कर दिया जाय कि वे १०० ही एक प्रतिनिधि चुन सकते हैं। अथवा यह कि ५ में से १ प्रतिनिधि पारसी होगा।

वर्तमान निर्वाचक सङ्घ

इस समय भारत में सन् १९३५ के "सुधार विधान" के अनुसार नीचे लिखे "निर्वाचक संघ" हैं:—

- १—साधारण निर्वाचक संघ
- २—सिक्ख " "
- ३—मुस्लिम " "
- ४—ऐंग्लोइंडियन " "
- ५—यूरोपियन " "
- ६—भारतीय ईसाई " "
- ७—व्यापारी उद्योग और रानिज निर्वाचक संघ
- ८—जमींदार निर्वाचक संघ
- ९—चिरव विद्यालय " "
- १०—श्रम (मजदूर) " "

- ११—माघारण स्त्री , =
 १२—स्त्री मिस्त्र " "
 १३—ऐंग्लोइंडियन स्त्री ,, "
 १४—मुस्लिम स्त्री " "
 १५—भारतीय ईसाई स्त्री ,

ध्यान रहे कि भारतीय ईसाइयों और स्त्रियों ने देश में कभी पृथक मतधिकार नहीं मांगा था। फिर भी वह उनके गले मढ़ दिया गया। क्योंकि किसी भी देश को पराधीन रखने के लिए इस विषय का अक्षेपण उनके लिए जरूरी होता है।

चुनाव-नियमावली



मतदाताओं की पहचान—

हर एक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की सूची काफी दिनों पहले एक निश्चित स्थान पर टांग दी जाती है और उनकी सूचना प्रकाशित कर दी जाती है। यह सूची राम अकमरों द्वारा तैयार कराई जाती है। परन्तु आज कल के युग में किसी पर निर्भर रहना गलती है। अकमरों में भी काफी गलतियाँ होती हैं। माथ ही, जिम दल का, जिम मंस्था या चोर्ट में प्राधान्य होता है, वह भी कभी २ अपने दिन की दृष्टि में इन कामों में चालबाजी में काम लेता है। बहुधा विरोधीपक्षों के मतदाताओं के नाम नहीं दर्ज किये जाते या गलत छाप दिये जाते हैं, जिम से न वे उम्मेदवार बनने योग्य रह जाते हैं, न मत देने योग्य। इसी तरह बहुत से ऐसे लोगों के नाम दर्ज हो जाते हैं जो वास्तव में मतदाता की योग्यता नहीं रखते। हमारे देश में ही

कई धार माननीय मदनमोहन मालवीय और ५० प्यारेलाल शर्मा जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम तक सूची में दर्ज होने से रह गए। शर्मा जी तो इसी कारण केन्द्रीय असेम्बली का एक चुनाव ही न लड़ सके।

हमारे यहाँ, क्या म्यूनिसिपैलिटियों के मतदाता, क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के और क्या प्रांतिक एवं केन्द्रीय असेम्बलियों के, इस धारे में अपने कर्तव्य की बहुत उपेक्षा करते हैं। अतः उन्हें सतर्कता से ऐसी पहरेदारों की जाँच करनी चाहिए और उनमें जो गलतियाँ हो वे दुरुस्त करानी चाहिए।

संशोधित निर्वाचक सूची—

इस प्रकार मिली सूचनाओं के आधार पर उक्त सूची का संशोधन किया जाना है और फिर वह संशोधित रूप में प्रकाशित की जाती है। इस सूची में जिनके नाम दर्ज होते हैं, वे ही उम्मेदवार होने या मत देने के अधिकारी होते हैं।

नामजदगी का परचा—

संशोधित मतदाताओं की सूची के साथ नामजदगी के परचे का एक नमूना (भरा हुआ) टांगा जाता है और उसके साथ वे हिदायतें भी टंगी रहनी हैं, जिनके माफिक परचा भरा जाना चाहिए।

कुछ याद रखने योग्य बातें—

- १—म्यूनिसिपल चुनावों में—जिस निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड से जो मतदाता होता है, वही वहाँ में उम्मेदवार हो सकता है। वहीं उसे मत देना पड़ता है। दूसरे वार्ड में

उसका नाम नहीं होना चाहिए। साथ ही जिस वार्ड का जो वोटर है वह उसी वार्ड या मंडल या इल्के से खड़े होने वाले उम्मेदवार को मत दे सकता है।

२—जिला बोर्डों—के चुनाव में एक आदमी ही जिले में दो जगह मतदाता नहीं हो सकता, भले ही सम्पत्ति आदि कारणों से वह दो या अधिक जगह में मतदाता होने योग्य हो।

नामजदगी—

संशोधित सूची टंग जाने के कुछ समय बाद नामजदगी की तारीख मुकर्रर होती है। उस तारीख तक कोई भी मतदाता किसी उम्मेदवार का प्रस्ताव भरकर पेश कर सकता है। इस पर एक मतदाता का समर्थन होना चाहिए। उम्मेदवार की स्वीकृति भी होनी चाहिए।

—इस नामजदगी के 'फार्म' को सावधानी से भरना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि प्रस्तावक व समर्थक उम्मी चुनाव क्षेत्र के मतदाता हों, जिनसे उम्मेदवार खड़ा हो रहा है। साथ ही नाम व उनके हिस्से भी वही हों जो मतदाताओं की सूची में हों। उनमें न कुछ घटाया जाय न बढ़ाया जाय।

—प्रत्येक उम्मेदवार को कमसे कम दो-तीन नामजदगी के फार्म भरने चाहियें, ताकि किसी वजह से एक खारिज हो जाय तो दूसरा सही होने पर काम आ जाय।

—उम्मेदवारों से जमानत भी जमा कराई जाती है। यह नगद होती है और एक नियम तानाद में 'मत' न मिलें, तो जमानत करली जाती है। अतः नामजदगी के साथ ही यह भी जमा करा देनी चाहिए। करना प्रस्ताव-पत्र पर विचार ही नहीं किया जायगा।

—नामजदगी का काम व रुपये जिस अधिकारी को दिये जाय, उसमे उनकी रसीद उसी वक्त ले लेनी चाहिए।

—ध्यान रहे कि एक मतदाता, एक चुनाव क्षेत्र से वतने ही उम्मेदवारों का प्रस्तावक या समर्थक बन सकता है, जितने उम्मेदवार उस क्षेत्र से चुने जाने वाले हों। यदि प्रस्तावक या समर्थक खुद भी उम्मेदवार हों, तो उस सख्या से एक कम तक के प्रस्तावक व समर्थक बन सकते हैं। उदाहरण के लिये यदि एक निर्वाचन क्षेत्र से ५ आदमी चुने जाने हैं, तो उस क्षेत्र का प्रत्येक मतदाता ५ उम्मेदवारों का प्रस्तावक या समर्थक बन सकता है। परन्तु यदि वह खुद भी उम्मेदवार है, तो वह दूसरे चार उम्मेदवारों का ही प्रस्तावक या समर्थक बन सकता है। इससे अधिक का प्रस्तावक या समर्थक बनने पर वे परचे ररारिज हो जायगे, जिनका नियत सख्या से ऊपर उसने प्रस्ताव या समर्थन दिया है।

नामजदगी की जाँच—

नामजदगी के बाद प्रस्ताव पत्रों की जाँच करने की तारीख मुफर्रर की जाती है। इस तारखे तक कोई भी उम्मेदवार अपना नाम वापिस ले सकता है। नाम वापिस ले लेने वाले उम्मेदवार की जमानत लौटा दी जाती है।

—जाँच के दिन प्रत्येक उम्मेदवार को जरूर पहुँचना चाहिए और प्रतिपक्षी उम्मेदवारों के परचों की गलतियाँ और अनियमितताएँ देखनी चाहिए। आम तौर पर नीचे लिखी बातें पर वम किया जा सकता है—

(१) उम्मेदवार, प्रस्तावक और समर्थक के नाम रालन या लिस्ट के अनुसार न होने पर एवं नामा के हिज्जे में फरक होने पर।

- (२) उम्मेदवार, प्रस्तावक और समर्थक की वल्लिदयत (पिता का नाम) जाति या पता गलत होने पर ।
- (३) उम्मेदवार, प्रस्तावक और समर्थक—इनमें से किसी के दूसरे निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होने पर ।
- (४) प्रस्तावक, समर्थक या उम्मेदवार के हस्ताक्षर नकली या जाली होने पर ।
- (५) उम्मेदवार, या प्रस्तावक या समर्थक की आयु गलत होने पर ।
- (६) उम्मेदवार, प्रस्तावक या समर्थक के, जांच शुरू होने के पहले, अपना प्रस्ताव या समर्थन वापिस ले लेने पर ।
- (७) गलत तरीके से परचा भरा होने पर ।
- (८) परचे के साथ अमानत की रसीद न होने पर ।
- (९) परचा निश्चित समय और निश्चित तारीख के बाद दाखिल किया जाने पर ।
- (१०) मतदाता या उम्मेदवार होने के लिए निश्चित योग्यताओं में से कोई न होने पर ।
- (११) उम्मेदवार, प्रस्तावक या समर्थक के नाबालिग, पागल या किसी ऐसे अपराध में मजा पाया हुआ होने पर, जिनके अपराधी मताधिकार से वंचित हों ।

इन में से कोई भी एक बात साबित होने पर नामसदगी खारिज हो जाती है। इसी तरह की आपत्तियां विपक्षी उम्मेदवार कर सकते हैं, उनका उत्तर देने को तयार रहना चाहिये।

—प्रत्येक आपत्ति लिख कर देना चाहिये और उसकी रसीद, जहां तक हो उसकी नकल पर, जांच कुनिन्दा आफिसर से ले लेना चाहिये, ताकि ऑफिसर किसी जायज बात को न माने तो उस की अपील या शिकायत के वक़्त ये चीजें काम आवें।

इस प्रकार जांच होने के बाद जिन उम्मेदवारों के परचे सही ठहरते हैं, वे उम्मेदवार घोषित कर दिये जाते हैं, अर्थात् उनके नाम छपा कर जनता में प्रकाशित कर दिये जाते हैं।

निर्विरोध चुनाव

यदि किसी चुनाव क्षेत्र से उतने ही या उससे कम उम्मेदवारों की नाम सदगी मंजूर हो, जितने कि उससे चुने जाने चाहिये, तो स्वीकृत नामसदगी वाले उम्मेदवार निर्विरोध चुने हुए माने जायेंगे। जांच करने वाला आफिसर उन्हें वहीं चुने हुए घोषित कर देगा। न करे तो सम्बन्धित उम्मेदवारों को तत्काल लिख कर उससे ऐसा घोषित करने की प्रार्थना करनी चाहिये और इस प्रार्थना की रसीद ले लेनी चाहिये। ऐसी दशा में 'मत' डलवाने की नीयत नहीं आती।

वापिसी

- —परचों की जांच हो जाने के बाद "रिटर्निंग आफिसर" एक तारीख (चुनाव के पहले की) निश्चित कर घोषित करता है कि जो उम्मेदवार अपने नाम वापिस लेना चाहें, वे अमुक तारीख तक ले सकते हैं।

जिन्हें अपने नाम वापिस लेने हों, उक्त तारीख तक ही ले लेने चाहिये, ताकि उनके नाम 'वैलट-पेपर-मतदाता पत्र' पर न छापे जायें। ऐसे उम्मेदवारों को ग्रामान्त का रुपया वापिस मिल जाना है।

विशेष स्थिति में

विशेष स्थिति में, या इच्छा होने पर कोई उम्मेदवार, चुनाव के दिन, मत लेना खतम होने के पहले किसी भी समय अपनी उम्मेदवारी वापिस ले सकता है, ऐसा भी कहीं २ नियम होता है।

चुनाव

—*—

यदि ऐसा न होकर उम्मेदवार अधिक होते हैं, तब निश्चित तारीख को चुनाव होता है। अतः चुनाव के लिये प्रत्येक उम्मेदवार को अपने एजेंट हर पोलिंग स्टेशन के लिये निश्चित करने चाहियें। एजेंट ऐसे होने चाहियें, जो चुनाव विधान के जानकार, चतुर और जहां तक हो, मतदानाश्रमों में से प्रमुख लोगों से परिचित हों।

साथ ही चुनाव सम्बन्धी अनियमितताओं पर पूरा ध्यान रखना चाहिये। आमतौर पर ये अनियमितताएँ दस प्रकार होती हैं:—

अनियमित ग्वर्च कराना—

- (१) वोट या मत पाने के लिए, दूसरे उम्मेदवार को मत न देने के लिए या मत डालने का न जाने देने के लिये किसी या किन्हीं मतदाश्रमों को कुछ रिश्वत देना या इसी उद्देश्य से दावत देना, भोजनादि कराना।

- (२) ऐसी जगह माग कर या किराये पर लेकर ~~यहाँ मतदानाओं~~ का ठहराना या बुलाना, जहाँ नशीले पदार्थ मिलते हों।
- (३) प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवार को अपना नाम वापिस लेने बैठ जाने के लिए रिश्वत देना या दबाव डालना, धमकी देना, इनाम देना या किसी तरह का वादा करना।
- (४) दूसरों से अनुचित प्रभाव डलवाना या लालच देना।
- (५) कल्पित नामा से चुनाव के सम्बन्ध में कोई काम करना।
- (६) ऐसे भूठी दूररास्स दिलाना, दाने कराना, भूठे ध्यान प्रकाशिन करना या कराना जिनमें किसी उम्मेदवार को हानि पहुँचे।
- (७) चुनाव के खर्च का हिस्सा भूठा या जाली देना या न देना।
- (८) निर्वाचक यानी मतदानाओं को सगरी खर्च देना।
- (९) किराए की मजारियों को भाड़े पर लेना और उनमें मत दातओं को लाना, या भाड़ा देने का वादा करना।
- (१०) रिना प्रेस के व प्रकाशक के नाम के परचे निकालना।
- (११) अपने कर्जदारा, किमानों या रिश्वतदारों या नीकरों से कर्जमाफ करने, ब्याज कम करने, लगान या किराया छोड़ने या कम करने अथवा वेतन बढ़ाने का वादा इस शर्त पर करना कि वे उसे या अमुक को मत दें।
- (१२) मतदाताओं के लिये पैट्रोल खर्च वगैरा उम्मेदवार या उसके एजेंट करें और मोटर गाड़ी आदि किसी मित्र की माग लें।
- (१३) छपाई का पेशा न करने वालों या अपने रिश्तेदारों या पतिष्ठ मित्रों से छपाई आदि का काम लेना। (यह यद्यपि

स्वतः अपगव नहीं है, परन्तु ऐसी स्थितियों का हिसाब प्रायः मर्त्य मान लिया जाता है ।)

अफसरों की अनियमितताएँ

१—चुनाव अफसरों के किसी काम को योषित-मनः से पहले या पीछे करने पर ।

२—किसी जन्मेदवार से कोई सेंट आदि स्वीकार करने के साथ उसके सम्बन्ध में किसी अनियमितता की अपेक्षा करने पर ।

३—एक ही आधार पर दो तरह के दायने देने पर ।

४—किसी जन्मेदवार या दल के पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट करने या दूसरों को अपना मत किसी को देने या न देने के लिये प्रेरित करने पर ।

५—किसी जन्मेदवार या मतदाता को नियमित सुविधाएँ न देने पर ।

६—गलत निगान लगाने या गलत रिवाजों देने पर ।

७—ऐसी सूचनाएँ प्रकाशित करने पर, जिन में किसी जन्मेदवार के हितों को हानि पहुँचे ।

नोट—यदि चुनाव अफसर जान बूझ कर किसी व्यक्ति या दल का पक्षपात करने वाला मित्र हो जाय, तो उसके तहत में हुआ मारा चुनाव रद्द हो जा सकता है ।

जायज गर्च

जन्मेदवारों के जायज खर्च इस प्रकार भांजे जाते हैं —

(१) जन्मेदवारों, उनके एजेंटों, मत एजेंटों, क्लर्कों और अन्य

कर्मचारियों का सफर खर्च, घेतन और खान-पान आदि का खर्च ।

- (२) चुनाव के सम्बन्ध में अत्रैतनिक कार्यकर्ताओं व मित्रों का खर्च ।
- (३) छपाई, निष्ठापन, डाक, तार, स्टेशनरी, दफ्तर गोलने या सभा आदि करने के लिए किराये पर लिए गए मकान का किराया आदि का खर्च ।

हिसाब की नियमितता

प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव के बाद, निश्चित मियाद के अन्दर अपना हिसाब चुनाव अफसर के पास भेज देना पड़ता है । चुनाव अफसर हिसाब मिलने पर उसकी सूचना सम्बन्धित लोगों को दे देता है । हिसाब पहुँचाने के बाद एक निश्चित मियाद के अन्दर कोई उम्मीदवार चाहे तो अपने विपक्षी के हिसाब की अनियमितताएँ लिखित दूरव्याप्त द्वारा भेज कर गवर्नर से उसका चुनाव रद्द किये जाने की प्रार्थना कर सकता है ।

इसलिए चुनाव का हिसाब बिल्कुल सायायदा, प्रत्येक खर्च से सम्बन्धित व्यक्तियों व काम के ब्यौर तथा प्रत्येक खर्च की रसीदों के साथ रखना चाहिये ।

ध्यान रहे कि गजेटों, सत्र-गजेटों के द्वारा किये गए कामों का भी जिम्मेदार उम्मीदवार ही माना जाता है ।

बिस्वी उम्मीदवार के विरुद्ध गेमी दूरव्याप्त पेश करने वाले को भी शुद्ध खर्च जमानत के तौर पर जमा करानी पड़ती है ।

दूरदवास्त में जिन अनियमितताओं या चुनाव अपराधों के आधार पर किसी का चुनाव रद्द कराना हो, वे सब व्यारे-वार लिखी जानी चाहियें। यदि अपराध करने या कराने वाला व्यक्ति मतदाना है, तो उसका 'रैलनन्वर' दिया जाना चाहिये। कौनसा अपराध किम तारीख का किम जगह हुआ, यह भी उसमें बताना चाहिये।

चुनाव-केंद्र (पोलिंग स्टेशन)

के कुछ नियम



- (१) चुनाव के केंद्र अर्थात् मतदाना या वोट डालने के लिये जो जगह निश्चित की जाती है, वह ऐसी जगह होनी चाहिये, जहां से प्रायः सब मतदाताओं को ममान सी ही दूरी पड़े। अर्थात् निर्वाचन क्षेत्र के मध्य में हो।
- (२) माय ही वह स्थान भार्वजनिक हो। कम से कम किमी उन्मीद्वार का या उनके प्रभावशाली मित्र, रिश्तेदार आदि का न हो।
- (३) चुनाव स्थान के भीतर मिवाय मतदाताओं और एजेंटों या उन्मीद्वारों के और कोई न आवे, ऐसी व्यवस्था हो।
- (४) चुनाव स्थान के भीतर कोई कन्वेमिंग-मतदाताओं को उन्मीद्वार-विशेष को मत देने या न देने को कहना, मममाना आदि वर्जित है।
- (५) मत टालने का "बैलट बक्म" एवम में, अलहदा ऐसी जगह हो, जहां कोई यह न देय मक कि मतदाता किसे मत दे रहे हैं।

- (६) "वैलट वक्स" का निरीक्षक वैलट वक्स से इतनी दूर बैठे कि यह भी, मतदाता ने किस नाम के आगे निशान लगाया है, यह न देख सके।
- (७) निरीक्षक सर्वथा निर्पेक्ष व्यक्ति हो।
- (८) परिचय-पत्र (Identification slips) बनाने वाले व्यक्ति या तो निर्पेक्ष हों या प्रत्येक उम्मीदवार के अलग २ समान संख्या में।
- (९) जिस चुनाव क्षेत्र पर जितने पोलिंग अफसर व प्रेसाइडिंग अफसर हों, वहां प्रत्येक उम्मीदवार अपने उतने ही एजेंट रख सकता है, अधिक नहीं। हा, ये बीच में बदले जा सकते हैं।
- (१०) एजेंटों को मतदाताओं की तसदीक करते समय काफ़ी सतर्क रहना चाहिये। 'मतदाता' वास्तव में वही व्यक्ति है, जिसके नाम का कार्ड है, वह अपनी जानकारी या अपने विश्वस्त आदमियों की जानकारी के आधार पर निश्चय करके तसदीक करनी चाहिये। वरना यदि किसी एजेंट ने ऐसे ज्यादा आदमियों की तसदीक कर दी, जो असली मतदाता नहीं थे, तो यह चुनाव-अपराध बन जायगा।
- (११) परिचय पत्र में नीचे लिखी बातें छपी होना ज़रूरी हैं.—

[अ] चुनाव-क्षेत्र का नाम

[ब] मतदाता का नाम

[स] पिता का नाम

[द] जाति व आयु

[ए] मतदाता का रोल नंबर व हस्ताक्षर या अंगूठे की निशानी ।

[ग] पोलिंग अधिकार के हस्ताक्षर ।

[क] वसती करने वाले के हस्ताक्षर ।

(१२) बिलट पेपर अर्थात् मतदाता-पत्र इस प्रकार का होगा:—

क्रम संख्या	क्रम संख्या
मतदाता का नम्बर	
उम्मेदवारों के नाम	मत का चिन्ह

उम्मेदवारों में से जिसे मतदाता अपना मत देना चाहे, ठीक उनके नाम के सामने वह X यह चिन्ह लगा देगा ।

यदि यह चिन्ह लगाना नहीं जानता, तो प्रेमाइडिंग अधिकार या बिलट-निरीक्षक से मदद ले सकता है ।

दूसरी पद्धति

निशान लगाने की कठिनाई को हल करने के लिये कहीं २ और कहीं २ एक और पद्धति भी काम में लाई जाती है । वह यह कि प्रत्येक उम्मेदवार अपना एक विशेष रंग—लाल, पीला, नीला,

हरा आदि—निश्चित कर लेते हैं या पशु, पक्षी आदि के चिन्ह मुकर्कर कर लेते हैं। फिर उसी रंग या चित्र वाले कार्ड छपा कर प्रेसाइडिंग आफिसर के सुपुर्द कर देते हैं। मतदाता इन में से जिसके चाहे कार्ड ले जाता है और अपनी पसन्द के उम्मीदवार का कार्ड “वैलट वक्स” में डाल आता है।

वहाँ २ इंच पर भी निशान लगाया जाता है।

तीसरी पद्धति

तीसरी रीति रंगीन वक्सों की है। अर्थात् प्रत्येक उम्मीदवार का वैलट वक्स अलग रंग का होता है। मतदाता अपना मत, अपनी पसन्द के उम्मीदवार के वक्स में डाल आता है। इसमें न तो निशान लगाने को भ्रंश रहती है न यह पता लग सकना है कि मतदाता कौन था ? अशिक्षित मतदाताओं के क्षेत्र में यह पद्धति अधिक उपयोगी साबित होती है।

इन सन्दूकों के पास किमी के उपस्थित रहने की, न जरूरत होती है, न नियम है।

इन में से किसी नियम का उल्लंघन किया जाना चुनाव सन्धन्धी अनियमितता है।

कुछ अन्य अनियमितताएँ

- (१) प्रेसाइडिंग आफिसर, पोलिंग आफिसर या अन्य किसी अधिकारी का किसी ओर पक्षपात दिखाना।
- (२) किसी मतदाता से किसी चुनाव अधिकारी का किमी उम्मेदवार को मत देने के लिये कहना।

- (३) किसी उम्मीदवार के एजेंट का किसी मतदाता से अपने उम्मीदवार के पक्ष में मत देने को कहना।
- (४) मतदाता के बजाय किसी दूसरे आदमी का, उम्मीदवार का नाम बोल छटना।
- (५) किसी एजेंट का गलत मतदाता की तसदीक करना।
- (६) ठीक समय पर 'मत' लेना शुरू या बंद न करना या अकारण समय से पहले शुरू या बन्द करना।
- (७) क्रमशः एक उम्मीदवार के इतने और दूसरे के इतने लेने का नियम बनाना।
- (८) उम्मीदवारों और एजेंटों की शिकायतें और आपत्तियां लेने या लेकर रमीद देने से इन्कार करना।
- (९) परिचयपत्र बनाने में किसी उम्मीदवार के मतदाताओं का जान झूठ कर ईरान करना।
- (१०) चुनाव स्थान के बाहर किसी मतदाता को कोई रिश्ता, लालच देना या कुछ उसके लाभ की बात करने का वादा करना।
- (११) मतदाताओं को किसी के पक्ष या विपक्ष में मत देने के लिये धमकी देना या उन पर अनुचित आलेश करना।
- (१२) किसी उम्मीदवार के बारे में झूठी, गलत-फहमी फैलाने वाली बात का प्रचार करना।
- (१३) जाति या धर्म के नाम पर किसी को मत देने या न देने के लिये कहना।

- (१४) किसी मतदाना को गैरहाजिर करने की कोशिश करना, उसे मत न देने को कहना या और किसी प्रकार रोक रक्खना ।
- (१५) मतदाताओं को भोजनादि कराना या भविष्य में दानत आदि देने का वादा करना ।
- (१६) किसी प्रतियोगी उम्मीदवार को अपना नाम वापिस लेने के लिये रिश्वत देना या उसके लाभ का कोई काम करने का वादा करना अथवा किसी जाति के या दल के काम में मदद करने का वादा करना ।
- (१७) अपने समर्थन या दूम्ने प्रतिस्पर्धी का विरोध करने के लिये अपने या दूसरो के नाम से परचे आदि तिरालना ।
- (१८) मतदानाओं को शपथ दिलाना या उनसे शपथ लेना और मतदाताओं का इसी कारण अपनी इच्छा के विरुद्ध मत देना ।

घोषणा पत्र

उम्मीदवार अपनी नीति, अपने सिद्धान्त और चुने जाने पर जो कुछ कार्य अपने मतदाताओं के लिये करेंगे, आदि धाने बनाने के लिये घोषणा-पत्र निकाल मक्ते हैं । दूसरे उम्मीदवारों में अपनी नीति का अंतर भी बता मक्ते हैं, किन्तु शिष्ट भाषा में । इसी प्रकार वे अपने प्रतिद्वन्दियों के आक्षेपों का उत्तर दे मक्ते हैं । सभाओं आदि भी कर मक्ते हैं ।

चुनाव सम्बन्धी कार्य

१—चुनाव अक्सरो को निश्चित समय में आध, घंटा पहले पहुँचना चाहिये ।

२—चुनाव अरुमर के पहुँचते ही उम्मीदवारों को अपने २ एजेंटों की निष्पत्ति की लिखित सूचना चुनाव अरुमर को दे देनी चाहिये।

३—उम्मीदवारों और एजेंटों के मानने चुनाव अरुमर, 'नैलट दक्क', जिनमें नोट दाने जाने हैं, ग्योनकर उन्हें दिखलाएगा कि वह विजुल ग्यामी है। फिर उनके सामने नममें ताला लगा, चाबी उसी के साथ कपडे में मो कर उस पर अपनी मुहर कर देगा।

(नोट—उम्मीदवारों को भी अपना मुहर साथ रखना चाहिये।)

४—उसके बाद बर पोलींग आदिमर निष्पत्ति करेगा और सब को चुनाव के मन्दन में आसन्नक दिखारने देगा।

५—इसी प्रकार जब 'बोर्डिंग' (मवदान) खनम हो चुकेगा, तब सब उम्मीदवारों की मौजूदगी में 'नैलट दक्क' पर कपडा मोकर, उसकी मौबन पर, चुनाव अरुमर, उम्मीदवार और उनके एजेंटों की मुहरें व दम्नखत होंगे। गिटनिंग आदिमर अपने दिन भर के काम की एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिनमें अपने प्रत्येक दैमने और कार्य का कारण दिखलाएगा, तथा जितनी गिफायतें आदि आडे होंगी, वे सब उसके साथ एक मज घूत लिफाफे में रख, उसे दारों में दार एवं उस पर मुहरें कर के 'नैलट दक्क' के साथ रख देगा। ये 'नैलट दक्क' पुतिम के पान, और मुहरें 'गिटनिंग अरुमर' के रग जना दिये जायेंगे और उम्मीदवारों तथा उनके एजेंटों को उनके ग्योनने की तारीख व स्थान की सूचना दी जायगी।

६—निश्चित तारीख पर एजेंटों और उम्मीदवारों की मौजूदगी में 'वैलट वक्स' निकाले जायेंगे और सब को उनकी मुहरें आदि देखने का अवसर दिया जायगा।

७—यदि मुहर टूटी हो या और कोई ऐसा कारण दिखाई दे, जिससे 'वैलट वक्स' खोले जाने आदि का सन्देह हो, तो तत्काल उसकी शिकायत लिख कर 'अफसर' को देनी चाहिये।

८—चुनाव अफसर जांच कर के ऐसी शिकायत पर कैसला देने के बाद ही वक्स खोल सकता है।

९—यदि अफसर के कैसले में उम्मीदवार या उसके एजेंट को सन्तोष न हो, तो वह यह दरखास्त कर सकता है कि वह उपर के अफसर से अपील करने जा रहा है, तब तक "वैलट-वक्स" उसी अवस्था में सुरक्षित रक्खा जाय।

१०—"वैलट वक्स" खोले जाने पर दोनों ओर के उम्मीदवारों और उनके एजेंटों को, 'मत-पत्र' देखने का अवसर दिया जाता है, ताकि कोई मत किसी गलती आदि के कारण खारिज होने योग्य हो तो वे उम्ह लिख कर दे सकें।

११—आमतौर पर, जहां "वैलट पेपर" पर चिन्ह X या + बनाया जाता है, वहाँ चिन्ह नाम के ठीक सामने न होने, उपर या नीचे की 'लाइन' को काट देने, दुहरा या गलत चिन्ह (जैसे ++) लगा देने या बोटर नम्बर या नम्बर मिलमिला न होने से मत खारिज कर दिये जाते हैं। निरान के अलावा कुछ लिख देने से भी 'मत' खारिज हो जाता है।

नोट—यदि निशान लगाने में 'मतदाता' से किसी तरह 'वैलट पेपर' गलत हो जाय या गिराव जाय तो मतदाता से अधिकार है कि उसे 'चुनाव अफसर' को लौटा कर दूसरा 'वैलट पेपर' ले ले। चुनाव अफसर लौटाये हुए वैलट पेपर को खारिज कर देगा और काउण्टर फाउल पर इस बात का नोट लिख देगा।

१२—यदि किसी मत के खारिज किये जाने या न किये जाने के सम्बन्ध में विवाद बना रहे, तो ऐसे मत "मुहर" करके रख दिये जाते हैं।

१३—इसके बाद मत गिने जाते हैं।

१४—यदि किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट की गिनती में कोई सन्देह हो, तो वह उसी समय उन्हें दुबारा गिने जाने की दरखास्त कर सकता है और वे दुबारा गिने जायेंगे।

१५—यदि 'मत' वैलट पेपर पर निशान लगा कर लिखे गये हों और उम्मीदवार या उस के एजेंट से गड़बड़ी का सन्देह हो, तो वह 'काउण्टर फाउल'-वैलट पेपर के उचे हिस्से, जिन पर चोटर नगर घ मिलमिला नगर पड़ा रहता है—गिने जाने की दरखास्त कर सकता है, जिसे अफसर का मजूर करना पड़ता है।

१६—यदि मत-पत्रों और "अवगिष्ट-पत्रा" (काउण्टर-फाउल्स (Counterfoils) की मग्या में अन्तर हो, तो ऐसा चुनाव रद्द हो जायगा।

१७—मत गिने जाने के बाद, मफल उम्मीदवार 'चुने गए' घोषित कर दिये जायगे और मत-पत्र आदि वापिस बक्सों में रख व मुहर करके सुरक्षित रख दिये जायगे।

कुछ आवश्यक सूचनाएँ



१—कोई उम्मीदवार या उसका एजेंट 'प्रेसीडिंग' अफसर (मत लेने वाला अफसर) व रिटर्निंग अफसर (चुनाएँ अफसर) नहीं बन सकता। पोलिंग अफसर भी निर्पेक्ष व्यक्ति ही हो सकते हैं।

२—'मत' गिनने, मत पत्रा को लेने, उनकी जांच करने आदि का काम 'चुनाएँ अफसर' या उसके द्वारा नियुक्त निष्पक्ष व्यक्ति ही कर सकता है। किसी दल विशेष के व्यक्ति या उम्मीदवार के सुपुर्द इन में से कोई काम किया जाना गैर-मान्य है।

३—सरकारी सस्थाओं के चुनाएँ में बैलट बक्स पुलिस के अधिकार में रहते हैं और 'सील' रिटर्निंग आफसर के पास रहती है। परन्तु यदि 'बैलट बक्स' चुनाएँ अफसर के अधिकार (कब्जे) में रहें तो 'सील' (मुहर) दूसरे अफसर के पास रहनी चाहिये, क्योंकि इस नियम का ध्येय "बैलट बक्स" में किसी तरह की गड़बड़ी होने की सम्भावना न रहने देना है। परन्तु यदि मुहर और 'बैलट बक्स' एक ही व्यक्ति के अधिकार में रहें तो आसानी से मुहर तोड़ कर, मत पत्र बदल दिये जा सकते हैं या निकाल लिये जा सकते हैं और फिर मुहर कर दी जा सकती है।

४—‘चुनाव अकसर’ को अपने व्यवहार में सर्वथा निषेध रहना चाहिये। क्योंकि उसके पक्षपाती साबित होने से उसके आधीन हुए सारे चुनाव रद्द हो जा सकते हैं।

५—चुनाव होने की जगह “वैलट वक्सों” की रक्षा का विशेष प्रबन्ध रहना चाहिये। क्योंकि अनेक धार हारने वाले उम्मीदवार दंगा आदि कराकर “वैलट वक्स” ग्रायब करा देते हैं।

६—चाहे कोई उम्मीदवार हारने वाला हो या जीतने वाला, उसे और उसके एजेंटों को प्रत्येक छोटी से छोटी गलती या शरारत पर ध्यान रख कर, ‘पिटोशन’ को सामग्री एकत्र करते रहना चाहिये। प्रत्येक शिकायत लिखित देना चाहिये और उसकी रसीद सम्बंधित अकसर से लेनी चाहिये।

७—चुनाव की जगह पर सब प्रबंध उस संस्था को करना चाहिये, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह जगह हो।

८—मतदाता को चुनाव-स्थल में जिन २ जगहों पर हो कर जाना पड़ता है, उन २ जगहों पर प्रत्येक उम्मीदवार का एक २ एजेंट रहना चाहिये, जिससे एक दूसरे के विरुद्ध मतदाता पर अमर डालने वाली कोई हरकत न हो सके।

९—एजेंटों, उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं का व्यवहार परस्पर भी, और अफसरों में भी शिष्टता पूर्ण होना चाहिये।



कांग्रेस और संघ विधान में प्रचलित
एकाकी

हस्तान्तरित-मत-पद्धति



हम घता चुके हैं कि उक्त पद्धति के भिन्न २ देशों में भिन्न २ रूप हैं। ऐसी वशा से हमारे देश में "कामेस" में भी और "संघ विधान" में भी जो रूप प्रचलित है, वह यहाँ दे देना आवश्यक है।

शब्द विशेष—इस सम्बन्ध में कुछ शब्दों का अर्थ खास तौर पर समझ लेने को जरूरत है। ये शब्द इस प्रकार हैं —

नं० १ CONTINUING CANDIDATE

खड़ा हुआ उम्मीदवार—अर्थात् जो अन्त तक अपना नाम वापिस न ले और धरावर चुनाव लड़ रहा हो।

नं० २ UNEXHAUSTED PAPERS

क्रमित-मत-पत्र—अर्थात् वह वैलट पेपर (मत-पत्र) जिस पर किसी खड़े हुए उम्मीदवार को अपना गौण मत सिलसिले या क्रम से दिया गया हो।

न० ३ EXHAUSTED PAPERS

गौण-मत पत्र—अर्थात् वे मतदान-पत्र या वैलट पेपर जिनमें ~

(अ) किसी खंडे हुए उम्मीदवार का मतदाता ने अपना गौण मत न दिया हो ।

(ग) खंडे हुए या बैठ गये दो या अधिक उम्मीदवारों से कोई सा एक ही गौण मत दिया गया हो । जैसे कोई मतदाना तीन उम्मीदवारों के नाम के सामने दो (२) के अंक बनाये अर्थात् वह तीनों को अपना दूसरा मत देता है ।

(स) चाहे उम्मीदवार खड़ा हो या बैठ गया हो लेकिन जिस उम्मीदवार को मतदाता ने अपना पहला या मुख्य मत दिया हो उसके नाम के नाम से ही वह क्रमशः दूसरा तीसरा मत दे गया हो ।

(द) क्रमवद्ध १, २, ३, ४ करके मत न दिये गये हों, बल्कि असम्यक् रूप से किसी को चौथा किसी को छटा आदि दे दिये गये हों ।

(ए) एक ही उम्मीदवार के सामने एक से अधिक अंक बना दिये गए हों ।

ORIGINAL VOTE OR FIRST PREFERENCE

मुख्य-मत वा पहली पसन्दगी

अर्थात् जिसे, मतदाता मध्य में श्रेष्ठ उम्मीदवार समझ कर उसे अपना पहला मत देता है ।

व्यावहारिक पद्धति

—००—

१—चुनाव के लिये उपर दिये गए नियमों के अनुसार नामजदगी की तारीख निश्चित की जायगी और कांग्रेस चुनावों में 'स्टिनिंग ऑफिसर' को तथा सरकारी चुनावों में असेम्बली-या कौंसिल के सेक्रेटरी को, हाथों हाथ नामजदगी के परचे दिये जायंगे या जवाबी-रजिस्टर्ड-पोस्ट से भेजे जायंगे।

२—यदि परचों की जांच के बाद मालूम होगा कि नामजदगी उतनी नहीं हुई है, जितनी जगहों का चुनाव होना है, तो शेष जगहों की नामजदगी के लिये तारीख मुकर्रर कर के घोषित की जायगी।

३—नामजदगी की जांच के बाद उपर दिये गए नियमों के अनुसार चुनाव होगा।

४—हरेक मतदाता 'वैलट पेपर' में अपनी पसन्द के सब से अच्छे उम्मीदवार के लिये पहला मत दे और उसके आगे नं० १ लिखदे। फिर अपने गाँव मत नं० २, ३ आदि डाल कर जिन्हें देना चाहे, दे।

५—नीचे लिखे कारणों से मत खारिज हो जायंगे।

(१) किसी उम्मीदवार के नाम के सामने कोई चिन्ह लगा देने, हस्ताक्षर कर देने या कोई अक्षर आदि लिख देने से।

(२) जिस मत पर नम्बर १ न लिखा हो।

- (३) एक में अधिक उम्मीदवारों के नाम के आगे मंग्या १ लिख देने से ।
- (४) दूसरी, तीसरी, चौथी आदि मंग्या एक में अधिक उम्मीदवारों के नाम के आगे दुबारा, तिवारा लिख देने से ।
- (५) एक ही उम्मीदवार के आगे १, २, ३ आदि एक से अधिक संख्या लिख देने पर ।
- (६) जिस पर कोई निशान या मंग्या न हो या पढ़ने में न आने योग्य निशान हो ।

६—ऐसे मतदाताओं के गौणमत भी नहीं जोड़े जायेंगे ।

७—परचों की जांच होने के बाद “चुनाव अफ़सर” मतों को ‘गड़ियों’ में बाँटेगा । अर्थात् जिन उम्मीदवारों को पहले या मुख्य-मत मिले हैं, उनकी एक ‘गड़ी’ बनाएगा । शमी प्रकार दूसरे, तीसरे आदि मतों की । फिर हर गड़ी के मतों की संख्या गिनी जायगी ।

८—सुविधा के लिये प्रत्येक ‘मत-पत्र’ का मूल्य १०० मत के समान मान लिया जायगा और फिर उस हिसाब से ममस्त मत-पत्रों की कीमत लगायी जायगी ।

९—इसके बाद चुनाव अफ़सर, जितनी जगहों (मंडलों) का चुनाव होने वाला है, उनकी संख्या में एक अधिक जोड़ कर ‘पर्याप्त संख्या’ निश्चित करेगा । इस संख्या के बराबर या इससे अधिक ‘मत’ जिन उम्मीदवारों से मिले होंगे, वे “चुने गए” घोषित कर दिये जायेंगे ।

नोटः—‘पर्याप्त संख्या’ निश्चित करने के लिये, भाग देने में जो मत अपूर्ण संख्या में शेष बच जायेंगे, वे खारिज समझे जायेंगे ।

१०—यदि किसी उम्मीदवार को ‘पर्याप्त संख्या’ से अधिक ‘मत’ मिले होंगे, तो वे “अतिरिक्त” मत कहलायेंगे और वे क्रम में उन उम्मेदवारों को दे दिये जायेंगे, जिनके सामने मतदाता ने नं० २, ३ आदि लिखा है ।

११—यदि कई उम्मीदवारों के “अतिरिक्त-मत” हों, तो उन में से जिसके सय से अधिक मत हों, वे पहले बाँटे जायेंगे । इन में भी पहले, “मुख्य-मतों” के ‘अतिरिक्त-मत’ बाँटे जायेंगे और फिर “गौण-मतों” के ।

१२—यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के ‘अतिरिक्त-मत’ बराबर बराबर हों, तो उन उम्मीदवारों को मिले “मुख्य-मत” गिने जायेंगे और जिसे सय से कम ‘मुख्य मत’ मिले होंगे, उसके अतिरिक्त-मत पहले बाँटे जायेंगे । परन्तु यदि ‘मुख्य-मत’ भी दोनों या अधिक उम्मीदवारों के बराबर हों, तो “चुनाव-अफसर” घिट्टियाँ डाल कर यह निश्चय करेगा कि किस के “अतिरिक्त-मत” पहले बाँटे जाय ।

१३—यदि किसी उम्मीदवार के “मुख्य मत” पर्याप्त-संख्या से अधिक हैं, तो “चुनाव अफसर” दुबारा उक्त उम्मीदवार के सय परचों की जांच करके, उनमें से ‘अमित-मतों’ की अलग अलग गड्डियाँ बना देगा एवं एक गड्डी “गौण मत-पत्रों” की बना देगा । फिर प्रत्येक “अमित मत-पत्रों” की गड्डी के मूल्य की जांच करेगा ।

१४—इसके बाद यदि ‘मुख्य मतों’ की संख्या या प्रीमत “अतिरिक्त मतों” के बराबर या उन में कुछ कम होगी, तो वह

“अतिरिक्त-मतों” को उम्मीदवार को दे देगा, जिस पर वे अपनी उम्मीदवार को मिले थे।

१५—यदि “मुख्य मतों” का मूल्य “अतिरिक्त मतों” से अधिक होगा, तो ‘चुनाव अफसर’ कुछ “क्रमित मत-पत्रों” की संख्या में “अतिरिक्त-मतों” को भाग देगा। इस भाग का जो फल होगा, वही प्रत्येक ‘अतिरिक्त-मत’ की कीमत मानी जायगी और इसी हिसाब से वे मत दूसरे उम्मीदवार के ग्रांते में बदल दिये जायेंगे।

१६—यदि किसी उम्मीदवार के ‘अतिरिक्त-मत’, उसे मिले हुए ‘मुख्य’ और ‘अतिरिक्त-मतों’—दोनों की वचन में मिले हैं, तो “चुनाव अफसर” उक्त उम्मीदवार के ग्रांते में बदली गई “अतिरिक्त-मतों” की आगिरी गड़ी की फिर से जांच कर उनके ‘क्रमित-मतों’ को दूसरी (यानी उक्त उम्मीदवार के वाद की) पसंदगी के अनुसार बाँट कर उनकी छोटी गड़ियां बना देगा और फिर उनका मूल्य ऊपर दी गई विधि में स्थिर कर उनका बाँटवारा करेगा।

१७—अगर सब अतिरिक्त-मतों के बाँट दिये जाने पर भी इतने मतदाता न चुने जाते हों, जितने उक्त क्षेत्र से चुने जाने चाहिये, तो:—

(अ) जिस उम्मीदवार को सबसे कम मत मिले होंगे, उनका नाम अक्षरिस्त में से निकाल देगा और उनके मत, उसमें अधिक मत पाने वाले दूसरी पसंदगी के उम्मीदवार के ग्रांते में बदल दिये जायेंगे। सब से पहले उनके “मुख्य-मत” और फिर “क्रमित-मत” बदले जायेंगे। उन से भी काम न चलेगा, तब “अतिरिक्त मत” बदले जायेंगे। ‘मुख्य मत’ का मूल्य १०० ही रहेगा। शेष मतों का मूल्य वही होगा, जिस पर विशेष विधि के अनुसार वे अपनी उम्मीदवार को मिले थे।

(घ) ऐसा प्रत्येक विभाजन "स्वतंत्र विभाजन" माना जायगा ।

(स) इसी प्रकार जब तक पूरी सत्या में उम्मीदवार न चुन लिये जाँय, हारे हुए उम्मीदवारों के 'मत' बँटते जायँगे ।

१८—यदि अन्तिम एक उम्मीदवार ही चुना जाना रहा जाता हो और साथ ही लड़े हुए उम्मीदवारों में से किसी के 'मत' अन्य सब उम्मीदवारों को मिले हुए मतों में अधिक हों एवं साथ ही 'अतिरिक्त-मत' भी ऐसे बचे हुए हों, जो किसी के दाते में न बँटले गए हों, तो वे सब मत उसे देकर "चुना हुआ" घोषित कर दिया जायगा ।

बैलट-पेपर का नक़्शा

क्रम सत्या	किसे, कौन सा मत दिया ।	उम्मीदवार का नाम

सूचनाएँ:—

१—प्रत्येक मतदाता एक उम्मीदवार को एक ही मत दे सकता है।

२—जितने उम्मीदवार उस क्षेत्र से चुने जाने हैं, उतने ही मत प्रत्येक मतदाता दे सकता है। जिसे वह सर्व श्रेष्ठ समझे उसके नाम पर (१) लिख दे। उसके न होने पर जिसे पसन्द करे उसके नाम पर (२) लिखे।

३—यदि एक ही संख्या एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम पर लिखी जायगी, तो वह 'मत' रह हो जायगा।

उदाहरण

पाठकों की सहूलियत के लिये हम इस पद्धति का एक उदाहरण दे देते हैं।

मान लीजिये कि इस पद्धति के अनुसार कहीं ७ सदस्य चुने जाने हैं। इन ७ जगहों के लिये १६ उम्मीदवार हैं और ५४ मतदाता हैं।

अब मान लीजिये कि 'मतदान' के बाद नीचे लिखे अनुसार "मुख्य-मत" उम्मीदवारों को मिलते हैं:—

क—२	ट—४
ख—६	ठ—३
ग—३	ड—२
घ—१	ढ—२
च—११	त—२
छ—३	थ—२
ज—५	द—२
झ—२	ध—१

अब प्रत्येक मत की कीमत १०० रखने के नियम के अनुसार कुल ५४०० मत हुए। मत मदस्थ होते हैं। अतः नियमानुसार एक संख्या बढ़ा कर $७ + १ = ८$ से ५४०० को बाँटा, तो ६७५ उत्तर आया। इसमें नियमानुसार १ बढ़ाने से ६७६ पर्याप्त संख्या हुई।

इस हिसाब से 'ख' और 'च' के मत 'पर्याप्त संख्या से अधिक हैं। अतः ये दोनों चुने हुए घोषित कर दिये गए। इनमें से 'ख' के "अतिरिक्त मत" २२४ बचे और 'च' के ४२४।

ये "अतिरिक्त-मत" मुख्य मतों के हैं। अतः 'च' के मत-पत्र 'गौण मतों' के अनुसार अलग अलग गट्टियों में बाँटे गए। मान लीजिये कि परिणाम नीचे लिखे अनुसार आया.—

'अ' के गौण मत	५
'क' " " "	३
'द' " " "	२
<hr/>	
"कमित-मत"	कुल १०
"गौण" "	१
<hr/>	
	११

इन सब का मूल्य ११०० हुआ। इन में "कमित मत-पत्रों" का मूल्य १००० अर्थात् अतिरिक्त-मतों से ज्यादा है। अतः १० 'कमित-मतों' से 'च' के ४२४ अतिरिक्त-मतों को भाग दिया, तो प्रत्येक मत का मूल्य ४२ आया। इस हिसाब से जब उक्त मत बाँटे गए तो दूसरे उम्मीदवारों को इस प्रकार मत मिले:—

'ज'	२१०
'झ'	१२६
'ढ'	८४

कुल ४२०

इसी तरह 'ख' के मत बाँटे गए तो एकमत का मूल्य ६ आया। उसके मत ६ से २२४ को गुणित करने पर इस प्रकार हुए:—

अतिरिक्त 'क्रमित मतों' का मूल्य $२४ \times ६ = २१६$

अपूर्ण संख्या के कारण खारिज ८

इस प्रकार 'ज' के अपने ५ मुख्य मतों के ५०० और गौण मतों से मिले हुए २१० मिलकर पर्याप्त संख्या से अधिक हो गए। अतः उसे 'चुना हुआ' घोषित कर दिया गया। 'ज' के 'अतिरिक्त मत' ३४ वचे। इन्हें दूसरे उम्मीदवार के खाते में बदलना था, अतः उनकी आखिरी गड़ी की जाँच की गई। परिणाम इस प्रकार आया:—

'ज' के 'अतिरिक्त मत'	३४
दूसरी गड़ियों के गौणमत	५
इन गड़ियों के प्रत्येक मत का मूल्य	४२
क्रमित मत-पत्र-	५
" " " का मूल्य	२१०
उपरोक्त ३४ अतिरिक्त मतों का मूल्य	
उपरोक्त नियम से	६

—चँदवारा—

इनमें से ६ की सीमत के ३ मत 'क' को दिये गए और दो मत 'द' को।

अब धूँकि अतिरिक्त मत नहीं बचे, अतः यह देखा गया कि किस उम्मीदवार का नाम खारिज किया जाय। जाँच करने पर मालूम हुआ कि 'घ' और 'ध' को सबसे कम 'मत' मिले हैं। किन्तु दिक्कत यह थी कि दोनों को बराबर मत मिले थे। अतः चुनाव आकसर ने चिट्ठियाँ डालीं और खारिज किये जाने के पक्ष में 'घ' का नाम आया।

इस तरह उसका एक मुख्य मत १०० की सीमा का दूसरी पसन्दगी वाले उम्मीदवार को दे दिया गया। इसी प्रकार फिर 'घ' का नाम खारिज हुआ और उसके मत 'ड' को दिये गये।

इसके बाद 'त' और 'थ' ऐसे रहे, जिन्हें सबसे कम मत मिले थे। अतः उपरोक्त नियम से इनमें से भी 'त' का नाम खारिज किया गया और उसके २०० की सीमा के मत आधे-आधे 'ग' और 'क' को बाँट दिये गए।

फिर इसी प्रकार 'ध' का नाम खारिज हुआ और उसके मत 'छ' और 'ट' में आधे-आधे बाँट दिये गए।

अब 'द' ऐसा रह गया, जिसे सब से कम मत मिले थे। उसे दो मुख्य मत मिले थे और दो गौण, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ६ था। इस तरह 'द' के २१२ मत थे। इसके मतदान ने अपना दूसरा ब तीसरा मत क्रमशः 'क' और 'ग' को दिया था। अतः इन दोनों को 'द' के मुख्यमत के सौ-सौ मिल गए। गौण मत देने वाले दानों ने 'द' के बाद अपने 'ठ' को दिये थे। अतः ये १२ 'ठ' को मिल गए।

अब 'ड' सब से कम मतोंवाला उम्मीदवार रह गया। इसके कुल २८४ मत थे। अतः इसका नाम खारिज कर दिया गया। इसने मुख्य मतों में से सौ सौ 'क' और 'छ' को मिले।

शेष दो मत (जो प्रत्येक ४८ की कीमत के थे) क्रमशः 'ग' और 'द' को मिले।

अब 'ज' के मत सब से कम, अर्थात् ३१२ रहे और इसलिये उसका नाम खारिज कर दिया गया। इसके मतों में से क, ग और ट को क्रमशः मौ-मौ मत मिले। शेष दो, १२ की कीमत के 'झ' को दिये गए। इस प्रकार क, ग, और ट को पर्याप्त संख्या में ऊपर मत मिल जाने के कारण वे चुने हुए घोषित कर दिये गए।

अब सिर्फ एक जगह खाली रही। अतः किमी का नाम खारिज करने के पहले सब के 'अतिरिक्त-मत' जोड़े गए। मानून हुआ कि 'क' और 'ग' के अतिरिक्त मत ६२ काशिल हैं। इनमें से 'क' को मुख्यमत कम मिले थे। अतः पहले उसके मत घटे गए। 'क' की आखिरी गद्दी में १०० मतों के मूल्य के परचे थे और चूंकि इस पत्र पर अलग गौरव-मत 'झ' को दिया गया था, अतः ये सब अतिरिक्त-मत उसे दे दिये गए। इसी तरह 'ग' के अतिरिक्त-मत 'झ' को मिले एवं 'ट' के 'द' को।

अब 'द' के मत सब से कम रह गए, इसलिये उसका नाम खारिज कर दिया गया एवं उसके ३६६ मत 'झ' को दे दिये गए। इस का फल यह हुआ कि 'झ' के मत पर्याप्त संख्या से बढ़ गए। परन्तु चूंकि जितनी जगहें थीं, वे सब चुनी जा चुकीं अतः 'ट' के शेष मत यों ही रह कर दिये गए और 'झ' चुना हुआ घोषित कर दिया गया।

Govt. College Library, Kotah.

Acc. No.	Class No.	Book No.	Author
9544	3242	N9544	आचार्य नरेन्द्र देव
Name of the Book		चुनाव पद्धति का न्यौरा जग-सत्ता	
Borrower's No.	Date of Issue	Borrower's No.	Date of Issue
—		—	
		—	
		—	